



दैनिक जागरण

बोबडे बोले, मुकदमे से पूर्व अनिवार्य मध्यस्थता वाले कानून के लिए यह सही वक्त >>3



सरोकार

वाह उस्ताद नहीं, वाह वोड़ाम बोलिये जनाव

जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम, झारखंड के वोड़ाम प्रखंड का आंधारझोरा गांव वाद्ययंत्रों के लिए विख्यात है। यहां 200 वर्षों से पारंपरिक वाद्ययंत्र बनाए जा रहे हैं। वोड़ाम के ढोल, नगाड़ा, मांदर, मुंदंग, तबला, ताशा और झम की धमक दूर-दूर तक है। (पेज-15)

रविवार विशेष

सोशल मीडिया पर मचा रहे धूम, कमाई भी बूम-बूम

नई दिल्ली : टेक ज्ञान से ब्रेक डॉस और कॉमेडी तक, सोशल मीडिया के सुपर स्टार करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं। यही कारण है कि 18 साल का टिकटोअर युवराज सिंह बॉलीवुड में छा गया है। (पेज-15)

न्यूज गैलरी

राज-नीति > पृष्ठ 3

बुजुर्गों के लिए देश भर में खुलेंगे डे-केयर सेंटर

नई दिल्ली : बुजुर्गों को सरकार अब अकेला नहीं छोड़ेगी, बल्कि उनकी जरूरतों व सुख-सुविधाओं का पूरा ख्याल रखेगी। इसी कड़ी में सरकार ने घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए देश भर में डे-केयर सेंटर खोलने की योजना बनाई है जहां उन्हें नाश्ता, भोजन, समाचार पत्र, खेलकूद जैसी सारी सुविधाएं मिलेंगी।

नेशनल न्यूज > पृष्ठ 6

निवेशक शिखर सम्मेलन के लिए मिले 50 करोड़

श्रीनगर : केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर राज्य में आयोजित होने वाले अपनी तरह के पहले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के प्रचार-प्रसार, आने वाले मेहमानों की आवासीय सुविधा व यात्रा के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपये भी उपलब्ध करा दिए हैं।

विजनेस > पृष्ठ 12

मजबूत स्थिति में है देश की इकोनॉमी : सीतारमण

चेन्नई : सुस्ती की बहस के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमी की वर्तमान स्थिति पर संतोष जताया है। 'जन-जन का बजट' नामक कार्यक्रम में कारोबारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय देश की इकोनॉमी अच्छी स्थिति में है, खासकर वृहत अर्थव्यवस्था के संकेतक अपने सुनहरे दौर में हैं।

स्पोर्ट्स > पृष्ठ 14

रिकॉर्ड पांचवें खिताब पर है युवाओं की नजर

नई दिल्ली : गत चैंपियन भारत पहली बार फाइनल में पहुंचे बांग्लादेश के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के पोचेफ्रस्ट्रूम में रविवार को अंडर-19 विश्व कप फाइनल में रिकॉर्ड पांचवीं बार खिताब जीतने के प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा। इस मैच में टीम इंडिया के यशस्वी जायसकाल, रिपनर रवि बिश्नोई और तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रहेंगी।

विरासत

उग्र के रामपुर में है नवाब मिक्की मियां खानदान का स्ट्रांग रूम, गैस कटर वालों ने खड़े कर दिए हाथ, स्ट्रांग रूम को बनाने के लिए लंदन की छब कंपनी के इंजीनियर बुलाए गए थे

राजा-महाराजाओं के दौर में शाही खजाने को सुरक्षित रखने के लिए किस कदर जतन किए जाते थे, इसका अहसास उग्र के रामपुर स्थित नवाब मिक्की मियां खानदान के स्ट्रांग रूम में करा दिया है। इस स्ट्रांग रूम की बाहरी दीवार में चार गुण सात फीट का दरवाजा है, लेकिन उसकी चाबी गुम हो जाने से इसे खोलने के लिए काटा जा रहा है।

आज के आधुनिक समय में भी तीन दिन के प्रयास के बाद भी स्टील से बने स्ट्रांग रूम की बाहरी दीवार की तीन परत ही काटी जा सकी है। अब लॉकर का दरवाजा दिख तो रहा है, लेकिन उसकी भी चाबी गुम हो जाने से उसे भी काटना पड़ेगा। फिलहाल काटने का काम यह जानने के लिए रोक दिया गया है कि अखिर इसके लिए उचित

बंकर से ज्यादा मजबूत नवाब खानदान का स्ट्रांग रूम

मुस्लेमीन, रामपुर

राजा-महाराजाओं के दौर में शाही खजाने को सुरक्षित रखने के लिए किस कदर जतन किए जाते थे, इसका अहसास उग्र के रामपुर स्थित नवाब मिक्की मियां खानदान के स्ट्रांग रूम में करा दिया है। इस स्ट्रांग रूम की बाहरी दीवार में चार गुण सात फीट का दरवाजा है, लेकिन उसकी चाबी गुम हो जाने से इसे खोलने के लिए काटा जा रहा है।

आज के आधुनिक समय में भी तीन दिन के प्रयास के बाद भी स्टील से बने स्ट्रांग रूम की बाहरी दीवार की तीन परत ही काटी जा सकी है। अब लॉकर का दरवाजा दिख तो रहा है, लेकिन उसकी भी चाबी गुम हो जाने से उसे भी काटना पड़ेगा। फिलहाल काटने का काम यह जानने के लिए रोक दिया गया है कि अखिर इसके लिए उचित



उत्तर प्रदेश के रामपुर में कोठी खास बाग में बने स्ट्रांग रूम का गेट। जागरण

तरीका क्या अपनाया जाए। पांच माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए। नवाब खानदान की कोठी खासबाग का भी सर्वे हो रहा है। इसी कोठी में नवाब खानदान का स्ट्रांग रूम है, जिसमें शाही खजाना रकता है।

स्ट्रांग रूम की बाहरी दीवार की चौड़ाई-ऊंचाई करीब 20 गुणा 20 फीट है। नवाब खानदान की बहु नूरबानो ने बताया कि 1930 में उनके ससुर नवाब रजा अली खां के पिता नवाब हमिद अली खां ने कोठी खासबाग का निर्माण कराया था, तभी स्ट्रांग रूम बना था। उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम को बनाने के लिए लंदन की चब कंपनी के इंजीनियर रामपुर आए थे। इसमें जर्मनी की उस स्टील का इस्तेमाल किया गया, जिससे फौज के टैंक बनाए जाते हैं।

नूरबानो का दावा है कि स्ट्रांग रूम पर यदि बम बरसाए जाएं, तब भी इस पर असर नहीं होगा। इस दीवार में 16-16 एमएम धातु की तीन परत हैं। इसमें ही चार गुण सात फीट का एक दरवाजा है। काटने के दौरान मिले मिश्रण एवं लोहे के महीन टुकड़ों को जांच के लिए गुरग्राम भेजा है ताकि पता चल सके कि इसमें कौन-कौन सी धातु मिली है।

ये हैं खासियत

रामपुर में खासबाग 12 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, इसी में कोठी खासबाग बनी है।

आलीशान कोठी को इस तरह बनाया गया कि शीघ्र गर्मी में भी पूरी तरह ठंडी रहे, आसपास तापमान भी पांच डिग्री कम रहता है।

कोठी में दाईं सौ कमरे और सिनेमा हॉल सहित कई बड़े हॉल हैं।

कोसी नदी किनारे बनी इस कोठी के चारों ओर बाग हैं, जिसमें एक लाख से ज्यादा पेड़ लगे हैं।

कोठी पूरीपूरि इस्लामी शैली में बनी है। यहां के बड़े बड़े हाल बर्माटीक और बेल्जियम ग्लास के झूमरों से सजाए गए हैं।

एक्जिट पोल में फिर केजरीवाल सरकार

अनुमान > दिल्ली में आप की प्रचंड बहुमत से वापसी की संभावना, भाजपा की सीटें बढ़ने की उम्मीद, लेकिन सत्ता से बहुत दूर

पिछले चुनाव जैसी रह सकती है कांग्रेस की स्थिति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही मंगलवार को आएंगे, मगर तमाम एक्जिट पोल के अनुमानों से साफ है कि आम आदमी पार्टी (आप) लगभग प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में धमाकेदार वापसी कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पक्ष में साफ दिख रही लहर पर सवार आप सुबे में 50-60 से भी अधिक सीटें हासिल कर सकती है। एक्जिट पोल के अनुसार जनता केजरीवाल के काम और चुनावी वादों पर पूरी तरह मुहर लगाती दिख रही है। वहीं, शाहीन बाग के जबरदस्त विरोध के इर्द-गिर्द एक्जिट पोल में धरशाही के अनुसर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में करीब 56 फीसद वोटों के साथ 59-68 सीटें मिलने का अनुमान है। जबकि भाजपा चुनावी अभियान एक्जिट पोल में धरशाही होता दिखाई दे रहा है। जबकि केजरीवाल की इस आंधी में कांग्रेस की जमीन दिल्ली में पूरी तरह लुटने के करीब पहुंच गई है।



जिसके सिर पर माता-पिता का आशीर्वाद होता हो उसके साथ ईश्वर स्वयं होते हैं। आज वोट डालने से पहले माता-पिता का आशीर्वाद लिया और फिर उनके साथ वोट डालने गया। भरे बेटे ने पहली बार अपना वोट डाला। अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली

ये सभी एक्जिट पोल फेल होंगे। मेरा यह ट्वीट संभाल कर रखिएगा। दिल्ली में भाजपा 48 सीटें लेकर सरकार बनाएगी। कृपया ईवीएम को दोष देने का अभी से बहाना न ढूँढें। मनोज तिवारी, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष

लगाया गया है और इसके अनुसार आप को कम से कम 49 से लेकर अधिकतम 63 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। भाजपा को 5 से 19 सीटें मिलने की उम्मीद है तो कांग्रेस को इसमें शून्य से चार सीटों के बीच अटकता हुआ आंका गया है। टाइम्स नाउ-इम्प्रेस के एक्जिट पोल में आप को 47 सीटों के साथ सत्ता मिलते हुए दिखाया गया है तो भाजपा को इसमें सबसे अधिक 23 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है।



मध्यम वर्ग और महिलाओं का भी मिलता दिखा जबरदस्त समर्थन

मध्यम वर्ग और महिलाओं का भी मिलता दिखा जबरदस्त समर्थन

एक्जिट पोल (सीटें 70)	आप	भाजपा+	कांग्रेस+
एबीपी-सीवोटर	49-63	5-19	0-4
सुदर्शन न्यूज	41-45	24-28	1-2
टाइम्स नाउ-इम्प्रेस	47	23	0
टीवी 9 भारतवर्ष-सिसरो	54	15	1
रिपब्लिक टीवी-जन की बात	48-61	9-21	0-1
इंडिया न्यूज-एनइटीए	53-57	11-17	0-2
न्यूज एक्स-पोलस्टार्ट	50-56	10-14	00
आज तक-एक्सप्रेस माय इंडिया	59-68	2-11	0
इलेक्शन चरका	48	19	3

मतदान में सुस्त पड़ी दिल्ली, 61.67 फीसद पड़े वोट

नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों के लिए शनिवार को 61.67 फीसद मतदान हुआ। मतदान का यह आंकड़ा दिल्ली में वर्ष 2008 के बाद हुए सभी विधानसभा चुनावों के मुकाबले न्यूनतम है। मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़े पैमाने पर मतदान हुआ, जबकि पॉश कॉलोनियों में मतदान का फीसद अत्यंत कम रहा। (पेज-2)

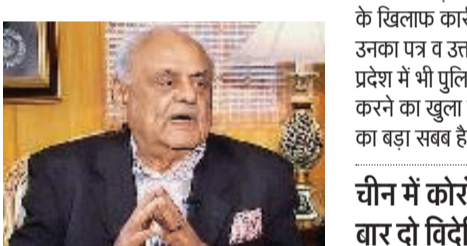
करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान का नया पैतरा

इस्लामाबाद, एजेंसियां : करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान ने नया पैतरा चला है। पाकिस्तान के गृह मंत्री इजाज शाह ने कहा है कि उनका देश गुरुद्वारा दरबार साहिब के लिए भारतीय श्रद्धालुओं को बिना पासपोर्ट के करतारपुर गलियारे में प्रवेश देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद और अधिक आगंतुकों को आकर्षित करना है।

पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान और भारत ने अपनी-अपनी सीमा के अंदर इस गलियारे का अलग-अलग उद्घाटन किया था। भारतीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो पाकिस्तान में वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गलियारे का उद्घाटन किया था। यह गलियारा भारतीय सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान में नारोवाल के करतारपुर में पवित्र गुरुद्वारा दरबार साहिब पहुंचने के लिए सबसे छोटा मार्ग उपलब्ध कराता है।

करतारपुर साहिब में गुरुनानक देव ने अपने जीवन के अखिरी 18 साल गुजारे थे। उन्होंने 1504 में रावी नदी के तट पर करतारपुर में सबसे पहले सिख समुदाय को बसाया था। शाह ने नेशनल एसेंबली

भारतीयों को पासपोर्ट मुक्त प्रवेश पर कर रहा विचार, इसका मकसद अधिक आगंतुकों को आकर्षित करना है



पाकिस्तान के गृह मंत्री एजाज अहमद शाह की फाइल फोटो। दिवदर से

में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि फिलहाल भारत से हुए समझौते के तहत भारतीय श्रद्धालुओं को बिना पासपोर्ट के करतारपुर गलियारे में जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन, और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें बिना पासपोर्ट के आने देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस समय यह है नियम

मध्य प्रदेश के थपड़ कांड में जा सकती है डीजीपी की कुर्सी

भोपाल : मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कलेक्टर थपड़ कांड से पेदा हुए आइएएस-आइपीएस विवाद की आंच प्रदेश के पुलिस मुख्या (डीजीपी) वीके सिंह तक पहुंच गई है। राज्य सरकार ने उन्हें हटाने की जमीन तैयार कर ली है। सिंह पर आरोपों की फेहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन थपड़ कांड में कलेक्टर निधि निवेदिता के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह विभाग को उनका पत्र व उत्तर प्रदेश की तरफ पर मध्य प्रदेश में भी पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का खुला समर्थन सरकार से तय कर का बड़ा सबब है। (पेज-4)

चीन में कोरोना वायरस से पहली बार दो विदेशियों की मौत

बीजिंग, एजेंसियां : महामारी का रूप लेते जा रहे कोरोना वायरस से चीन के तुहान शहर में पहली बार दो विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। इनमें अमेरिका की एक महिला और जापान का एक पुरुष शामिल है। इनको मिलाकर शनिवार तक चीन में मरने वालों की संख्या 723 हो गई है, जबकि 34,598 लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं। यह आंकड़ा 200-03 में सार्स नामक बीमारी से हुई 774 लोगों की मौत के करीब पहुंचते जा रहा है। चीन की सरकार इससे निपटने की तमाम कोशिश कर रही है। (पेज-13)

भारत-श्रीलंका दोस्ती की मजबूती पर मोदी और राजपक्षे ने लगाई मुहर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत-श्रीलंका के दोस्ताना रिश्तों को गति देने की प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की नई सरकार से वहां के तमिल अल्पसंख्यकों की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की पुरजोर वकालत की। श्रीलंका के पीएम महिदा राजपक्षे के साथ द्विपक्षीय बातचीत में मोदी ने श्रीलंकाई संविधान के अनुरूप तमिलों के अधिकारों को लेकर बेबाक रुख अपनाया। वहीं दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण रिश्तों को सुलझाने में मानवीय नजरिये को तबज्जो देने पर हामी भरी।

श्रीलंका में हुए चुनाव में राष्ट्रपति चुने गए गोतबाया राजपक्षे के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री बने महिदा राजपक्षे अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आए हैं। मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं के बीच दिखी गरमाहट से साफ है कि राजपक्षे नई पारी में चीन की तरफ एकतरफा झुकाव की पुरानी राह पर नहीं चलेंगे। इसीलिए अपने छोटे भाई गोतबाया

मोदी ने तमिल अल्पसंख्यकों की सत्ता में भागीदारी तय करने की वकालत की

नई पारी में चीन की तरफ एकतरफा झुकाव की राह पर नहीं चलेंगे राजपक्षे

के पहले विदेश दौर के लिए भारत को चुनने के बाद महिदा ने भी मोदी से मुलाकात की पहली वरीयता दी है। इनके राष्ट्रपति रहते चीन का श्रीलंका पर प्रभाव बढ़ गया था, जिससे भारत के साथ उसके रिश्तों में काफी खिंचाव आ गया था। लेकिन, मैत्रिपाल सिरिसेन की सरकार ने भारत से निकटता रखकर चीन से रणनीतिक दूरी बनाए रखी। अब राजपक्षे ने भी भारत से दोस्ती और चीन के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने का संदेश दिया।

मोदी ने वार्ता के दौरान पुराने दौर से आगे निकलकर भारत-श्रीलंका के मैत्रीपूर्ण रिश्तों को आम लोगों के स्तर पर बढ़ाने पर खास जोर दिया। मोदी ने बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि श्रीलंका में शांति बहाली से संबंधित मुद्दों पर हमने खुले मन से बातचीत की। हमें विश्वास है

कि श्रीलंका सरकार एकीकृत श्रीलंका के भीतर समानता, न्याय, शांति और सम्मान के लिए तमिल लोगों की अपेक्षाओं को साकार करेगी। मोदी ने साफ कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन को लागू करने के साथ-साथ सुलह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका अनादि काल से पड़ोसी ही नहीं घनिष्ठ मित्र भी हैं। चाहे सुरक्षा हो या अर्थव्यवस्था या सामाजिक प्रगति, हर क्षेत्र में हमारा अतीत और भविष्य एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। मोदी ने कहा कि श्रीलंका में स्थायित्व, सुरक्षा और समृद्धि भारत के हित में भी है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भी शांति और खुशहाली के लिए हमारा घनिष्ठ सहयोग बहुमूल्य है। हमारी सरकार की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति और सागर डॉक्ट्रिन के अनुरूप हम श्रीलंका के साथ संबंधों को प्राथमिकता देते हैं।

आतंकवाद की समस्या पर भी हुई बातचीत

Presenting

THE NEW AVATAR OF DHYEYA IAS AT NEW LOCATION IN GREATER NOIDA

GREATER NOIDA

IAS PRE CRASH COURSE (WEEKEND)

GS (WEEKEND) BATCH

15TH FEB

MUKHERJEE NAGAR

सामान्य अध्ययन हिन्दी माध्यम

10TH FEB | 11:30 AM

चैकल्पिक विषय

भूगोल

द्वारा संजीव शर्मा

10TH FEB | 11:30 AM

COMPREHENSIVE ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES (CAIPTS) TARGET 2020

"Examine Yourself Before Examination"

Total 17 Tests | 12 GS Tests + 5 CSAT Tests

FREE GS MODEL TEST FOR ALL

16TH FEBRUARY 2020

GREATER NOIDA

4TH FLOOR, VEERA TOWER, ALPHA-1, COMERCIAL BELT, GREATER NOIDA, UP-201310

9205336037, 38 | 0120 4254088

MUKHERJEE NAGAR

A 12, 13 2ND FLOOR, ANSAL BUILDING, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009

011 49274400 | 9205274741

FOR DETAILS VISIT US ON: WWW.DHYEYAIAS.COM OR CALL ON 011 49274400

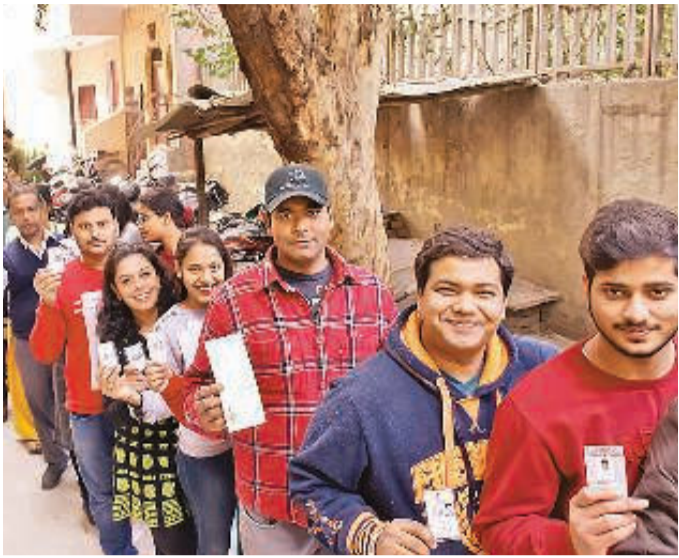
मतदान में सुस्त पड़ी राजधानी, 61.67 फीसद पड़े वोट

लोकतंत्र का पर्व ▶ मुस्लिम बहुल इलाकों, अनधिकृत कॉलोनियों, झुग्गियों व ग्रामीण इलाकों में हुआ अधिक मतदान, पॉश कॉलोनियों में वोट फीसद अत्यंत कम रहा

वर्ष 2008 के बाद से किसी भी विधानसभा चुनाव में दिल्ली के मतदाता नहीं रहे इतने उदासीन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों के लिए 61.67 फीसद मतदान हुआ। मतदान का यह आंकड़ा दिल्ली में 2008 के बाद हुए सभी विधानसभा चुनावों के मुकाबले न्यूनतम है। मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़े पैमाने पर मतदान हुआ, जबकि पॉश कॉलोनियों में मतदान का फीसद अत्यंत कम रहा। उत्तर-पूर्व जिले में सर्वाधिक 65.24 फीसद, जबकि दक्षिण-पूर्व दिल्ली जिले में सबसे कम 54.89 फीसद मतदान हुआ। इसी के साथ ही कुल 672 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। अब सभी की नजर 11 फरवरी को अपने वाले नतीजों पर है। मतदान के दौरान हिंसा की एक-दो घटनाएं और ईवीएम खराब होने के कुछ मामले अवश्य सामने आए, लेकिन आमतौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा।



करोल बाग के कृष्णा गली स्थित मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लगी कतार। पारस कुमार

से मुस्तफाबाद में सर्वाधिक 70.55 फीसद, मटियामहल में 68.36 फीसद, जबकि सीमापुरी में 68.08 फीसद मतदान हुआ। दिल्ली में पहली बार 12 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता पर्वी प्रकाशित क्यूआर कोड को स्कैन कर मतदान कराया गया। ये व्यवस्था विधानसभा क्षेत्र सुल्तानपुर माजरा, सीलामपुर, छतरपुर, बल्लोमारा, बिजवासन, त्रिलोकपुरी, राजौरी गार्डन, शकूरबस्ती, नई दिल्ली, रोहास नगर व जंगपुरा के सभी मतदान केंद्रों के साथ ही दिल्ली कैंट के आठ मतदान केंद्रों पर भी लागू की गई थी। इसके कारण कई केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया धीमी रही और कुछ जगहों पर मतदाताओं को परेशानी हुई।

दिल्ली की सबसे बुजुर्ग महिला ने दिया वोट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : ग्रेटर कैलाश विधानसभा के चितरंजन पार्क में दिल्ली की सबसे बुजुर्ग मतदाता 111 वर्षीय कलितारा मंडल ने शनिवार को मतदान किया। उनका जन्म वर्ष 1908 में हुआ था। मतदान के बाद कलितारा ने कहा कि वोटर आईडी बनाने के बाद मैं सभी चुनावों में मतदान किया है। वोट देते वक्त मैं खुशी महसूस करती हूँ। मतदान मुझे मेरी शक्तियाँ बताता है इसलिए सभी लोगों को मतदान करना चाहिए। वहीं, ग्रेटर कैलाश-2 में 92 वर्षीय अमृतलाल खन्ना ने कहा कि मुझे बुजुर्ग पर मतदान का प्रभाव धीमी रही और कुछ जगहों पर मतदाताओं को परेशानी हुई।



कलितारा मंडल ने भी किया मतदान। जागरण

चिराग दिल्ली में 87 साल की सत्ते देवी ने निगम स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र में सुबह से सबसे पहले वोट डाला। वह व्हीलचेयर पर आई थीं। उनके साथ पति भवान, पुत्र योगेंद्र व पर की सदस्य सावित्री व पौत्र देवाशीष ने भी वोट डाला। देवाशीष ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करते हैं। वोट डालने के लिए वह विशेष रूप से दिल्ली आए थे। उधर, ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के सीआर पार्क में किरनमयी दास (90), एससी पॉल (88) व रेखा दास (73) अपने परिवार के सदस्यों के साथ वोट डालने पहुंचे।

चुनावी दंगल में दिखे लोकतंत्र के खूबसूरत रंग

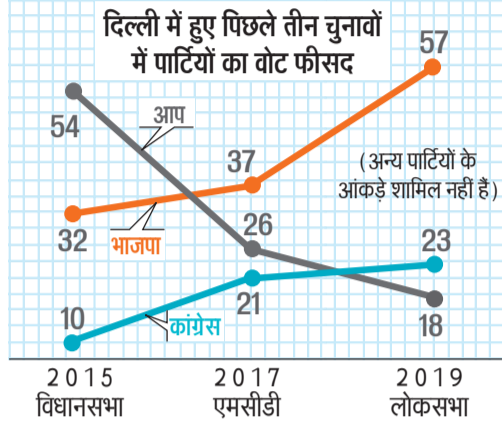
संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली

चुनाव प्रचार अभियान की तरह मतदान के दिन भी राजधानी की फिजा हर पल बदलती रही। नेताओं के बीच जहाँ जुबानी जंग होती रही, वहीं कार्यक्रमों दिनभर पसीना बहाते रहे। आरोप-प्रत्यारोप, नोकझोंक, हल्की झड़प और नाराजगी के साथ ही उत्साह व उत्तेजा के बीच मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम का बटन दबाकर दे दिया है। अब सभी को 11 फरवरी का इंतजार है, जब ईवीएम में बंद सूरमाओं के भविष्य खुलेंगे।

कार्यकर्ता जहाँ अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए जी-टोड़ कोशिश करते दिखे तो मतदाताओं ने भी लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया। रिटाला सहित कई स्थानों पर कार्यकर्ता आपस में भिड़ते रहे तो कहीं एक-दूसरे पर तंज कसते दिखे। इसके विपरीत कई मतदान केंद्रों से कुछ दूरी पर अलग-अलग पार्टियों के टेबल के पास टोपी लगाकर खड़े कार्यकर्ता हंसी-मजाक कर रहे थे। कड़वाहट भरे चुनाव प्रचार अभियान के बाद कार्यकर्ताओं का यह मिजाज संदेश दे रहा था कि यह लोकतंत्र का पर्व है और इसमें कटुता का कोई स्थान नहीं है। इस हंसी मजाक के बीच मतदाताओं को अपने टेबल पर बुलाने और हाथ जोड़कर अपने प्रत्याशी के समर्थन की मूक अपील करने को लेकर भी वह सजग थे। कई मतदान केंद्रों पर क्यूआर कोड वाली वोटर पर्वी दी जा रही थी। जिनके पास यह पर्वी नहीं थी, उन्हें मतदान करने में दिक्कत आई और कई वंचित रह गए, जिससे उनमें नाराजगी थी। त्रिलोकपुरी में साहिल परिवार के साथ वोट देने आए थे, लेकिन उन्हें वापस लौटा दिया गया। इसी तरह से मोबाइल लेकर वोट देने पहुंचे मतदाता भी सुरक्षा कर्मियों से उलझते दिखे। द्वारका में विजय का कहना था कि चुनाव आयोग को मोबाइल रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी तरह से कई स्थानों पर लोगों को वाहन खड़ा करने में परेशानी हुई। इन सबके बीच आदर्श मतदान केंद्र, पिक बूथ पर पहुंचे मतदाताओं को वीआइपी होने का एहसास हो रहा था।

फूलों से हुआ स्वागत, मोबाइल रखने को मिला लॉकर : प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए एक-एक आदर्श मतदान केंद्र पर लोगों को काफी बेहतर सुविधाएं मिलीं। स्वागत के लिए गुब्बारे और फूलों

विस और लोस में मतदाताओं की पसंद अलग-अलग					
विस चुनाव 2015	विस 2013	लोस 2019	लोस 2014		
वोट पड़े 67.47%	66.02%	60.60%	65.10%		
पार्टी	सीटें	वोट%	सीटें	वोट%	सीटें
आप	67	54.3	28	29.5	0 33 0 33
भाजपा	3	32.2	31	34.1	7 46.6 7 46.6
कांग्रेस	0	9.7	8	24.5	0 15.2 0 15.2
अन्य	0	3.8	3	11.9	- - - -



से सजे हुए गेट बनाए गए थे। जिस रंग के गुब्बारे गेट पर लगाए गए थे, उसी रंग का पंडाल और टेंट भी लगाया गया। इन केंद्रों पर मोबाइल रखने के लिए लॉकर की सुविधा देने के साथ ही लाइन में लगकर इंतजार करने के बजाय बैटने के लिए सोफे लगाए गए थे। क्रेच की व्यवस्था भी की गई थी, जिससे जब तक महिलाओं ने मतदान किया, बच्चे क्रेच में खेलते रहे।

कतार में लग डाला वोट, शाम को धरने पर पहुंचे

अरविंद कुमार द्विवेदी, नई दिल्ली

करीब दो माह से पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) व एनआरसी के विरोध में आंदोलन का केंद्र बने शाहीन बाग के लोगों ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव में जमकर मतदान किया। शाहीन बाग पर देश-दुनिया की नजर रही। हर कोई यहां के मतदाताओं का रुख देखना चाहता था। मतदान केंद्रों के बाहर वोटरों की लंबी कतारें लगी थीं। ओखला विधानसभा क्षेत्र के शाहीन बाग, जामिया नगर, बटला हाउस, ओखला गांव, अबुल फजल एंक्लेव, जाकिर नगर, नूर नगर, जोगाबाई, जोगाबाई एक्सप्रेसटेशन, गफफार मंजिल आदि के मतदान केंद्रों पर भीड़ के कारण पैर रखने की जगह नहीं थी। तैमूर नगर गांव व खिजराबाद गांव में भी वोटरों ने जमकर मतदान किया। इसके बाद शाम को शाहीन बाग के धरनास्थल पर लोग पहुंचे और पहले की तरह विरोध-प्रदर्शन किया।



विधानसभा चुनाव में शाहीन बाग प्रचार का मुख्य केंद्र बिंदु बना रहा। शनिवार को यहां के अबुल फजल एंक्लेव स्थित एसडीएमसी स्कूल में मतदान के लिए बने बूथों पर लंबी-लंबी कतारें लगी रही। विपिन शर्मा

स्थानीय लोगों का कहना है कि दिल्ली के किसी भी चुनाव में उन्होंने इतनी जबरदस्त वोटिंग पहले कभी नहीं देखी थी। बारी-बारी वोट डालने आए लोग : जामिया नगर व शाहीन बाग में सुबह पुरुष मतदाता बड़ी संख्या में वोट देने पहुंचे। दोपहर होते-होते महिलाओं की संख्या भी बढ़ने लगी। शाहीन बाग पब्लिक स्कूल, शाहीन बाग टोकर नंबर-8, ओखला स्कूल, एसडीएमसी नेताओं को लग रहा है कि मतदान में गिरावट की वजह मध्यम वर्ग की उदासीनता है और इसका सीधा नुकसान उसे होगा। पार्टी के शीर्ष नेता मतदान फीसद को लेकर चिंतित थे। उनकी चिंता का कारण कुछ माह पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव के अनुभव को लेकर था।

हरियाणा में मतदान फीसद में गिरावट से भाजपा को नुकसान हुआ था। भाजपा के शीर्ष नेताओं को लग रहा था कि कहीं दिल्ली में भी मतदान फीसद कम न हो जाए, इसलिए वे मतदाताओं को घर से बूथ तक पहुंचाने को बड़ी चुनौती मान रहे थे। इससे पहले वे कई दिनों से बूथ प्रबंधन को मजबूत करने में लगे हुए थे। बूथ कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए काम करने का निर्देश दिया गया था। सांसदों को उनके काम की निगरानी करने की हिदायत दी गई थी। बावजूद इसके पिछले भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी के कई नेताओं को लग रहा है कि मतदान में गिरावट की वजह मध्यम वर्ग की उदासीनता है और इसका सीधा नुकसान उसे होगा। पार्टी के शीर्ष नेता मतदान फीसद को लेकर चिंतित थे। उनकी चिंता का कारण कुछ माह पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव के अनुभव को लेकर था।

होते-होते महिलाएं भी वोट देने के लिए पहुंचने लगीं तो ये कतारें और बढ़ती गईं। दरअसल, सुबह पुरुषों की भीड़ ज्यादा थी इसलिए महिलाओं ने इंतजार किया, पर भीड़ कम न होते देख वह भी कतार में लग गईं। चलने तक नहीं थी जगह : बटला हाउस की गलियों में चलने की जगह नहीं मिल पा रही थी। पुलिस को अनारुसमेंट कराना पड़ा कि जो लोग वोट डाल चुके हैं, वे अपने बालिका स्कूल आदि पर सुबह करीब आधा किमी लंबी लाइन लग गईं। वहीं, दोपहर

मुंबई वाली के जवाब में तापसी बोलीं, 'मैं दिल्ली वाली ही हूँ'

सुशील गंभीर, नई दिल्ली : अभिनेत्री तापसी पन्नू ने मुंबई से आकर रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में परिवार के साथ मतदान किया। इसके बाद उन्होंने फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया और दूसरों को भी वोट डालने के लिए जागरूक किया। तापसी के ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा कि मुंबई वाले क्यों तय करेंगे कि दिल्ली में किसकी सरकार बने। इस पर तापसी ने करारा जवाब दिया कि मेरी नागरिकता पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। मेरी आर का टैक्स दिल्ली को जाता है और मैं दिल्ली वाली ही हूँ।

तापसी ने सोशल मीडिया पर पिता, मां और बहन के साथ वोट डालने के बाद फोटो शेयर की थी। तापसी ने लिखा मुंबई से खासतौर पर वोट डालने के लिए आई हूँ। यहाँ पर पर किसी को आने का अंदाजा भी नहीं था। पन्नू परिवार ने वोट डाल दिया, आप भी वोट जरूर दें क्योंकि हर वोट जरूरी है। इस पर एक यूजर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुंबई में रहने वाले लोग हमारे लिए सरकार क्यों तय कर रहे हैं। काफी समय हो गया है तापसी को मुंबई में रहते हुए और उन्हें अपना वोट भी शिफ्ट करवाना चाहिए। इस पर तापसी करारा जवाब दिया।



बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू (दाएं से दूसरी) ने अपने परिवार के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अंगुली पर लगी स्याही दिखाती हुई। प्रे

केजरीवाल ने देर शाम बुलाई बैठक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की सुरक्षा को लेकर अपने आवास पर एक बैठक बुलाई। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय, वरिष्ठ नेता संजय सिंह एवं पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर मौजूद थे। इस दौरान स्ट्रॉंग रूम में जमा ईवीएम की सुरक्षा को ज्यादा पुख्ता करने के उपायों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई।

बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक केजरीवाल के साथ अपने विचार साझा किए और उन्हें कुछ सुझाव भी दिए। इस दौरान एंक्टिवेटेड पोल को लेकर भी चर्चा हुई जिसमें कहा गया कि परिणाम इससे भी बेहतर आएंगे।

कम मतदान ने बढ़ा दी भाजपा की चिंता

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव में पिछली बार के मुकाबले कम मतदान हुआ। मतदाताओं की इस उदासी से राजनीतिक पार्टियों खासकर भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी के कई नेताओं को लग रहा है कि मतदान में गिरावट की वजह मध्यम वर्ग की उदासीनता है और इसका सीधा नुकसान उसे होगा। पार्टी के शीर्ष नेता मतदान फीसद को लेकर चिंतित थे। उनकी चिंता का कारण कुछ माह पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव के अनुभव को लेकर था।

हरियाणा में मतदान फीसद में गिरावट से भाजपा को नुकसान हुआ था। भाजपा के शीर्ष नेताओं को लग रहा था कि कहीं दिल्ली में भी मतदान फीसद कम न हो जाए, इसलिए वे मतदाताओं को घर से बूथ तक पहुंचाने को बड़ी चुनौती मान रहे थे। इससे पहले वे कई दिनों से बूथ प्रबंधन को मजबूत करने में लगे हुए थे। बूथ कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए काम करने का निर्देश दिया गया था। सांसदों को उनके काम की निगरानी करने की हिदायत दी गई थी। बावजूद इसके पिछले भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी के कई नेताओं को लग रहा है कि मतदान में गिरावट की वजह मध्यम वर्ग की उदासीनता है और इसका सीधा नुकसान उसे होगा। पार्टी के शीर्ष नेता मतदान फीसद को लेकर चिंतित थे। उनकी चिंता का कारण कुछ माह पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव के अनुभव को लेकर था।

करने में लगे हुए थे। बूथ कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए काम करने का निर्देश दिया गया था। सांसदों को उनके काम की निगरानी करने की हिदायत दी गई थी। बावजूद इसके पिछले भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी के कई नेताओं को लग रहा है कि मतदान में गिरावट की वजह मध्यम वर्ग की उदासीनता है और इसका सीधा नुकसान उसे होगा। पार्टी के शीर्ष नेता मतदान फीसद को लेकर चिंतित थे। उनकी चिंता का कारण कुछ माह पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव के अनुभव को लेकर था।

एक्टिवेटेड पोल को नकारा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मतदान के बाद सभी एंक्टिवेटेड पोल में आप की सरकार बनने की संभावना जताई गई है। भाजपा को वोट 2015 की तरह परराज्य का सामना करना पड़ सकता है। इसके विपरीत भाजपा नेता जीत का दावा कर रहे हैं। प्रवेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एंक्टिवेटेड पोल के नतीजों को सिर से खारिज कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया, 'ये सभी एंक्टिवेटेड पोल फेल होंगे। मेरा ये ट्वीट संभावना के रखिएगा। भाजपा दिल्ली में 48 सीट लेकर सरकार बनाएगी। कृपया ईवीएम को दोष देने का अभी से बहाना न ढूँढ़ें।' राज्यसभा सदस्य व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विजय गोयल ने भी दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली में जिस तरह से लोगों का समर्थन दिखा, उससे स्पष्ट है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है।

उत्साह

पहली बार मतदान करने वाले युवाओं ने शिक्षा और ढांचागत विकास जैसे मुद्दों पर दिया वोट

किशन कुमार, नई दिल्ली : लोकतंत्र के महापर्व में पहली बार सहभागिता निभाने वाले मतदाताओं में जोश देखने को मिला। दिल्ली के इन नए दबंगों ने शिक्षा से लेकर दिल्ली के ढांचागत विकास जैसे मुद्दों पर अपना वोट डाला। युवतियों ने महिला सुरक्षा के नाम पर अपना पहला मतदान किया। विभिन्न पोलिंग बूथों पर शाम तक युवा मतदाताओं की भीड़ सबसे ज्यादा देखी गई। सुबह से ही ओल्ड राजेंद्र नगर, पटेल नगर, करोल बाग व पहाडगंज के मतदान केंद्रों पर युवा मतदान के लिए पहुंचने लगे थे। सिवासी दंगल में उम्मीदवारों के वोट डालने के पहले अनुभव की मुस्कान युवाओं के चेहरे पर देखते ही बन रही थी। करोल बाग में मतदान करने पहुंची शालू ने कहा कि दिल्ली में महिला सुरक्षा का मुद्दा अहम है, आमतौर पर दिन ढलने के बाद महिलाओं का निकलना सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में शैक्षणिक स्तर पर भी सुधार की जरूरत है। मतदान के लिए पहुंचते-पहुंचते ने कहा कि दिल्ली को ढांचागत विकास की जरूरत है। इसी मुद्दे पर उन्होंने अपना पहला वोट डाला है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली के मतदाताओं को दबंग नाम देना सराहनीय है।



दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान करने पहुंचे कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाइज़ की तलाशी लेता पुलिसकर्मी। तस्वीर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी (दाएं) और पुत्र रेहान (बाएं) भी नजर आ रहे हैं। रेहान ने पहली बार चुनाव में वोट डाला। एएनआइ

नेशनल कैपिटल

पेटीएम संस्थापक व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पर धोखाधड़ी का केस

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजय शेखर शर्मा व पेटीएम पेमेंट बैंक समेत पांच के खिलाफ कविनगर थाने में आईटी एक्ट व धोखाधड़ी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। कैशबैक का झांसा देकर पेटीएम खाता हैक कर कारोबारी के खाते से करीब डेढ़ लाख उड़ाने के मामले में एएसएसपी कलानिधि नैथानी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।

राजनगर में आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट की एजेंसी चलाने वाले राजकुमार सिंह का बिजनेस पेटीएम खाता है, जिसमें आईसीआईसीआइ बैंक का खाता जुड़ा हुआ है। उनके पास 28 दिसंबर को कॉल आई कि मैं अजय शेखर शर्मा पेटीएम से बोल रहा हूँ। बातचीत में एक बार उसने अपना नाम अजय शर्मा भी बताया। कॉलर ने कैशबैक देने की बात कहकर बताया कि उन्हें मैसेज किया गया है। मैसेज में दिए लिंक पर क्लिक करने को कहा गया। राजकुमार सिंह ने लिंक पर क्लिक करने से इन्कार कर दिया। इस पर कॉल करने वाले ने उसी दिन हुई राजकुमार को दो टूटनेकेशन के बारे में बताया। कॉलर द्वारा खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी देने पर उन्हें विश्वास हो गया और उन्होंने लिंक पर क्लिक कर दिया। इसके बाद खाते से 1.47 लाख रुपये कई बार में निकल गए। पीड़ित के अनुसार इसमें से 41 हजार रुपये रजत जैन के पेटीएम में गए, जबकि बाकी रकम अन्य एक बैंक खाते में गई।

दोजेकेशन के दौरान 1400 रुपये का कैशबैक मिला था, उसे भी निकाल लिया गया। शिकायत पर बैंक ने रकम को लीन खाते में डाल दिया। ये रुपये उनके खाते में ही दिख रहे थे, लेकिन जनवरी में ये रुपये दिखने बंद हो गए। एएसएसपी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। साक्ष्यों के आधार पर छानबीन कर विवेचना कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

महिला एसआइ के हत्यारे साथी एसआइ ने कर ली आत्महत्या

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास शुक्रवार देर रात दिल्ली पुलिस की प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर प्रीति अहलावत की गोली मार हत्या करने के बाद आरोपित प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर दीपांशु राठी ने सोनीपत में अपने घर के पास जाकर उसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। दोनों 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर थे। शुक्रवार को घटना के बाद पुलिस को उसके बैचमेट प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर दीपांशु राठी पर भी शक हुआ था। पुलिस जांच कर ही रही थी कि शनिवार तड़के दीपांशु का शव सोनीपत में कार में मिला। जांच में साफ हो गया कि उसी ने प्रेम-प्रसंग में नाहन एमएम पिस्टल से तीन गोली मार प्रीति की हत्या कर दी और कार से दिल्ली से सोनीपत भागकर सिर में गोली मार आत्महत्या कर ली।

प्रीति हरियाणा के रोहतक की रहने वाली थी। वह बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई थीं और आठ महीने के प्रशिक्षण के बाद उनकी पहली तैनाती पटपडगंज औद्योगिक थाने में हुई थी। रोहिणी में किराये पर घर लेकर वह अपने बैच की ही दो अन्य महिला प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर के साथ रहती थीं। वहीं से रोज मेट्रो से थाने आती-जाती थीं। आरोपित दीपांशु राठी सोनीपत की शास्त्री कॉलोनी का रहने वाले थे। प्रशिक्षण के पश्चात उनकी तैनाती भजनपुरा थाने में हुई थी। पुलिस के मुताबिक प्रशिक्षण के दौरान दोनों में जास पहाचन हुई थी। धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन छह महीने पहले प्रीति ने दीपांशु से दूरी बना ली थी और दीपांशु राठी ने पीछा शुरू कर दिया। बिना कुछ कहे दीपांशु ने पीछे से प्रीति पर पिस्टल से तीन गोлияं चलाईं। सिर में एक गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के तुरंत बाद दीपांशु कार से फरार हो गया।

पुलिस अधिकारी का कहना है कि शुक्रवार शाम को दीपांशु इयूटी के दौरान सरकारी नाहन एमएम की पिस्टल लेकर इलाके में गश्त करने के बहाने निकल गया था। वह कार से सीधे रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास पहुंच गया। जांच से पता चला है कि प्रीति के घर वाले उनकी शादी दूसरी जगह करना चाह रहे हैं। उधर, दीपांशु के घर वाले भी शनिवार को उसके लिए रिश्ता देखने जाने वाले थे।

पुलिस अधिकारी का कहना है कि दीपांशु का सोनीपत के अस्पताल में पोस्टमार्टम करा दिया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट में आत्महत्या का पुष्टि हो गई है। उसके अंगुंठे में पिस्टल के टिप्पण का हिस्सा फंसा हुआ था। गोली चलाने वाले आरोपित के हाथ में धुंध के साथ बारूद लग जाता है। साथ ही टिप्पण पर अंगुली का निशान रह जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट से दीपांशु के हाथ के धोवन से बारूद के बारे में पता लगाया। साथ ही अंगुली का निशान लेकर टिप्पण पर पड़े निशान से मिलान किया।

मध्यम वर्ग और महिलाओं का भी मिलता दिखा जबरदस्त समर्थन

प्रथम पृष्ठ का शेष

न्यूज एक्स-पोल स्टार्ट के एंक्टिवेटेड पोल में आप को 50 से 56, भाजपा को 10 से 14 तो कांग्रेस को शून्य सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। रिपब्लिक चैनल के एंक्टिवेटेड पोल में भी केजरीवाल की आंधी चलने का अनुमान लगाया गया है जिसमें करीब 52 फीसद वोटों के साथ आप को 48-61 सीटें जीतते हुए दिखाया गया है। भाजपा को 38 फीसद वोट के साथ 9 से 21 सीटें जीतने की स्थिति में आंका गया है। तो कांग्रेस को पांच फीसद वोट के साथ अधिकतम एक सीट मिलने की गुंजाइश है।

एंक्टिवेटेड पोल के सभी अनुमानों से स्पष्ट है कि दिल्ली में आप को दलित-मुसलमान, गरीब, छात्रों ही नहीं मध्यम वर्ग और महिलाओं का भी जबरदस्त समर्थन मिलता दिख रहा है। चुनाव नतीजों के इस अनुमान से यह भी साफ है कि मुफ्त बिजली, पानी, महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा, वाई-फाई के साथ दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में केजरीवाल सरकार के कामों पर लोगों ने न केवल मुहर लगाई है बल्कि इन्हें आगे जारी रखने के आप के वादे पर भी भरोसा किया है। भाजपा के आक्रामक राष्ट्रवादी प्रचार और कांग्रेस के रोजगार दिलाने व दिल्ली की पुरानी विरासत लौटाने के वादे को जनता ने पूरी तरह से ठुकरा दिया है।

दिल्ली से मुंबई व हावड़ा रेल लाइनों के दोनों ओर दीवार बनाने का काम शुरू

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रेलवे ने दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा रूट पर ट्रेनों की रफ्तार को 160 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए ट्रैक के दोनों ओर दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस क्रम में 3000 किलोमीटर की लंबाई में ट्रैक के दोनों ओर दीवार बनाने के ठेके पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

भविष्य में दोनों स्टूटों पर बंदे भारत जैसी सेमी-हाईस्पीड ट्रेनों के संचालन की योजना के तहत ट्रेनों को हादसों से बचाने तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने अनेक कदम उठाए हैं। ट्रैक के दोनों ओर कंक्रीट की दीवारें खड़ी करने के ठेके दिया जाना उनमें से एक है।

इसके अलावा ब्राइडगेज लाइनों पर चौकीदार रहित क्रासिंगों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। चौकीदार वाली क्रासिंगों को भी क्रमिक रूप से खत्म करने का अभियान शुरू होना है। इसके लिए ऐसी क्रासिंगों पर ओवरब्रिज अथवा अंडरपास बनाकर खत्म किया जा रहा है। क्रासिंग हादसे खत्म करने के लिए क्रासिंगों की इंटरलॉकिंग भी की जा रही है। अब तक

3000

किमी कंक्रीट की दीवार खड़ी की जाएगी दोनों रूटों पर

160

किमी प्रति घंटा तक होगी इन रूटों पर ट्रेनों की रफ्तार



दिल्ली-हावड़ा रेलवे रूट पर दौड़ती ट्रेन।

फाइल

11,552 लेवल क्रासिंगों की इंटरलॉकिंग की जा चुकी है। यही नहीं, ट्रैक के रखरखाव के काम में मानवीय गलतियों को न्यूनतम करने के लिए मशीनों का उपयोग बढ़ा दिया गया है। चलती ट्रेनों में कोच और वेगन की यांत्रिक खामियों का पता लगाने के लिए ट्रैक पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग आफ रोलिंग स्टॉक (ओएमआरएस) और डील इंपैक्ट लोड डिटेक्टर (वाइल्ड) प्रणालियां लगाई जा रही हैं। अब तक 7 जगहों पर ओएमआरएस लगाए जा चुके हैं, जबकि दो और जगहों पर इन्हें लगाया जा रहा है।

इसी प्रकार 17 स्थानों पर वाइल्ड लगा दिए गए हैं।

दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को न्यूनतम चोट पहुंचने, इसके लिए लंबी दूरी की सभी ट्रेनों में पुराने आइसीएफ कोच की जगह पर लिंक हॉफमैन बुश (एलएचबी) कोच लगाने का अभियान छेड़ा गया है। कोच कारखानों में अब सिर्फ एलएचबी कोच का उत्पादन हो रहा है। कोच के भीतर आग से सुरक्षा के लिए उन्नत क्वालिटी की ज्वलनरोधी की इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं फिक्स्चर्स का उपयोग किया जा रहा है।

आगामी सिग्नल के प्रति लोको पायलट को पूर्व चेतावनी देने के लिए सिग्नल से दो पोल पहले इलेक्ट्रिक पोल पर प्रकाश में चमकने वाले रिट्रो-रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड लगाए जा रहे हैं। उत्तर भारत में कोहरे के दौरान सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए जीपीएस आधारित फॉग पास डिवाइस लगाई जा रही हैं। इससे ड्राइवर को आगे आने वाले सिग्नल, क्रासिंग आदि की दूरी का अंदाजा लगा जाता है।

हाल ही में रेलवे ने सिग्नल प्रणाली के आधुनिकीकरण की पायलट योजना प्रारंभ की है जिसके तहत बीना-झांसी समेत 640 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले चार रूटों पर काम शुरू किया जा रहा है। इस प्रायोगिक परियोजना पर 1609 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी) सिस्टम, ट्रेन कोलीजन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (टीकेएस) तथा केब सिग्नलिंग (जिसमें लोको पायलट को केबिन के भीतर मानीटर पर सिग्नल दिखाई देता है) जैसी आधुनिक प्रणालियों की कुशलता को आजमा कर देखा जाएगा और फिर संपूर्ण रेलवे में इन्हें अपनाया जाएगा।

वीडियो सर्विलांस से होगी यात्रियों की सुरक्षा

प्रदीप चौरसिया, मुरादाबाद

महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए निर्भया फंड से रेलवे इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) आधारित वीडियो सर्विलांस सिस्टम लगाने जा रहा है। यह सिस्टम देशभर के 983 रेलवे स्टेशनों पर लगाए जाएंगे। कुंभ मेला के पहले हरिद्वार स्टेशन पर वीडियो सर्विलांस सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है। तीन प्रकार के लेंस होंगे और दो किमी तक निगरानी की जा सकती है।

रेल प्रशासन ने 'ए' व 'बी' श्रेणी के स्टेशनों पर सीसीटीवी लगा रखा है। सिस्टम से 50 मीटर से कम दूरी तक निगरानी होती है। उनमें दूर की तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं आती है। घटना होने के बाद आपराधी को फोटो पहचानने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे आधुनिक वीडियो सर्विलांस सिस्टम लगाने जा रहा है। इसके लिए निर्भया फंड से 250 करोड़ रुपये का बजट मिला है। रेलवे ने काम

- दो किमी दूर तक होगी निगरानी, तीन प्रकार के लेंस
- रेलटेल को सौंपा गया काम, हरिद्वार स्टेशन पर तमोगा सिस्टम

मंडल में 12 स्टेशन पर सामान्य सीसीटीवी लगाए जाएंगे

मुरादाबाद रेल मंडल के चार स्टेशनों पर सामान्य सीसीटीवी लगे हैं। सभी का कंट्रोल आरपीएफ करती है। फंड से रेल मंडल के 12 स्टेशनों पर सामान्य सिस्टम के सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं। बाद में उनको अपडेट सिस्टम में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

रेलटेल को सौंपा है।

यह होगी खासियत : वीडियो सर्विलांस सिस्टम में शक्तिशाली लेंस लगा है, जिससे दो किमी दूर तक की चीजें पूरी तरह से साफ दिखेंगी। पूरी तरह से स्वचालित सिस्टम में लेंस स्वतः ही संबोधित को जूम

करेगा और तीन तरफ से वीडियो बनाएगा। प्लेटफार्म पर लगे कैमरे से पूरे यार्ड की निगरानी हो सकेगी।

कंट्रोल रूम से हो सकेगा फोकस : सिस्टम में अल्ट्रा एचडी-4 के कैमरे लगेंगे। कंट्रोल रूम में बैठा कर्मचारी संदिग्ध पर कैमरा फोकस कर सकता है। उसके प्रत्येक क्षण का वीडियो कंट्रोल रूम को भेज सकेगा।

30 दिन का डाटा रहेगा सुरक्षित : घटना का विश्लेषण करने के लिए 30 दिन का डाटा सुरक्षित रहेगा। पुलिस अधिकारी ऑनलाइन मोबाइल से इससे जुड़ सकते हैं और स्टेशन की प्रत्येक गतिविधि देख सकते हैं।

कुंभ मेला के पहले हरिद्वार में लग जाएंगे सिस्टम : कुंभ मेला जनवरी, 2021 से शुरू हो जाएगा। इससे पहले रेलवे हरिद्वार स्टेशन पर सिस्टम लगा देगा। प्रवर मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा ने बताया कि आधुनिक सिस्टम वाला सीसीटीवी हरिद्वार में कुंभ मेला के पहले लगाया जाएगा।

न्यूज गेलरी

एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ याचिका पर फैसला कल

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जाति (अनुसूचित जनजाति (एससी, एसटी) (अत्याचार रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2018 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को फैसला सुनाएगा। इस कानून के जरिए एसटी,एसटी के खिलाफ अत्याचार के आरोपितों के लिए अग्रिम जमानत के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस विनोद सरन और जस्टिस रविंद्र भट की पीठ फैसला सुनाएगी। पिछले साल अक्टूबर में पीठ ने इस कानून में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को बरकरार रखने के संकेत दिए थे। केंद्र सरकार ने संशोधनों के जरिए आरोपित की तत्काल गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत के प्रावधान को फिर से बहाल कर दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि वह इसकी भी स्पष्ट करेगी कि पुलिस एससी,एसटी कानून के तहत की गई शिकायत पर कोई कार्रवाई करने से पहले प्राथमिक जांच कर सकती है, अगर उसे शिकायत प्रथम दृष्टया फर्जी लगती है। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने 20 मार्च, 2018 के अपने फैसले में इस कानून के तहत शिकायत पर स्वतः गिरफ्तारी के प्रावधान पर रोक लगा दी थी। साथ ही अग्रिम जमानत का प्रावधान भी जोड़ दिया था। बाद में 30 सितंबर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने पुराने कानून को बहाल कर दिया था। केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च के फैसले को पलटते हुए दोबारा पुराने कानून को लागू कर दिया था। (एनआइ)

गुजरात में बच्चों को नाश्ते में अंडा नहीं देगी सरकार

अहमदाबाद : विज्ञापनों में भले ही संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे स्लोगन का प्रचार होता रहा है, गुजरात सरकार ने आदिवासी बहुल दाहोद जिले में कुपोषित बच्चों को अंडा देने से साफ इन्कार किया है। सरकार की ओर से बच्चों को पौष्टिक आहार व दूध पहले से दिया जा रहा है। दाहोद जिले में अत्यंत कुपोषित बच्चों को नाश्ते में अंडा देने की खबरों के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री विजय रूपानी के कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य में कुपोषण अभियान के जरिये कुपोषित व अत्यंत कुपोषित बच्चों को नाश्ते में पौष्टिक आहार व दूध दिया जा रहा है। फल व फास्ट फूड सामग्री दी जा रही है, ऐसे में बच्चों को नाश्ते में अंडा दिए जाने की बात पूरी तरह बेवज्जियाद है। गौरतलब है कि गुजरात शाकाहारी बहुल प्रदेश है तथा मुख्यमंत्री विजय रूपानी स्वयं दिन समुदाय से आते हैं और शाकाहार, अहिंसा व जीव दया का गंभीरता से पालन करते हैं। (राज्य)

मुकदमे से पूर्व अनिवार्य मध्यस्थता वाले कानून के लिए यह सही वक्त : बोबडे

दो टूक ▶ सीजेआइ ने कहा, जजों का लक्ष्य लोकप्रियता पाना नहीं, विवाद सुलझाना

भारत में मध्यस्थता प्रणाली को लेकर लोगों को कम जानकारी

नई दिल्ली, एंजेंसियां : प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) शरद अरविंद बोबडे ने शनिवार को कहा कि देश में मुकदमे से पहले अनिवार्य मध्यस्थता वाला कानून बनाने का यह सबसे सही समय है। उन्होंने कहा कि इससे कार्यक्षमता सुनिश्चित होगी और पक्षकारों के साथ ही साथ अदालतों के लिए मामलों के लंबित होने का समय घटेगा।

प्रधान न्यायाधीश 'वैश्वीकरण के युग में मध्यस्थता' विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे संस्करण को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी जज का लक्ष्य लोकप्रियता पाना नहीं होता है। उसका उद्देश्य यह होता है कि विवाद का हल हो। जस्टिस बोबडे ने कहा कि भारत में संस्थागत मध्यस्थता के विकास के लिए एक मजबूत 'आरबिट्रेशन (मध्यस्थता) बार' जरूरी है क्योंकि यह ज्ञान और अनुभव वाले पेशेवरों की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करेगा।



नई दिल्ली में शनिवार को 'वैश्वीकरण के युग में मध्यस्थता पर अंतरराष्ट्रीय' सम्मेलन के तीसरे संस्करण के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। एनआइ

सीजेआइ ने कहा कि आज अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य और निवेश वाले वैश्विक आधारभूत ढांचे में मध्यस्थता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैश्विक समुदाय के एक अभिन्न सदस्य और व्यापार व निवेश के क्योंकि यह ज्ञान और अनुभव वाले पेशेवरों की उपलब्धता के कई फायदों की जरूरत पर शामिल होता है इसका सीमापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य और निवेश वाले वैश्विक आधारभूत ढांचे में मध्यस्थता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैश्विक समुदाय के एक अभिन्न सदस्य और व्यापार व निवेश के क्योंकि यह ज्ञान और अनुभव वाले पेशेवरों की उपलब्धता के कई फायदों की जरूरत पर

आतंकवाद की समस्या पर भी हुई बातचीत

प्रथम पृष्ठ का शेष

मोदी और राजपक्षे की बैठक में आतंकवाद की समस्या को लेकर भी बातचीत हुई। दोनों देशों ने इस समस्या का डटकर मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मोदी ने पिछले साल अप्रैल में श्रीलंका में ईस्टर डे पर बर्बर आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि यह केवल श्रीलंका नहीं, पूरी मानवता पर आघात था।

दोनों नेताओं ने श्रीलंका में संयुक्त आर्थिक परियोजना, व्यापारिक और निवेश संबंधों को बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श किया। मोदी ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने, पर्यटन को प्रोत्साहन देने, और संपर्क बेहतर बनाने पर भी चर्चा की गई। चेन्नई और जाफना के बीच हाल ही में सीधी फ्लाइट की शुरुआत इसी दिशा में प्रयासों का हिस्सा है।

श्रीलंका को दी जा रही सहायता की चर्चा करते हुए मोदी ने कहा कि उसके विकास में भारत एक विश्वस्त भागीदार रहा है। पिछले साल घोषित नई लाइन ऑफ क्रेडिट से हमारे विकास सहयोग को और अधिक जगह मिलेगा। श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में आतंरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए 48,000 से ज्यादा घरों के निर्माण



नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में श्रीलंका के अपने समकक्ष महिदा राजपक्षे के साथ बातचीत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनआइ

का इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरा हो जाने को लेकर मोदी ने खुशी जताई। मोदी ने मधुआरों के मानवीय मुद्दे पर राजपक्षे से बातचीत की और कहा कि इस विषय का

प्रभाव दोनों देशों के लोगों के जीवनयापन पर सीधे रूप से पड़ता है। इसलिए इस मुद्दे पर मानवतापूर्ण नजरिया रखने पर दोनों सहमत थे।

ई-गवर्नेंस मामले में दिल्ली और चंडीगढ़ अदालत

मुंबई, प्रे्ट : राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (एनईएसडीए) के सभी मानकों पर संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एवं दीव प्रशासन अदालत आए हैं। शनिवार को यहां जारी आधिकारिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

यह मूल्यांकन व्यापक रूप से चार श्रेणियों-संघ शासित प्रदेश, शेष राज्य, संघ शासित प्रदेश एवं केंद्रीय मंत्रालयों की वेबसाइट-के लिए किया गया। शेष राज्यों की श्रेणी में 18 राज्य शामिल हैं। इनमें हरियाणा और राजस्थान अदालत रहे हैं।

यहां 23वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने यह रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोक्त और पहाड़ी राज्यों में नगालैंड सर्विस पोर्टल के मामले में शीर्ष पर है। सर्विस पोर्टल के लिए तय इस्तेमाल में आसानी, सामग्री की उपलब्धता समेत सात मानकों में नगालैंड ने 45 फीसद मापदंड पूरे किए। केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टल श्रेणी के मूल्यांकन में त्रिपुरा के तहत आने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की वेबसाइट पहले नंबर पर रही। जबकि, सभी मापदंडों

पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट अदालत रही।

एनईएसडीए के ढांचे के तहत सभी सर्विस पोर्टल (राज्य/संघ शासित प्रदेश और केंद्रीय मंत्रालय सर्विस पोर्टल) का सात प्रमुख मानकों पर मूल्यांकन किया गया। इन मानकों में पहुंच, सामग्री उपलब्धता, उपयोग, संघ शासित प्रदेश एवं केंद्रीय मंत्रालयों की वेबसाइट-के लिए किया गया। शेष राज्यों की श्रेणी में 18 राज्य शामिल हैं। इनमें हरियाणा और राजस्थान अदालत रहे हैं।

यहां 23वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने यह रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोक्त और पहाड़ी राज्यों में नगालैंड सर्विस पोर्टल के मामले में शीर्ष पर है। सर्विस पोर्टल के लिए तय इस्तेमाल में आसानी, सामग्री की उपलब्धता समेत सात मानकों में नगालैंड ने 45 फीसद मापदंड पूरे किए। केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टल श्रेणी के मूल्यांकन में त्रिपुरा के तहत आने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की वेबसाइट पहले नंबर पर रही। जबकि, सभी मापदंडों

राज्य में 13 लाख युवा ले चुके हैं अब तक प्रशिक्षण, पिछले पांच साल में देश में 92 लाख युवाओं को मिल चुका है प्रशिक्षण

रंग लाई कोशिया

638 जिलों में 723 से अधिक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र चल रहे हैं, जहां अच्छी आधारभूत संरचना के साथ-साथ अच्छे प्लेसमेंट की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। जल्द ही 53 संसदीय क्षेत्रों के 85 जिलों में 89 नए प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोलने की तैयारी है। इससे देश के हर जिले में कम-से-कम एक कौशल विकास केंद्र खोलने की लक्ष्य को हासिल करना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, श्रीडी एनालिटिक्स जैसे नए क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम भी शुरू करने की योजना है।

सरकार की कोशिश आने वाले सालों में देश के हर जिले में कौशल विकास केंद्र स्थापित कर स्थानीय जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षण ले चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में आठ लाख, राजस्थान में सात लाख और मध्य प्रदेश में 6.5 लाख युवाओं ने प्रशिक्षण ले चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर का क्षेत्र युवाओं को पहले ही पसंद रहा है, जबकि वस्त्र व परिधान दूसरी पसंद के रूप में सामने आया है। कौशल विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फिलहाल देश के 513 संसदीय क्षेत्रों में आने वाले

आर्थिक मंदी पर गलती मानकर मनमोहन से सलाह मांगे सरकार : चिदंबरम

हैदराबाद, एनआइ : बेरोजगारी में बढ़ोतरी और आर्थिक मंदी को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य पी. चिदंबरम ने शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार माने कि उसने गलती की है और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से डूबती अर्थव्यवस्था पर सलाह देने का अनुरोध करें।

बजट 2020-21 विषय पर छात्रों को संबोधित करते हुए चिदंबरम ने कहा, 'यह अब तक को सबसे गरीब विरोधी सरकार है। ग्रामीण भारत और कृषि क्षेत्र खराब स्थिति में है। कम से कम सरकार इतना तो कर ही सकती है कि वह गलती स्वीकार करे और डॉ. मनमोहन सिंह से कहे कि आइए और हमें सलाह दीजिए।' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए उन्होंने बजट-2020 भाषण की तुलना 'सत्यनायक कथा' से की। चिदंबरम ने कहा, 'वित्त मंत्री देश की आर्थिक स्थिति क्यों नहीं बताना चाहती? अगर मैं सत्यनायक की कथा पढ़ी होती तो मुझे पता होता कि बजट पेश करने के दौरान उन्होंने क्या कहा। भारत के इतिहास में कभी भी जीडीपी लगातार छह तिमाही तक नहीं गिरी। सातवीं तिमाही में क्या होगा, मुझे नहीं पता।

नई पहल

इन सेंट्रलों में उन्हें नाश्ता, भोजन व खेलकूद जैसी सारी सुविधाएं मिलेंगी, चलने फिरने में लाचार बुजुर्गों के लिए ली जाएगी एनजीओ की मदद

बुजुर्गों के लिए देश भर में खुलेंगे डे-केयर सेंटर

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

बुजुर्गों को सरकार अब अकेला नहीं छोड़ेगी, बल्कि उनकी जरूरतों व सुख-सुविधाओं का पूरा ख्याल रखेगी। इसी कड़ी में सरकार ने घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए देश भर में डे-केयर सेंटर खोलने की योजना बनाई है जहां उन्हें नाश्ता, भोजन, समाचार पत्र, खेलकूद जैसी सारी सुविधाएं मिलेंगी। इन सेंट्रलों में जहां उन्हें अपनी उम्र के लोगों का साथ मिलेगा, वहीं वे अपना दिन भर का समय एक खुशनुमा माहौल में बिता सकेंगे।

फिलहाल मौजूदा समय में उन्हें दिन भर घर में ही कैद होकर रहना होता है। बुजुर्गों के प्रति सरकार की फिर्कमंदी के कदम यहीं नहीं थमे। वह उन बुजुर्गों को लेकर भी एक और नई योजना पर काम रही है, जो चलने-फिरने या फिर अपने खराब स्वास्थ्य के चलते प्रस्तावित डे-केयर सेंटरों तक भी नहीं आ सकते हैं। घर में अकेले रहने वाले ऐसे बुजुर्गों के लिए एनजीओ के माध्यम से ख्याल रखने की योजना पर काम करने की तैयारी है जिसकी जल्द ही घोषणा हो



प्रतीकात्मक।

सकती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक बुजुर्गों की देखरेख को लेकर प्रस्तावित नए कानून में ये सारे उपाय किए गए हैं। फिलहाल इससे जुड़ा विधेयक मौजूदा समय में संसद में लंबित है जिसके पारित होने के साथ ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। योजना से जुड़ी सारी तैयारियां लजपत पूरी हैं। माना जा रहा है कि संसद के बजट सत्र में यह विधेयक पारित हो जाएगा।

बुजुर्गों पर इसलिए भी है जोर

बुजुर्गों की देखरेख को लेकर सरकार का इसलिए भी जोर है, क्योंकि यही वह उम्र होती है, जब किसी को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। वैसे भी देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा समय में देश में 60 साल से ज्यादा आयु वर्ग वाले लोगों की संख्या करीब 11 करोड़ है, जिसके 2035 तक दोगुने से ज्यादा होने की संभावना जताई जा रही है।

बुजुर्गों की देखरेख को लेकर सरकार का यह कोई पहला कदम नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वह उनका ख्याल रखते हुए वयोश्री नाम से एक योजना चला रही है जिसमें उन्हें छद्दी, वॉकर, बत्तीसी, सुनने की मशीन जैसे उपकरण मुहैया कराए जाते हैं। योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, कि लगभग सभी संसदों ने मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर अपने-अपने क्षेत्र में इस योजना के तहत कै पालन की मांग की है।

कह के रहेंगे



माधव जोशी

मप्र में रिटायर हो रहे कर्मियों को संविदा नियुक्ति देकर टालेंगे संकट

राज्य ब्यूरो, भोपाल

मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति का सिलसिला शुरू होने में डेढ़ माह शेष हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने अपनी खराब माली हालत और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कामकाज पर पड़ने वाले असर को देखते हुए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति देने पर विचार शुरू कर दिया है। संविदा नियुक्ति लेने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाला फंड तत्काल नहीं मिलेगा, जिससे सरकार की माली हालत पर भी असर नहीं पड़ेगा और दफ्तरों का काम भी प्रभावित नहीं होगा।

मप्र का पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए मप्र में पदोन्नति पर रोक लगी है। इससे कामकाज

राज्य सरकार की खराब माली हालत ने विगाड़े समीकरण

सरकार के सामने दो विकल्प

- 1-सेवानिवृत्ति उम्र 62 की जगह 63 वर्ष कर दी जाए, ताकि फिलहाल कर्मचारियों की कमी और बड़ी देनदारी को टाला जा सके।
- 2-सेवानिवृत्ति के साथ ही एक साल की संविदा नियुक्ति दे दी जाए। रिटायरमेंट फंड पर सरकार सामान्य दर से ब्याज दे।

प्रभावित हो रहा था तो शिवराज सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा दो साल बढ़ाकर 62 साल कर दी थी। दो साल की यह अवधि मार्च में खत्म हो रही है। यानी 31 मार्च को प्रदेशभर में चार

आठ हजार कर्मचारी रिटायर्ड होंगे

मार्च से दिसंबर 2020 तक प्रदेशभर से करीब आठ हजार अधिकारी-कर्मचारी रिटायर्ड हो जाएंगे। इसका सीधा असर सरकारी कामकाज पर पड़ेगा, क्योंकि इन पदों पर काम करने वाले नहीं हैं।

सरकार को युवाओं का भविष्य और कर्मचारी हित दोनों को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए। - वीरेंद्र खोंगल, सदस्य, राज्य कर्मचारी आयोग

हजार से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी एक साथ रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में संकट से निपटने के लिए रिटायर कर्मियों को पहली बार एक साल के लिए संविदा पर रखा जा सकता है। इसके बाद अवधि बढ़ाई भी

जा सकती है। संविदा अवधि समाप्त होने के बाद सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले फायदे सामान्य दर से ब्याज के साथ देने पर भी विचार चल रहा है।

रिटायरमेंट उम्र 65 करने पर विचार : पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 साल करने का प्रस्ताव रखा था। बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की बजाय विकल्पों पर मंथन हुआ। यहां सरकार ने मार्च के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति देने के संकेत दिए हैं। सरकार यह व्यवस्था अगले एक साल जारी रख सकती है। इतने में पदोन्नति में आरक्षण मामले का फैसला आता है या सुप्रीम कोर्ट सशर्त पदोन्नति देने की मांग मंजूर करता है, तो ठीक, वरना संविदा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

न्यूज गेलरी

छग में हुक्का बार पर प्रतिबंध शराब की 49 दुकानें होंगी बंद

राष्ट्रपु: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में हुक्का बार के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। शराबबंदी की ओर धीरे-धीरे बढ़ने का एक और संकेत देते हुए अंग्रेजी शराब की 49 दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया है। धान पर खरम हुई सियासत को देखते हुए धान खरीद की तिथि भी पांच दिन बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शनिवार देर शाम को कैबिनेट की बैठक में उक्त निर्णय लिए गए। हुक्का बार को लेकर यह शिकायत मिल रही थी कि हुक्का बार में स्मूली छात्रों से लेकर नाबालिग बच्चों की मौजूदगी दिखती है। इससे समाज में गलत प्रभाव पड़ता है। शराबबंदी की ओर धीरे-धीरे कदम बढ़ाते हुए प्रदेश भर के 49 अंग्रेजी शराब की दुकानों को बंद करने का निर्णय भी लिया गया है। पिछले साल 50 शराब दुकानों को बंद किया गया था। (नईदुनिया)

जदयू के पोस्टर पर राजद ने क्रिया पलटवार

पटना : राजद एवं जदयू के बीच बिहार में पिछले करीब एक महीने से पोस्टर के जरिये बार-पलटवार जारी है। जदयू के पोस्टर के बाद राजद ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया है। जदयू ने दो दिन पहले पोस्टर जारी कर लालू परिवार के पुत्र मोह पर कटाक्ष किया था। वंदे मातरम की पैरोकी बनाते हुए पोस्टर में घंघे मातरम लिखकर राजद के शीर्ष नेताओं का मजाक उड़ाया गया था। राजद के पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर रखा गया है। पोस्टर पटना में कई जगह लगाए गए हैं। एक पोस्टर राबड़ी देवी के आवास के बाहर भी लगाया गया है। पोस्टर के बीच में नीतीश कुमार की एक तस्वीर है और चारों ओर कई स्लोगन लिखे गए हैं। तंज कसते हुए लिखा गया है कि 15 सालों में नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया है। इसलिए गिनाने से भी बचते हैं। इसके अलावा सरकारी खर्च से टेलीविजन एवं रेडियो पर प्रचार, माफिया से संबंध एवं पटना में जल-जमाव पर भी स्लोगन बनाया गया है। सभी में सरकारी कामकाज पर अंगुली उठाई गई है। (राब्यू)

‘वंद स्कूल खुलेंगे, पारा शिक्षकों का भी रखेंगे खयाल’

इटखौरी (चतरा) : झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि पिछली सरकार में बंद किए गए विद्यालयों को सरकार फिर से खोलेगी। सरकार की सोच झारखंड में शिक्षा का अलख जगाने की है और विद्यालय इसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। शनिवार को ब्रह्मकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे शिक्षा मंत्री मीडिया से मुखातिब थे। शिक्षा मंत्री ने इस दौरान पिछली सरकार पर तंज भी किया। उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने राज्य में विद्यालय बंद करवाया, राज्य की जनता ने उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। उनके साथ बरही के विधायक उमाकंठ अकेला ने भी मंच पर पूजा-अर्चना की। पारा शिक्षकों के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार को उनका भी खयाल है और वह इस मसले पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है। (जास)

असर

पदोन्नति में आरक्षण को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आसान होता दिख रहा है नई भर्तियों का रास्ता

उत्तराखंड में खुली नई भर्तियों की राह

राज्य ब्यूरो, देहरादून

पदोन्नति में आरक्षण को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड के सभी विभागों में लंबित पदोन्नतियों के खुलने व इसके सापेक्ष रिक्त होने वाले पदों पर भर्तियों की राह भी खुलती नजर आ रही है। प्रदेश में बीते सभी विभागों में पदोन्नति रुकी हुई थी। अधिकांश विभागों में पदोन्नति के बाद ही निचले पद खाली होने थे, जिन पर भर्ती की जानी थी। इनकी संख्या तकरीबन 20 हजार के आसपास मानी जा रही है। हालांकि, सही आंकड़ा जुटाने के लिए कार्मिक विभाग सभी विभागों से विस्तृत जानकारी लेने की तैयारी कर रहा है।

प्रदेश सरकार ने बीते सितंबर माह में प्रदेश में सभी विभागों में डीपीसी बैठकों को स्थगित करते हुए पदोन्नति प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी थी। इसका आधार हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण के मसले को लेकर चल रहे मुकदमों को बाधना गया। कोर्ट में चल रहे इन

दिकतों हटें, रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू करेगी राज्य सरकार

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने से पदोन्नति पर रोक की बाधा दूर



सुप्रीम कोर्ट

फाइल

मुकदमों का सबसे अधिक असर नौकरी की राह तक रहे युवाओं और सेवानिवृत्ति की दहलीज पर खड़े कार्मिकों पर पड़ा।

दरअसल, प्रदेश के विभिन्न विभागों में निचली श्रेणी के अधिकांश पद सीधी भर्ती के हैं। इनके ऊपर के पदों पर भी आधे पद सीधी भर्ती तो आधे पदोन्नति के जरिये भरे जाते हैं। वर्ष 2018 में सरकार ने जब ऐसे पदों की गणना

प्रक्रिया होगी शुरू अपर सचिव कार्मिक सुनम सिंह वादिद्या ने कहा कि कोर्ट का फैसला आने के बाद अब जद्व डीपीसी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभागों से भी पदोन्नति के सापेक्ष रिक्त होने वाले पदों का ब्योरा लिया जाएगा।

की थी तब इनकी संख्या 26 हजार आंकी गई थी। हालांकि, इनके बाद इनमें से कुछ पदों पर तो भर्ती हुई, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हुए हैं। इनमें राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, परिवहन, वन विभाग, वन निगम, सिंचाई विभाग, खाद्य-अपूर्ति, आबकारी, उद्योग व आयुष आदि समेत 40 विभागों के पद शामिल हैं।

पीडीपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री नईम पर पीएसए

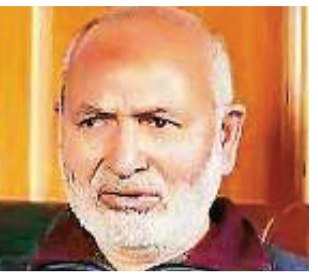
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री नईम अख्तर को भी छह माह की एहतियातन हिरासत के बाद शनिवार को पीएसए (जन सुरक्षा अधिनियम) के तहत नजरबंद कर दिया गया। इसके साथ ही नेशनल कांफ्रेंस के पूर्व विधायक मुबारक गुल, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के राजनीतिक सलाहकार तनवीर सादिक को भी सबजेल से रिहाई के बाद उनके घरों में नजरबंद कर दिया है। सब जेल एमएलए हॉस्टल में अब सिर्फ छह लोग ही एहतियातन हिरासत में हैं।

नईम अख्तर को पीएसए के तहत बंदी बनाया जाएगा, यह दो दिन पहले ही तय हो गया था। नौकरशाही छोड़ सियासत में सक्रिय हुए शाह फैसल पर भी जल्द ही पीएसए लगाए जाने की संभावना है। पांच अगस्त 2019 के बाद पीएसए के तहत बंदी बनाए जाने वाले नईम अख्तर मुख्यधारा की

पूर्व विधायक मुबारक गुल भी एमएलए हॉस्टल से छूटते ही नजरबंद

छह माह की एहतियातन हिरासत में के बाद शनिवार को ही छूटे थे यह नेता



नईम अख्तर

फाइल

सियासत से जुड़े छठे नेता हैं। उनसे पहले नेकां अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला पर 17 सितंबर 2019 को पीएसए लगाया गया था। गत पुर्नवार को पूर्व मुख्यमंत्री और नेकां उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, नेकां महासचिव

अली मोहम्मद सागर, पीडीपी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती व उनके मामा सरताज मदनो को पीएसए के तहत बंदी बनाया गया था।

अधिकारियों का कहना है कि पांच अगस्त 2019 को हिरासत में लिए गए नेकां के पूर्व विधायक और जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पूर्व स्पीकर मुबारक गुल और उमर अब्दुल्ला के राजनीतिक सलाहकार तनवीर सादिक को शनिवार दोपहर सब जेल एमएलए हॉस्टल से रिहा कर दिया गया। लेकिन दोनों नेता जैसे ही घर पहुंचे, पुलिस ने दोनों को अगले आदेश तक नजरबंद कर दिया।

सबजेल एमएलए हॉस्टल में बंद नईम अख्तर को आज ही रिहा किया गया था। इससे पहले कि वह घर पहुंचते, पुलिस ने उन्हें पीएसए के तहत दोबारा हिरासत में लेकर गुफकार रोड स्थित एम-5 सरकारी बंगले में कैद कर दिया। इस बंगले को सबजेल का दर्जा दिया गया है।

बंगाल में निजी वाहनों से स्कूल जाने पर लगाया गया प्रतिबंध हटा

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कोलकाता के 26 प्रमुख स्कूलों में बच्चों के आने-जाने के लिए पूल कार की अनिवार्य व्यवस्था किए जाने से संबंधित संकुलर (अधिसूचना) को वापस ले लिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बिना राज्य सरकार को सूचित किए व बगैर अनुमति के यह संकुलर जारी किया था। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस बारे में पता चलने पर उन्होंने तुरंत मेरे सामने इस मुद्दे को उठाया और हमने स्कूल शिक्षा विभाग को तत्काल प्रभाव से यह संकुलर वापस लेने को कहा।

शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि मैं ऐसे संकुलर जारी करने के पीछे आवश्यकता को समझने में पूरी तरह विफल रहा। पार्थ ने कहा कि हमें यह भी नहीं पता कि अन्य शहरों में पहले ऐसी कोई मिसाल या व्यवस्था है या नहीं। वहीं, स्कूल शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने भी कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से पूल कार की अनिवार्यता को लेकर जारी अधिसूचना को वापस ले लिया गया है। हालांकि, इसे वापस लेने के पीछे कारण बताने से उन्होंने साफ इन्कार किया। उल्लेखनीय

राज्य सरकार ने अनिवार्य पूल कार को लेकर जारी संकुलर लिया वापस

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हस्तक्षेप के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने वापस लिया फैसला

स्कूलों सप्ताह महानगर के 26 स्कूलों को बच्चों के आने के लिए दिया था निर्देश



ममता बनर्जी

फाइल

है कि जनवरी के अंतिम हफ्ते में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर कोलकाता के 26 प्रमुख स्कूलों के अधिकारियों से कहा था कि वे अनिवार्य रूप से ऐसी व्यवस्था शुरू करें जिसमें एक अप्रैल से छात्र या तो कार पूल करके स्कूल आए या स्कूल बस से आए। यानी असाधारण व आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर स्कूल आने के लिए व्यक्तिगत वाहनों के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था।

नगर-निकाय चुनावों में जीत के लिए घर-घर जाएंगे भाजपा सांसद

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल में इसी वर्ष होने वाले नगर-निकाय चुनावों लेकर भाजपा तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा चुनाव की तरह नगर पालिका एवं नगर निगम चुनावों में भी जगह दी जा सकती है। तेजस्वी के लिए सुकून की बात यह है कि किसी ने भी पार्टी के फैसले पर उंगली नहीं उठाई। मुंभर के राजद विधायक विजय कुमार विजय ने आरक्षक जन्म जाहिर की थी, किंतु समाधान मिलने पर सहमत भी दिखे।

नहीं दिखे तेजप्रताप : बैठक में राजद के चार बागी विधायक नहीं पहुंचे। चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहे इस विमर्श से विधायक तेजप्रताप यादव का गायब रहना भी चर्चा का विषय बना हुआ था। तेज प्रताप के अलावा चंद्रिका राय, फराज फातमी, प्रेमा चौधरी और महेश्वर यादव का तो पहले से तय था कि वे नहीं आने वाले हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में शक्ति सिंह यादव ने बताया कि वह की कटौती नहीं की गई है, बल्कि राजद के जनाधार में विस्तार का प्रयास किया गया है।

बंगाल में जनसंपर्क पर भाजपा का जोर, विधायक भी मतदाताओं से करेंगे बात

पार्टी के 18 सांसद एवं 10 विधायक घर-घर जाकर मतदाताओं से बात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे

सह-संयोजक बनाया गया है। लोकसभा चुनाव प्रबंधन कमेटी में भी भाजपा ने मुकुल राय को संयोजक बनाया था। इस तरह राज्य में नगर-निकाय चुनावों के लिए भी पार्टी ने मुकुल राय पर भरोसा जताया है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को बंगाल में रिकार्ड परिणाम हासिल हुआ था। इनके दो सांसद से 18 सांसद हो गए। इससे यहां पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया। नागरिक संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ राज्य में शुरू हुए प्रदर्शनों ने भाजपा को थोड़ा असहज कर दिया था, लेकिन दल ने इस कानून के समर्थन में व्यापक प्रचार शुरू कर स्थिति में सुधार लाई है। अप्रैले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी नगर-निकाय चुनावों में बेहतर परिणाम हासिल करना चाहती है। इसके लिए जनसंपर्क पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।

राकांपा प्रमुख शरद पवार की हत्या की साजिश के शक में शिकायत दर्ज

पुणे, प्रेद : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार की हत्या की साजिश का शक जताते हुए पार्टी के एक कार्यकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

शनिवार को साइबर सेल और शिवाजी नगर थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि जब से प्रदेश में शिवसेना-एनसीपी की सरकार बनी है कुछ लोग इस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। शिकायत करने वाले एनसीपी कार्यकर्ता लक्ष्मीकांत खबिया का कहना है कि यू-ट्यूब समेत सोशल मीडिया के कई प्लेटफार्म पर इस तरह के वीडियो डाले जा रहे हैं जिनमें नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसे की तरह सबक सिखाने की बात की जा रही है। उल्लेखनीय है कि लेखक व सामाजिक कार्यकर्ता दाभोलकर की 2013 और वामपंथी विचारक पुनसलर की 2015 में हत्या कर दी



शरद पवार

फाइल

गई थी। इन मामलों में कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

खबिया ने पार्टी प्रमुख पवार के खिलाफ इस तरह के बयान देने और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई के वकंठशपन ने कहा कि हम शिकायत की नाम भी दिए गए हैं जिसमें एक पत्रकार और एक सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाला

अतिवादी है। खबिया का कहना है कि इन दोनों के भाषण सुनने से ऐसा लगता है कि कहीं यह पवार साहब को रास्ते से हटाने की साजिश तो नहीं। राज्य में जबसे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बनी है एक यू ट्यूब चैनल पर ये दोनों अनाप-शानाप बोल रहे हैं। इन चैनल के कमेंट बॉक्स में पवार साहब को गोली मारो, बम फेंको जैसी टिप्पणियां की जा रही है।

शिकायतकर्ता ने कहा कि मैंने एनसीपी कोर्ट से गृहमंत्री बने अनिल देशमुख से इस मामले में विशेष जांच टीम (एसआइटी) गठित करने की मांग की है। इस मामले में पुणे के पुलिस आयुक्त के वकंठशपन ने कहा कि हम शिकायत की जांच कर रहे हैं। तथ्यों की पड़ताल के बाद ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे।

न्यूज गैलरी

नूतन के बंगले में चोरी करने के आरोप में एक गिरफ्तार

ठाणे : मशहूर अभिनेत्री नूतन के बंगले से नल और पांड्य चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अभिनेत्री का बंगला ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके में स्थित है। अपराध शाखा के सहायक निरीक्षक संदीप बगुल ने बताया कि तीन फरवरी को भोर के समय तीन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने बंगले पर तेनात दो चौकीदारों को दबोच लिया और छत की टाइल्स हटाकर घर में दाखिल हुए। बगुल ने बताया, 'गुप्त सूचना पर सक्रियता बरतते हुए हमने सजय भंडारी को कलवा के भास्कर नगर से गिरफ्तार किया। उसने हमें बताया कि उसके साथ जीतू वाघमारे और गनपत गुलार भी शामिल थे। दोनों को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।' मुंब्रा पुलिस ने आइपीसी की धारा 397 (जान लेने की कोशिश के साथ लूट या डकैती) के तहत मामला दर्ज किया है। सहायक निरीक्षक ने कहा कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। (प्र.)

कार्यालय पर हमला कराने वाला एसडीएम रिमांड पर

छतरपुर : मध्य प्रदेश के छतरपुर में खुद के कार्यालय पर हमला कराने के आरोपित छतरपुर एसडीएम अनिल सपकाले को शनिवार को कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। उमर, संभागीय आयुक्त आनंद शर्मा ने एसडीएम के अत्याचार के कार्यों की जांच के निर्देश कलेक्टर को दिए हैं। कोर्ट में पेश करने के दौरान अधिवक्ताओं ने सपकाले के खिलाफ नारेबाजी की। एसडीएम की ओर से जमानत अर्जी भी लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। गौरतलब है कि एक कॉलेज संचालक को फंसाने के लिए पांच फरवरी को एसडीएम कार्यालय छतरपुर में सपकाले ने हमला करवाया था। हमले की साजिश में शामिल निजी यूनिवर्सिटी के चेरमैन, पूर्व भाजपा नेता जितेंद्र अक्षर और इब्राहिम राजू बुंदेला को पुलिस शुक्रवार को ही कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले चुकी है। (नईदुनिया)

एक लाख के इनामी समेत 14 नक्सलियों ने किया समर्पण

दोरनापाल : छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शनिवार सुबह इंजरम में सीआरपीएफ 223 वाहिनी के अधिकारियों के समक्ष भेज्जी थाना क्षेत्र में सक्रिय 12 नक्सलियों ने समर्पण किया। वहीं, शाम को दोरनापाल पुलिस व सीआरपीएफ 74 वाहिनी के समक्ष एक लाख के इनामी समेत दो नक्सलियें ने समर्पण किया। समर्पण करने वाले नक्सली पुलिस जवानों पर फायरिंग, ब्लास्ट, वाहनों में लूटपाट व आगजनी जैसी बड़ी वारदात में शामिल रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोरनापाल में समर्पण करने वाले दोनों नक्सली माइवी राजु व हेमला सुक्का लंबे वक्त से हाईकोर नक्सली गतिविधियों में संलग्न थे। (नईदुनिया)

जंगल में 20 घंटे तलाशी के बाद पंजाब हरियाणा के पांच बदमाश गिरफ्तार

नईदुनिया, बड़वानी

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में उमटी क्षेत्र से अवैध हथियार खरीदकर लौट रहे पंजाब व हरियाणा के पांच बदमाशों को 20 घंटे की तलाशी के बाद पुलिस ने जंगल से गिरफ्तार कर लिया। ये बदमाश गुरुवार को बड़वानी के समीप आगरा-मुंबई रोड पर जामली गांव के टोल प्लाजा पर पुलिस को देख कार छोड़कर भाग निकले थे। एक बदमाश को गुरुवार और चार को शुक्रवार को ग्राम मातमूर-मोहीपुरा के जंगल से गिरफ्तार किया गया। इनसे एक विदेशी व सात देशी पिस्टल, 27 कारतूस व कार जब्त की गई है।

चारों बदमाशों ने भागने के दौरान शुक्रवार सुबह नागलवाड़ी में एक पुलिस आरक्षक को बाइक व मोबाइल भी लूटा था। पांचों बदमाशों पर पंजाब-हरियाणा में हत्या, लूट आदि के प्रकरण दर्ज हैं। बड़वानी के एसपी डीआर तेजीवार ने शनिवार को पूरे मामले की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि गुरुवार को सूचना मिली थी कि उमटी

मुंहतोड़ जवाब

► पाकिस्तान से घुसपैठ के लिए हुई गोलीबारी, भारत ने की कड़ी कार्रवाई

चार पाक चौकियां तबाह, तीन सैनिक ढेर

पुंछ में हुई पाक गोलाबारी में नायक शहीद, दो जवान भी घायल

जागरण न्यूज नेटवर्क, पुंछ

जम्मू-कश्मीर में आशंका सच साबित हुई और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर साजिशान भारी गोलाबारी शुरू कर दी। शनिवार को पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के गुल पुर सेक्टर के देगवार में सैन्य चौकियों के अलावा करीब एक दर्जन गांवों को निशाना बनाते हुए मोर्टार दागे। इसमें एक अग्रिम चौकी पर तैनात नायक शहीद और दो अन्य जवान घायल हो गए। गोलाबारी से सीमा पर कुछ जगह आग भी लग गई है। भारत ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए चार चौकियां तबाह कर दीं। वहीं, एक अधिकारी सहित तीन पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की सूचना है।

शहीद नायक की पहचान राजीव सिंह शेखावत निवासी राजस्थान और घायलों की सिपाही शोयम सिंह व सिपाही आजाद सिंह के रूप में हुई है। पाकिस्तानी सेना ने शनिवार को गुलपुर सेक्टर में दोपहर बाद करीब 3:45 बजे पहले भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलाबारी शुरू की। बाद में एकाएक रिहायशी क्षेत्रों में भारी मोर्टार दागने शुरू कर

एलओसी पर लगी आग से वारूदी सुरंग में हो रहे विस्फोट

पुंछ के बालाकोट सेक्टर में सीमा पर पाकिस्तानी की ओर से साजिशान लगाई गई आग शनिवार को दूसरे दिन भी बुझ नहीं पाई। इस आग ने करीब तीन किलोमीटर के सीमांत क्षेत्र को अपने दायरे में ले रखा है। सेना के दमकल कर्मी और जवान आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान ने गत शुक्रवार को सीमा पर आग लगा दी थी, ताकि वारूदी सुरंग नष्ट हो जाए और आतंकों को सुरक्षित घुसपैठ करवाया जा सके।

दिए। इसी बीच, एक अग्रिम पोस्ट पर पाक गोलाबारी से एक सैनिक शहीद व दो अन्य जवान घायल हो गए। गोलाबारी के बीच घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। गोले जब लोगों के घरों के आसपास गिरने लगे तो भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तानी सेना की कई चौकियां तबाह हो गई हैं। सीमा पार कई जगहों से धुआं उठता देखा गया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने कुछ समय के लिए गोलाबारी बंद की, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन शुरू कर दिया। पिछले करीब चार दिन से उत्तरी कश्मीर में टंगशर के सामने गुलाम कश्मीर में नीलम व लीपा घाटी में पाकिस्तान ने अपने तोपखाने की दिशा बदलने के साथ गतिविधियां भी तेज की हैं।

नवी मुंबई में 21 मंजिली इमारत में आग, सात घायल

ठाणे, प्रेद : नवी मुंबई की एक बहुमंजिली आवासीय इमारत में गैस सिलेंडर विस्फोट होने से आग भड़क उठी। 21 मंजिली इमारत में आग पर काबू पाने के दौरान अग्निशमन दस्ते के सात कर्मचारी घायल हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि पालम बीच रोड के समीप सीवुड्स स्थित सी होम अपार्टमेंट के सबसे ऊपर की दूसरी मंजिल के एक डुप्लेक्स में शनिवार सुबह गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। आग पर काबू पाने के दौरान घायल हुए सातों कर्मचारियों को नेशनल बर्न सेंटर में भर्ती कराया गया है। उनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जाती है, उधर उन्हें सघन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में रखा गया है।

नवी मुंबई आपदा नियंत्रण कक्ष के प्रमुख दादासाहेब चावुकस्वर ने कहा, 'सुबह 6:30 के आसपास डुप्लेक्स फ्लैट में सिलेंडर विस्फोट होने के बाद सबसे ऊपर के दो माले पर आग फैल गई।'

ठाणे म्यूनििसिपल कार्पोरेशन के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन सेल के प्रमुख संतोष कदम ने कहा कि आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन की छह गाड़ियां भेजी गईं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।



महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गैस सिलिंडर से 21 मंजिला इमारत में लगी आग। एएनआइ

उत्तराखंड में भूकंप के झटके, बागेश्वर में दो

घायल, दो मकान क्षतिग्रस्त

जागरण संवाददाता, बागेश्वर : उत्तराखंड में शनिवार सुबह कुमाऊं में भूकंप के झटके महसूस हुए। सुबह 6:31 बजे आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.7 मैग्नीट्यूड मापी गई है। भूकंप का केंद्र बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील का गोगिना क्षेत्र था। बागेश्वर में अधिक प्रभाव होने से दो मकान रातभर खेत-जंगलों में भटकते चार बदमाश शुक्रवार तड़के नागलवाड़ी पहुंचे। यहां गश्त कर बाइक से लौट रहे आरक्षक गब्बरसिंह अवासे ने उन्हें रोककर पुछताछ की तो उससे मारपीट कर उनकी बाइक व मोबाइल लूट कर आरोपित मातमूर-मोहीपुरा के जंगल की ओर भाग गए। इस पर पुलिस ने छह टीमें बनाकर संभावित जंगल क्षेत्र की घेराबंदी की और चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।

डोंगल से नेट चलाकर कर रहे थे वाट्सएप कॉलिंग : पकड़े गए बदमाश इतने शातिर हैं कि वे एक-दूसरे से बात करने के लिए डोंगल (राउटर) के माध्यम से इंटरनेट चला कर वाट्सएप कॉलिंग का उपयोग करते थे, ताकि कॉल डिटेल् में उनके नंबर बल लगाया गया। पुलिस को देख पांचों बदमाश कार छोड़कर फरार हो गए थे।

हिजबुल और लश्कर के पांच आतंकी गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

पुलिस ने अपने आतंकरों भी अभियान को जारी रखते हुए शनिवार को बड़गाम व बांडीपोरा में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पांच आतंकों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, पोस्टर और आतंकों के लिए जाली दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए पहचानपत्र, दो लैपटॉप और अन्य सामान भी जब्त किया है। एसपी बांडीपोरा राहुल मलिक ने बताया कि बीते कुछ दिन से हाजिन और उसके साथ सटे इलाकों में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी की खबरें आ रही थीं। इस बीच, लश्कर के कुछ धमकी भरे पोस्टर भी पाए गए। इन पोस्टरों में लोगों को सुरक्षाबलों और केंद्र सरकार के खिलाफ भड़काया गया था। इन सभी मामलों का संज्ञान लेते हुए एक जांच शुरू की गई। जल्द ही हाजिन ने सक्रिय लश्कर के एक दो सदस्यीय मॉड्यूल का पता चला। इन दोनों को उनके ठिकाने

महबूबा पर अलगाववादियों संग काम करने का आरोप

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के अनुच्छेद 370 पर विवादित बयान, आतंकों के प्रति नरम रवैया और अलगाववादियों के साथ काम करने ही मुख्य रूप से जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) का आधार बना। उनकी पार्टी का झंडा और निशान भी उनके लिए पीएसए के कारणों में एक है। सिर्फ महबूबा ही नहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी अनुच्छेद 370 और आसिफ अहमद पर पुत्र अब्दुल खालिक पर निवासी परं मोहल्ला हाजिन के रूप में हुई है। आसिफ की हाजिन में दुकान है। इन दोनों के पास से आतंकों के लिए तैयार किए गए मतदाता पहचान पत्र, फर्जी वाहन चालक लाइसेंस, सिमकार्ड, आतंकी सातकों के पोस्टर भी मिले हैं। पुलिस ने इनके पास से दो लैपटॉप व अन्य सामान भी जब्त किया है। इसी दौरान, पुलिस ने बड़गाम जिले में सक्रिय हिजबुल मुजाहिदीन के तीन आतंकों को अलग-अलग छापां में गिरफ्तार करने का दावा किया है। इनकी पहचान अमिर शफी डार, शब्बीर अहमद गनई और मुसदर अहमद खान के रूप में हुई है। इन तीनों के पास से भारी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद भी मिला है। आतंकों को पकड़ने के लिए एक विशेष टिम भी बनाया गया है।

महबूबा बोली थीं - कोई तिरंगा उठाने वाला



महबूबा मुफ्ती। फाइ

नहीं होगा : डोजियर में महबूबा द्वारा जुलाई 2019 को दिए भाषणों का भी जिक्र है। इसमें महबूबा के उस भाषण का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 व 35ए से छेड़छाड़ करना वारूद को हाथ बयानबाजी के लिए जरूर रंज होगा। उन पर पीएसए के लिए बनाए आधार पर उनकी बयानबाजी का जिक्र है। पांच अगस्त 2019 की तड़के एहतियातन हिरासत में लिए उमर व महबूबा को गत गुरुवार को पीएसए के तहत बंदी बनाया गया है। सूत्रों ने बताया कि महबूबा को पीएसए के तहत बंदी बनाए जाने का जो डोजियर जारी किया है उसमें अलगाववादियों पर नरम रुख और उनके साथ मिलकर काम करने की सूचनाओं व आरोपों का जिक्र है। डोजियर में अनुच्छेद 370 हटाने से पूर्व महबूबा के टवीट का हवाला दिया है। आतंकों के मारे जाने के बाद उनके सम्मान और सेना पर आतंकों के खिलाफ केमिकल हथियार इस्तेमाल करने के आरोप व तीन तलाक और देशभर में मौब लिंचिंग पर भड़काऊ टवीटों का जिक्र भी डोजियर में है।

उमर ने कहा था - आधा है भारत में जम्मू-कश्मीर का विलय : उमर को पीएसए के तहत बंदी बनाए जाने के डोजियर में 370 हटाने के खिलाफ उनकी बयानबाजी का उल्लेख किया है। इसमें उनके उस बयान का भी जिक्र है जिसमें उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 समाप्त करने या इसमें बदलाव से जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ जाएगी। जम्मू-कश्मीर के भारत विलय को अर्धमिलन के उनके बयान का डोजियर में हवाला दिया गया है।

बांडीपोरा से लापता हुए चारों किशोर पुलिस ने तलाश निकाले

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : परिवारवालों को बिना बताए लापता हुए चार किशोरों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही तलाश कर लिया। ये सभी उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए थे। पुलिस ने इन सभी को पकड़ने के बाद जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर शनिवार को उनके अभिभावकों को सौंप दिया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शुक्रवार को बांडीपोरा के कलूसा इलाके से ये चारों किशोर लापता हो गए थे। इनमें 13 वर्षीय कामरान फैयाज पुत्र फैयाज अहमद, 14 वर्षीय अमिर मुस्ताक पुत्र मुस्ताक अहमद बेग, 14 वर्षीय फैयाज खान पुत्र मोहम्मद मकबूल खान और 16 वर्षीय आबिद सुलेमानी पुत्र मोहम्मद कलवा शामिल हैं। आबिद सुलेमानी मूलतः उत्तर प्रदेश में बिजनेस का रहने वाला है और बीते कुछ समय से कलूसा में ही रह रहा था। पुलिस ने बताया कि जल्द ही पता चल गया कि यह चारों लड़के जवाहर सुरंग पार कर गए हैं कि इन दोनों एक्सचेंजों की वजह से देश के उधमपुर में इन सभी को पकड़ लिया गया। सभी सूझने निकले थे।

दो गैरकानूनी एक्सचेंजों का पर्दाफाश आइएसआइ से लिंक की आशंका

नई दिल्ली, आइएनएस : जम्मू-कश्मीर की मिलिट्री इंटेलीजेंस और मुंबई पुलिस ने संयुक्त अभियान में दो वीओआइपी (वाईएस और इंटरनेट प्रोटेक्टॉल) एक्सचेंज और सिम बॉक्स का पर्दाफाश किया है। इनका इस्तेमाल रक्षा कर्मियों से जानकारीयां जुटाने के लिए किया गया और आशंका है कि इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ का हाथ है।

गुरुवार को उत्तर प्रदेश में नोएडा और केरल में चंगारामुकुलम में छापे मारे गए थे। सैन्य सूत्रों ने बताया कि इन छापां में दो सक्रिय सिम बॉक्स बरामद हुए। इनमें से प्रत्येक में 100 सिम कार्ड्स के स्टॉक हैं। इसके अलावा दो रूटर, तीन मॉडेम, कई एंटेना, बैटरियां और कनेक्टर बरामद हुए। इस दौरान एक व्यक्ति को चंगारामुकुलम से गिरफ्तार भी किया गया है।

दरअसल, सितंबर 2019 में रक्षा कर्मियों को संदेहास्पद नंबरों से कॉल आई थीं जिनमें अहम रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़ी जानकारीयां मांगी गई थीं। कॉल करने वालों ने अपनी फर्जी पहचान बताई थी इसलिए इनमें आइएसआइ की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। मिलिट्री इंटेलीजेंस और

उत्तर प्रदेश के नोएडा और केरल के चंगारामुकुलम में मारे गए थे छापे, एक गिरफ्तार

छापां में दो सक्रिय सिम बॉक्स भी बरामद किए गए

मुंबई पुलिस की आगे की जांच में उत्तर प्रदेश और केरल में गैरकानूनी वीओआइपी एक्सचेंजों का पता लगा जिनके जरिये पाकिस्तान से आने वाली कॉल्स को लोकल नंबरों पर रूट कर दिया जाता था। इनका इस्तेमाल रक्षा कर्मियों से जानकारीयां जुटाने के लिए किया गया। इन एक्सचेंजों में चीन निर्मित सिम बॉक्स का इस्तेमाल किया गया जिसके सिम कार्ड्स लगाए गए थे। इन सिम बॉक्स में डायनेमिक आइएसआई सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से उन्हें ट्रेक करना कठिन हो जाता है। इसी समय से टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने इसे गैरकानूनी घोषित कर रखा है। अभी तक की जांच में पता चला है कि इन दोनों एक्सचेंजों की वजह से देश के टेलीकॉम विभाग को भी करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।

निवेशक सम्मेलन को मिले 50 करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर राज्य में आयोजित होने वाले अपनी तरह के पहले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के लिए केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। सम्मेलन के प्रचार-प्रसार, आने वाले मेहमानों की आवासीय सुविधा व यात्रा के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपये भी उपलब्ध करा दिए हैं। यह सम्मेलन राज्य के समग्र आर्थिक परिदृश्य को मजबूत बनाने के इरादे से आयोजित किया जा रहा है। इसे पूरी तरह सफल बनाने और दुनियाभर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रशासन हर संभव उपाय कर रहा है।

सम्मेलन अप्रैल के तीसरे या अंतिम सप्ताह में होगा। इसका उद्घाटन सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर स्थित राजकेआइसीसी में और समापन शरदकालीन राजधानी जम्मू में होगा। सम्मेलन के आदर्श वाक्य और थीम- एकसाथलोर, इन्वेस्ट एंड ग्रो है। इसके जरिए दुनियाभर की कनेक्टिविटी, उद्योगपतियों को एक ही मंच पर जमा कर उन्हें केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए

जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों की सैर करेंगे मेहमान

शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों को कश्मीर घाटी और जम्मू के विभिन्न हिस्सों की भी सैर कराई जाएगी। डल झील किनारे स्थित कई होटलों में उनके ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। सम्मेलन के दौरान श्रीनगर में सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त रहेगा ताकि आतंकी किसी भी तरह से गड़बड़ी कर माहौल न बिगाड़ सकें।

तैयार करना है। जम्मू-कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (जेकेटीपीओ) के प्रबंध निदेशक रविंद्र कुमार ने बताया कि वैश्विक शिखर सम्मेलन बीते 70 सालों में जम्मू-कश्मीर में होने वाला अपनी तरह का पहला सम्मेलन है। यह राज्य के आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल देगा। इसकी सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने साथ ही हम इसकी तिथि का एलान करेंगे। पिलहाल, इसमें बुलाए जाने वाले मेहमानों की सूची बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि कनेक्टिविटी और मेरठ के लिसाडी गेट थाना क्षेत्र के फतेहउल्लापुर के दिलनवाज को गिरफ्तार किया था। इनसे 23 लाख रुपये मिले थे। आरोपितों ने पूछताछ में बताया था कि देवबंद के एक गांव निवासी उनके

नई इकाइयों के लिए 20 हजार कनाल भूमि चिह्नित

करीब 20 हजार कनाल जमीन को नई औद्योगिक इकाइयों और निवेश के लिए पूरे केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर राज्य में चिह्नित किया गया है। इस सम्मेलन में निर्माण, आइटटी, पर्यटन, हारस्पिटेलिटी, पर्यटन, दवा, बागवानी, कृषि, फि्लम-मार्गजिन, डेयरी, ऊन व रेशम उत्पादन, दस्तकारी, कौशल विकास, अवसंचना और रियल इस्टेट व शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश को जुटाने का प्रयास किया जाएगा।

कूपर्स और एक्सप्रो को नॉलेज, मीडिया व इवेंट भागीदार के तौर पर शामिल किया गया है। जेकेटीपीओ इस पूरे आयोजन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही है। सम्मेलन में क्या-क्या होगा : सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर अलग-अलग सत्र होंगे। इसके अलावा टेक्नीकल प्रेजेंटेशन, राउंड टेबल चर्चा, भागीदारी में विभिन्न उपक्रम स्थापित करने जैसे विषयों पर भी कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा विभिन्न निवेशकों, उद्योगपतियों और स्थानीय हितधारकों के बीच वन-टू-वन इंटरैक्शन और एमओयू भी तय किए जाएंगे।

आयोजन

मेघालय के शंकर मान थापा ने जीती मैराथन, केन्या के साइमन दूसरे और छत्तीसगढ़ के रामनारायण रहे तीसरे स्थान पर, महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश की डिंपल दूसरे और रेनु तीसरे स्थान पर रही

शांति का पैगाम लेकर नक्सलगाढ़ में दौड़े देश-विदेश के धावक

नईदुनिया, नारायणपुर

छत्तीसगढ़ में बस्तर ने शनिवार को दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया कि लाल आतंक के खोफ से अब वह उबर गया है। शांति का पैगाम देने के लिए धुर नक्सल प्रभावित अबुल्लागढ़ में पीस हॉफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें देश-विदेश के सैकड़ों धावकों ने दौड़ लगाई। पुरुष वर्ग में मेघालय के शंकर मान थापा ने एक घंटा दो मिनट में 21 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग में केन्या की एलीसा एक घंटा 11 मिनट 22 सेकंड में दौड़ पूरी कर अक्वल रही। विजेताओं को नगद राशि और मेडल से पुरस्कृत किया गया।

कई दिनों पूर्व से इस आयोजन की तैयारी चल रही थी। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर बड़ी संख्या में खेलेप्रीमी जुटे हुए थे। पुरुष वर्ग में केन्या के साइमन ने एक घंटा पांच मिनट 20 सेकंड के साथ दूसरा स्थान पांच



छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सल प्रभावित अबुल्लागढ़ में शांति का संदेश देने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन हुआ। दौड़ में पुरुष वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले (बाएं से क्रमशः) मेघालय के शंकर थापा, अफ्रीकी देश केन्या के साइमन और छत्तीसगढ़ के रामनारायण। नई दुनिया

दल्लीराजहरा(छत्तीसगढ़) के रामनारायण एक घंटा आठ मिनट सात सेकंड में दौड़ पूरी कर तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ की डिंपल रही। तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश की हीरेनू ने प्राप्त किया। इन्होंने दौड़ एक घंटा 17 मिनट में

पूरी की। पहले स्थान के विजेताओं को मेडल और एक लाख 61 हजार रुपये की नकद राशि से नवाजा गया। द्वितीय स्थान आने वाले को 61 हजार रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को 31 हजार रुपये की नकद राशि और मेडल से पुरस्कृत किया गया। मैराथन में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही नारायणपुर जिले और औरछा विकासखंड के 10 पुरुष और 10 महिलाओं को भी मेडल और 10-10 हजार रुपये की नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। इस मैराथन दौड़ के लिए छत्तीसगढ़ समेत देश के निवेशन राष््यों और केन्या के छह लोगों सहित 11 हजार से अधिक धावकों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया था। दौड़ सुबह सात बजे जिला मुख्यालय के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैदान से शुरू हुई। विधायक चंदन कश्यम ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ शुरू कराई। कलेक्टर पीएस एम्मा ने अतिथियों का स्वागत किया और मैराथन आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला।

आशा का अर्थशास्त्र



विवेक कौल
इजी मनी ट्राइब्यूनल
के लेखक और
अर्थशास्त्री

सरकारें आशावादी होती हैं। पिछले साल की घोषणाओं पर हुआ काम उनके लिए मायने नहीं रखता है। उनके लिए ज्यादा अहमियत यह बात रखती है कि इस साल और ज्यादा संख्या में कौन-कौन सी नई घोषणाएं की जाएं।

जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आशावादी होना जरूरी होता है, पर अति आशावादिता हमेशा उचित बात नहीं होती है। हाल ही में पेश आम बजट 2020-21 को ही ले लीजिए। इसमें देश की अर्थव्यवस्था की सुस्ती तोड़ने के लिए आशावाद की कमी नहीं है। लेकिन यह कितना तार्किक है, इस बात की पड़ताल बहुत जरूरी है। एक फरवरी को पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को बताया कि अगले वित्त वर्ष में सरकार विनिवेश से दो लाख दस हजार करोड़ रुपये कमाने की आशा रखती है। पिछले साल भी कुछ ऐसी ही कहानी सुनाई गई थी। इस वित्त वर्ष में सरकार विनिवेश से करीब एक लाख पांच हजार करोड़ कमाना चाहती थी। अप्रैल और दिसंबर 2019 के बीच में सरकार केवल अठारह हजार एक सौ करोड़ कमा पाई है। इसलिए इस वर्ष के विनिवेश को देखते हुए यह कहना बनता है कि अगले वर्ष का विनिवेश लक्ष्य बहुत ज्यादा आशावादी है। पिछले साल के बजट भाषण में सीतारमण ने ये कहा था कि चुनिंदा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का रणनीतिक विनिवेश जारी रहेगा। अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतिहास गवाह है कि भारत में रणनीतिक विनिवेश बहुत कम हुआ है। कुछ साल पहले ओएनजीसी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम को खरीदा था और सरकार ने इसे रणनीतिक विनिवेश मान लिया था। असली रणनीतिक विनिवेश तब होता है जब एक सरकारी कंपनी निजी क्षेत्र की कंपनी को बेची जाए। सीतारमण ने ये भी कहा था कि सरकार और भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का रणनीतिक विनिवेश करेगी। ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कहा तो ये भी गया था कि एयर इंडिया की रणनीतिक

विनिवेश की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। ये शुरू तो हो गई है पर जिस गति से चल रही है उसको देख कर ऐसा नहीं लग रहा है कि इस वित्त वर्ष में पूरी हो सकेगी। यहां पर ये भी कहना जरूरी है कि पिछली बार से इस बार एयर इंडिया के बिकने की संभावना कहीं ज्यादा है। इस साल के बजट में सरकार ने आइडीबीआई बैंक को निजी, खुदरा और संस्थागत निवेशकों को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, बेचने का इरादा बनाया है। अब देखना ये होगा कि सरकार ये इरादा पूरा कर पाती है कि नहीं। इतिहास सरकार की मंशा के प्रतिकूल है। इससे भी ज्यादा आइडीबीआई बैंक जैसी लचर स्थिति में है, उसमें अगर निजी निवेशकों ने बैंक को खरीदा तो अपने आप में ये बड़ी बात होगी। सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम का भी थोड़ा हिस्सा विनिवेश करने का मन बना लिया है। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे बीमा निगम के काम करने में पारदर्शिता बढ़ेगी लेकिन, बीमा निगम को शेयर बाजार पर लिस्ट करना आसान नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि इस पर अभी से काम शुरू हो जाए। अमूमन सरकारें विनिवेश पर बजट के दौरान घोषणा करके सो जाती हैं।

वित्त मंत्री ने पिछले बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पास पड़ी जमीन पर सार्वजनिक अवसंरचना (पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर) बनाने की बात भी कही थी। इस पर भी कुछ खास प्रगति नहीं हुई है। इस बार के बजट में सीतारमण ने एक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल की बात की है जो लैंड बैंक की भी जानकारी देगी। अब देखना ये है कि किस हद तक ये प्रस्ताव वास्तविकता में बदलता है। पिछले साल के बजट में ये दावा भी किया गया कि एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की सेवाएं बाकी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्राहकों तक पहुंचाई जाएगी। ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है।

अगर सकल कर राजस्व की ओर नजर डालें तो कुछ ऐसी ही तस्वीर उभर कर सामने आती है। पिछले साल बजट में ये उम्मीद लगाई गई थी कि इस साल के सकल कर राजस्व में 18.3 प्रतिशत का इजाफा होगा। अप्रैल और दिसंबर 2019 के बीच सकल कर राजस्व में 3 प्रतिशत की गिरावट हुई है। इसके बावजूद सरकार ने ये उम्मीद लगाई है कि अगले साल सकल कर राजस्व में 12 प्रतिशत का इजाफा होगा। 12 प्रतिशत बढ़त अपने आप में बहुत ज्यादा नहीं है पर इस साल के कर संग्रह को देखने के बाद ये बहुत ज्यादा लगता है। पर सरकारें आशावादी होती हैं, इसलिए उनके लिए पिछले साल की घोषणाओं पर क्या काम हुआ है, महत्वपूर्ण नहीं होता है। उनके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि इस साल और भी नई घोषणाएं की जाएं।

बजट बाद की बात



जनमत

हा 95% क्या आम बजट 2020-21 के प्रस्तावों को सही तरीके और तय समय के भीतर लागू करके अपेक्षित नतीजे पाए जा सकते हैं?

व्या पिछले बजट के कई अहम प्रस्तावों को लागू न कर पाने के साथ वर्तमान प्रस्तावों को समय से सिरिरे चढ़ाने में सरकार सक्षम है?

हा 85%

नहीं 15%

आपकी आवाज

फिंसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार ने आम बजट वषों न पेश किया हो, लेकिन उस बजट के प्रस्तावों पर एक वित्तीय वर्ष में वो शायद ही खरी उतरी हो। मोदी सरकार पिछले आम बजटों में स्मार्ट सिटी, बेरोजगारी, महंगाई और अन्य आमजन के आधार से जुड़ी योजनाओं-प्रस्तावों पर खरी नहीं उतर पाई है, इसलिए 2020-21 में भी शायद यह खरा उतर पाए। लेकिन पिछले बजट की कमियों को दूर करने और इस बजट को कामयाब करने के लिए मोदी सरकार को सबसे पहले देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ उद्योग-धंधों और आमजन से जुड़े प्रस्तावों पर प्राथमिक आधार पर काम करना होगा, ताकि अगले बजट से पहले यह प्रस्ताव रपतार पकड़ सकें।

राजेश कुमार चौहान

बजट एक साल के लिए होता है। हालांकि मोदी सरकार ने देश को आगे ले जाने के लिए ऐसा बजट तैयार किया है जो कि अगले कुछ वर्षों में देश के विकास को रपतार देगा। हो सकता है इसका असर अभी न दिखे लेकिन आगामी सालों में यह दूरदर्शी बजट देश को विकास की ओर ले जाने वाला सिद्ध होगा।

रत्नाकर

कोई भी नीति या योजना खराब नहीं होती है। सभी नीतियों से फिंसी न किंसी स्तर पर सभी तबके का भला होता है। अगर प्रत्यक्षतौर पर गरीब वर्ग को फायदा पहुंचता है तो अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ अभी तक जाता है। जरूरत इस इतनी है कि योजनाओं को लागू सही तरीके से किया जाय। समय का भी ध्यान रखा जाय।

अभिषेक

किसी बढ़िया योजना-नीति का गलत और किसी खराब योजना-नीति का सही क्रियान्वयन करीब समान नतीजा देते हैं। बजट 2020-21 पेश हो चुका है। अर्थविद बारीक मीमांसा में लगे हैं। जाकी रही भावना जैसी...को चरितार्थ करने वाले भी कम नहीं हैं। अधिकांश की नजर में यह दूरदर्शी बजट है। इसमें अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का अगले एक दशक का खाका है। अर्थव्यवस्था को रफता-रफता गति देते हुए 2024 तक पांच लाख करोड़ डॉलर के क्लब में शामिल करने का इसे आधार माना जा रहा है। सरकार के सामने असली चुनौती आम बजट

2020-21 के प्रस्तावों को प्रभावी रूप से लागू करने की है। ये चुनौती इसलिए भी टेढ़ी खीर दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले बजट की कई अहम घोषणाएं अभी तक सिरिरे नहीं चढ़ सकी हैं। सरकार इस नाकामी पर भले ही दलील दे कि पिछला बजट पेश किए अभी सिर्फ सात महीने ही हुए हैं, लेकिन आम बजट-2020-21 का रंग चोखा दिखाने के लिए उसमें हींग और फिटकरी पर्याप्त मात्रा में डालनी होगी। ऐसे में क्षेत्रवार वर्तमान बजट के प्रस्तावों को लागू कराने के लिए सरकार के सामने चुनौतियों की पड़ताल आज हम सबके लिए बड़ा मुद्दा है।

आसान नहीं लक्ष्य संधान

अर्थव्यवस्था की सुस्ती के बीच पेश किए गए आम बजट 2020-21 में कई दूरदर्शी कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है। देश की वित्तीय बुनियाद को मजबूत रखने के लिए इसके महत्वाकांक्षी प्रावधानों से अधिकांश अर्थवत्ता और रेटिंग एजेंसियां प्रभावित होंगी। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक वर्तमान समस्या के समाधान के लिए इन प्रस्तावों को समयबद्ध और कारगर तरीके से लागू कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा।

उद्योगों को चमकाने की फीकी कलई

सरकार ने सितंबर 2014 में जोर-शोर से 'मेक इन इंडिया' योजना शुरू करते वक्त लक्ष्य रखा था कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका योगदान 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 2022 तक 25 प्रतिशत कर दिया जाए। लेकिन सितंबर 2019 तक यह 17.38 प्रतिशत पर अटका हुआ था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में 'उद्योग, वाणिज्य व निवेश' पर बोलना शुरू किया तो उन्होंने भारत की शाश्वत उद्यमशीलता का उल्लेख किया। जब प्रोत्साहन की बात आई तो मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व सेमी-कंडक्टर पैकेजिंग बनाने पर केंद्रित स्क्रीन तक सिमट गई। इस स्क्रीन में उन्होंने टेक्निकल उपकरणों को भी नथी कर दिया। लेकिन ये उद्योग क्षेत्र तो खुद ही तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्हें शायद किसी प्रोत्साहन की जरूरत नहीं थी।



अनिल सिंह
संपादक -
अर्थकाम.कॉम

लेकिन नहीं बताया कि हमारा निर्यात साल-दर-साल क्यों घटता जा रहा है। अंततः जब उद्योग व वाणिज्य क्षेत्र के लिए बजट आवंटन करना था तो असल आंकड़ा 27,227 करोड़ रुपये तक सिमट गया। यह मौजूदा वित्त वर्ष के 28,608 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 4.82 प्रतिशत कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर इस सरकार की नहीं, देश के लिए भी बड़ी प्राथमिकता है। वित्त मंत्री ने दिसंबर अंत में घोषित पांच साल में 103 लाख करोड़ रूपए निवेश करने के राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का एक बार फिर उल्लेख किया। लेकिन जब कुछ ठोस करने

हिमालयी विनिवेश लक्ष्य

बजट में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपये विनिवेश से जुटने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय घाटे का लक्ष्य संशोधित किया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए यह जीडीपी का 3.8 फीसद रहा जबकि बजट अनुमान में इसे 3.3 फीसद रखा गया था। अब वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इसे जीडीपी का 3.5 फीसद कर दिया गया है। ये आत्मविश्वास बताता है कि सरकार अपने विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के प्रति संकल्पित है। अगर विनिवेश लक्ष्य हासिल हो जाता है तो यह ऐतिहासिक होगा। हालांकि क्रेडिट सुईस की रिपोर्ट सरकार की इस मंशा पर सवाल खड़े करती दिखती है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विनिवेश लक्ष्य 1.05 लाख करोड़ रुपये रखा गया था। जो लक्ष्य से बहुत पीछे रहा है।

लघु बचतों से रकम

वित्त वर्ष 2020-21 और 2019-20 (संशोधित) में प्रत्येक से लघु बचतों से 2.4 लाख करोड़ रुपये जुटाने की बात कही गई है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इस मद में शुरुआती अनुमान 1.3 लाख करोड़ रुपये था। विशेषज्ञ इस पर भी हैरत जता रहे हैं कि क्या वित्तीय घाटे का 30 फीसद हिस्सा इससे पूरा करना संभव होगा।

अप्रत्यक्ष दबाव

बजट 2020-21 को सही तरीके से लागू कराने की चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पूर्व में सरकार की आर्थिक घोषणाओं के लक्ष्य को भी हासिल करना है। रिजर्व स्तर पर रोजगार सृजन, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना, 2024 तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार करना। इन मामलों पर भी वित्तमंत्री को रात-दिन एक करने की जरूरत होगी।

कोई भी नीति या योजना खराब नहीं होती है। सभी नीतियों से फिंसी न किंसी स्तर पर सभी तबके का भला होता है। अगर प्रत्यक्षतौर पर गरीब वर्ग को फायदा पहुंचता है तो अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ अभी तक जाता है। जरूरत इस इतनी है कि योजनाओं को लागू सही तरीके से किया जाय। समय का भी ध्यान रखा जाय।

अभिषेक

सकल टैक्स राजस्व

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सकल टैक्स राजस्व वृद्धि का लक्ष्य 12 फीसद रखा गया है। जबकि बजट में नामिनल जीडीपी वृद्धि दर का लक्ष्य 10 फीसद रखा गया है। जीएसटी संग्रहण में 12.76 फीसद वृद्धि के साथ 6.90 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य है। गोल्टमैन सैक्स का मानना है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रति माह के औसत संग्रहण में 15 फीसद इजाफे की दरकार होगी। आयकर संग्रह में भी जीडीपी के 2.8 फीसद के हिसाब से वृद्धि का अनुमान है। समग्र रूप से अगर नामिनल जीडीपी 10 फीसद सालाना की दर वृद्धि करे और टैक्स राजस्व में 12 फीसद का इजाजा हो तो टैक्स बायोसी 1.2 हासिल करना बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। खासकर उस हालात में जब वित्त वर्ष 2019-20 में ये 0.5 रहा हो।

अमल की हकीकत

बजटीय क्रियान्वयन से संबंधित कागजात को देखें तो पिछले बार की कई अहम घोषणाएं अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई हैं।

लंबी है फेहरिस्त
राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों के लिए मौजूदा स्क्रीम के स्थान पर नई स्क्रीम लागू करने का अभी कैबिनेट नोट तैयार है। रेटेल हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक मॉडल टेनेसी कानून बनाने का एलान किया गया था। इसका का भी नोट तैयार है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही राज्यों को वितरित करने का दावा किया जा रहा है। कमजोर व बंद होने वाले सरकारी उपकरणों के जमीन पर सस्ते आवासीय इकाई बनाने की घोषणा को अमल में लाने के लिए कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है।

सरकार की दलील
वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इसकी वजह बताते हैं कि पिछला बजट पेश किए हुए अभी सिर्फ सात महीने हुए हैं। ऐसे में कई ऐसी घोषणाएं हैं जिनके प्रारूप को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है या कई ऐसे घोषणाएं हैं जो कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। प्रस्ताव: वित्त मंत्री ने पिछले बजट में नागरिक उड्डयन सेक्टर, मीडिया (एनीमेशन) व बीमा सेक्टर को विदेशी निवेश के लिए और खोलने का एलान किया था। वर्तमान स्थिति: बजट प्रपत्रों के मुताबिक अभी इस बारे में विभिन्न मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श शुरू ही हुआ है। जैसे मीडिया में इतिवृत्ती बढ़ाने को लेकर सूचना व प्रसारण मंत्रालय के साथ विमर्श हुआ है लेकिन अंतिम फैसला कब होगा इसका पता नहीं है। इसमें सिर्फ एक घोषणा सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर के लिए स्थानीय सोर्सिंग नियमों को बदलने का पालन किया गया है। प्रस्ताव: सूचीबद्ध कंपनियों के लिए न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग की सीमा मौजूदा 25 फीसद से बढ़ा कर 35 फीसद करना। वर्तमान स्थिति: सभी सरकारी उपकरणों का कम से कम 25 फीसद शेयर निर्गम करने की घोषणा पर भी अमल की शुरुआत नहीं हुई है।

...यानी चौगुनी मशक्कत

संटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनॉमी के अनुसार साल 2013 से 2019 के बीच हमारे देश के किसानों की आय में लगभग 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है। यदि इसमें किसानों द्वारा बाजार से खरीदी जाने वाली सामग्री पर उनके द्वारा किए गए अधिक खर्च की गणना कर लें तो मेरे अनुमान से आय में वृद्धि 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी। इसके सामने, सरकार ने वायदा किया है कि मार्च 2023 तक किसान की आय दोगुनी कर दी जाएगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसान की आय में लगभग 30 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि होना जरूरी है।

वित्त मंत्री ने किसानों द्वारा किए जा रहे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हासिल करने पर जोर दिया है जैसे संतुलित फर्टिलाइजर के प्रयोग और सोलर पंप-सेट के उपयोग से। यह कदम सही दिशा में है लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कृषि पदार्थों के मूल्यों में लगातार गिरावट आ रही है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने वाली तकनीकें निरंतर विकसित होती जा रही हैं। जैसे ट्यूबवेल, टिश्यू कल्चर और रासायनिक फर्टिलाइजर। लेकिन खाद्य उत्पादों की खपत में समानांतर वृद्धि नहीं हो रही है क्योंकि विश्व की जनसंख्या में उछाल आ गया है। फलस्वरूप कृषि उत्पादों की सप्लाई बढ़ रही है जबकि डिमांड कम हो बढ़ रही है। तदनुसार कृषि उत्पादों के दाम गिर रहे हैं। अतः सरकार के प्रयास से जो कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी उससे किसान की आय में वृद्धि होना कम ही संभव है क्योंकि इन उत्पादों के बाजार मूल्यों में उतनी ही गिरावट आने की संभावना है। अपने देश में ही कई अनुभव उपलब्ध हैं जब किसानों को अपने बड़े हुए उत्पादन को खेत में ही बर्बाद करना पड़ा था। चूंकि बाजार में फसल के दाम गिर गए थे। लिहाजा उत्पादन में वृद्धि से अक्सर किसान को नुकसान होता है। इस परिस्थिति में उत्पादन बढ़ाने के स्थान पर माल की क्वालिटी में सुधार करके इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने कहा है कि हॉर्टिकल्चर के कलस्टर बनाकर हर जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा जाएगा। इस कदम को पूरी ताकत से लागू करना चाहिए। भारत के पास विविध प्रकार की जलवायु की अमूल्य संपदा है। हमारे देश में हर मौसम में किसी क्षेत्र में गर्मी तो किसी क्षेत्र में ठंड होती है। अतः ट्यूनिंग जैसे फूलों का निर्यात हम बंध कर सकते हैं। नीदरलैंड जैसे देश में ट्यूनिंग फूलों की खेती से अपार आय होती है। ट्यूनीशिया जैतुन के फलों को और फ्रांस वाइन को पूरे विश्व में सप्लाई करता है। हम भी ऐसा कर सकते हैं लेकिन हर जिले में किस उत्पाद को बढ़ावा जाए इसके लिए गहन रिसर्च करना जरूरी है। इस दिशा में हमारी प्रयोगशालाएं और



मरत
सुनसुनवाला
वरिष्ठ अर्थशास्त्री

किसानों की आय दोगुनी करने का एक मात्र उपाय है कि हर जिले की ळह फसल जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग हो, उसे चिन्हित किया जाए फिर उसके उत्पादन एवं मार्केटिंग की व्यवस्था पर प्रभावी गैहनत हो।

विश्वविद्यालय लचर हैं। किसी किसान ने बताया कि उन्होंने अपनी स्थानीय युनिवर्सिटी के बताए अनुसार अपने खेत में कीनू के वृक्ष लगाए। जब फल हुए तो उनका आकार छोटा था। जब युनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे तो प्रोफेसर ने कहा कि हां पाई हमारे भी वृक्ष सफल नहीं हुए। यानि प्रोफेसर ने बिना सोचे समझे ही संस्तुति कर दी थी। इस प्रकार की रिसर्च से किसानों को भयंकर घाटा लगता है और नए उत्पादों में प्रवेश करने से पहले वे हजारों करोड़ों की रिसर्च से किसानों को भयंकर घाटा लगता है। इस प्रकार हर 5 जिलों के बीच विशेष उत्पाद पर रिसर्च करने के केंद्र बनाने होंगे। तब इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। बजट में दूसरा स्वागत योग्य कदम किसानों की परती भूमि पर सोलर विद्युत उत्पादन कर ग्रिड से जोड़ने की समस्याएं हैं जिन्हें दूर करना होगा। घिसी पिटी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने से किसान की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करना कठिन होगा। एक मात्र उपाय है कि हर जिले के लिए जो फसल उचित हो और जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग हो उसे चिन्हित किया जाए फिर उत्पादन एवं मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए अन्यथा जैसे पिछले दस वर्षों में किसानों की आय 5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है वैसे ही बढ़ती रहेगी।



दैनिक जागरण

कड़ी मेहनत देर से ही सही परंतु फल अवश्य देती है

मध्यस्थता का विचार

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने मुकदमों से पहले मध्यस्थता को अनिवार्य बनाने के लिए नए कानून की जो जरूरत जताई वह कोई नई बात नहीं है। सच तो यह है कि इसके पहले स्वयं प्रधान न्यायाधीश ने ही पिछले वर्ष इस तरह के किसी कानून की आवश्यकता पर बल दिया था। ऐसा कोई कानून इसलिए आवश्यक हो गया है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य और निवेश के कई मामले अदालतों तक पहुंचते हैं और वे वहां लंबा समय लेते हैं। बेहतर व्यापारिक-औद्योगिक गतिविधि और निवेश के लिए उपयुक्त माहौल के निर्माण के लिए मुकदमेबाजी से पहले मध्यस्थता संबंधी कानून का निर्माण वक्त की जरूरत बन गया है और इसे पूरा किया ही जाना चाहिए। उचित यह होगा कि इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार सक्रिय हो, लेकिन इसी के साथ खुद न्यायपालिका को भी देखना होगा कि उसके स्तर पर मध्यस्थता का निर्वहन कैसे हो सके। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि स्वयं उच्चतर न्यायपालिका के स्तर पर कई ऐसे मामले वर्षों तक खिंचते रहते हैं, जिनका निस्तारण कहीं अधिक शीघ्रता से हो जाना चाहिए। चूंकि व्यापार, वाणिज्य और निवेश के अदालती मामलों का निपटारा होने में देरी होती है तो इससे न केवल भारतीय न्यायपालिका की छवि प्रभावित होती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय निवेश संबंधी गतिविधियों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक ऐसे समय जब कारोबारी माहौल सुगम बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास हो रहे हैं तब इसका कोई औचित्य नहीं कि मुकदमेबाजी से पहले मध्यस्थता के कानून की जो आवश्यकता महसूस की जा रही है उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा न किया जाए।

यह भी समय की मांग है कि सामान्य अदालती मामलों का निस्तारण जल्द करने की कोई प्रक्रिया विकसित की जाए। इससे अधिक निराशाजनक और कुछ नहीं हो सकता कि अदालती मामलों के समयबद्ध निपटारे के लिए एक लंबे अरसे से बातें हो रही हैं, लेकिन इस दिशा में जितनी तेजी से आगे बढ़ा जाना चाहिए वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। धीमी, थका देने वाली और जटिल अदालती प्रक्रिया का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है, इसकी ताजा और शर्मनाक बानगी दिल्ली के वसंत विहार दुकर्म मामले में देखी जा सकती है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय तक अपना फैंसला सुना चुका है, लेकिन गुनहगारों के लिए अदालती विकल्प खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यह स्थिति तब तक दूर नहीं होने वाली जब तक न्यायिक सुधारों की रफ्तार तेज नहीं की जाती। न्यायपालिका और विधायिका को मिलकर वह राह निकालनी चाहिए जिससे न केवल अदालतों पर मुकदमों का बोझ समाप्त हो, बल्कि लोगों के लिए समय पर न्याय मिलना भी सुनिश्चित हो।

वसूली पर लगाम

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने अपने विभाग के अंतर्गत ही कार्य करनेवाले ड्रग इंस्पेक्टरों के विरुद्ध दवा दुकानदारों से वसूली के आरोप लगाए हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी ड्रग इंस्पेक्टर ऐसे नहीं हैं। फिर भी, मंत्री का यह आरोप काफी गंभीर है, क्योंकि दवा का व्यवसाय सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा होता है। ऐसे में यदि वसूली का धंधा पनप रहा है तो इसपर लगाम जरूरी है। दवा दुकान ड्रग इंस्पेक्टरों को लाभ पहुंचाएंगे तो वे कहीं न कहीं अपना लाभ भी देखेंगे। यह लाभ लोगों के स्वास्थ्य को ही नुकसान पहुंचाएगा। मंत्री ने ड्रग इंस्पेक्टरों के ऐसे कारनामे पर सख्ती से रोक लगाने की भी बात कही है। यह एक अच्छी पहल कही जा सकती है, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी यह भी है कि वे ऐसी वसूली पर रोक लगाने की दिशा में तत्काल ठोस कदम उठाएं। यदि वसूली की जानकारी होने के बाद भी ऐसा चलता रहता है तो कहीं न कहीं इसके लिए वे भी जिम्मेदार माने जाएंगे। यह भी सही है कि स्वास्थ्य विभाग में अभी तक औषधि प्रशासन के कार्यों की नियमित समीक्षा नहीं होती। इसी का नतीजा है कि इस क्षेत्र में मनमानी होती रही है। औषधि प्रशासन पर निगरानी रखने के लिए कोई पारदर्शी तंत्र भी विकसित नहीं है। दवा दुकानदार भी ऐसी वसूली की शिकायत सरकार स्तर पर नहीं करते। इसका कारण यह है कि वे भी कानूनों और नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करते। उनमें यह भी डर व्याप्त होता है कि किसी न किसी नियम के उल्लंघन में उनके लाइसेंस पर ही आफत न आ जाए। दवा दुकानों में फार्मासिस्ट का होना अनिवार्य है, लेकिन कई दुकानों में फार्मासिस्ट उपलब्ध नहीं हैं। एक-एक फार्मासिस्ट कई दवा दुकानों के लिए काम करते हैं। इस पहलू को हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा है। जो भी हो, उम्मीद की जा सकती है जब मंत्री ने बात छोड़ दी है तो वे औषधि के वितरण, प्रबंधन और बाजार पर नियमित निगरानी का तंत्र भी विकसित करेंगे। दवा विक्रेताओं को भी नियमों का पालन कर इस पहल में सहयोग करना चाहिए, ताकि किसी तरह की वसूली की गुंजाइश ही न रहे।

स्वास्थ्य मंत्री ने दवा दुकानों से ड्रग इंस्पेक्टरों द्वारा वसूली का गंभीर मसला उठाया है। यह सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। जरूरत तत्काल प्रभावी कदम उठाने की है



संजय गुप्त

संसद से पारित कानून के खिलाफ सड़क पर उतरने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने यही करना शुरू कर दिया है

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में विपक्ष और खासकर कांग्रेस के आरोपों की जिस तरह ध्वजिया उड़ाते हुए उसके दुष्प्रचार को बेनकाब किया उसके बाद कम से कम उन लोगों को तो वास्तविकता का आभास हो ही जाना चाहिए जो नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर अंदेश से ग्रस्त हैं या फिर उसके खिलाफ धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने न केवल यह नए सिरे से साफ किया कि इस कानून से किसी भारतीय नागरिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बल्कि यह भी बताया कि इसमें संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री के साथ अन्य अनेक नेताओं के उन बयानों का जिक्र किया जिनमें पूर्वी पाकिस्तान से परेशान होकर भारत में शरण लेने आए लोगों को राहत देने की जरूरत जताई गई थी। उन्होंने 1950 में असम के मुख्यमंत्री को लिखी गई नेहरू जी को उस चिट्ठी का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) से आए शरणार्थियों और प्रवासियों में अंतर करना होगा। इसी के साथ उन्होंने नेहरू-लियाकत समझौते का भी उल्लेख किया, जिसमें दोनों देशों ने अपने-अपने देश के अल्पसंख्यकों की चिंता करने की हामी भरी थी। चूंकि पाकिस्तान ने इस समझौते का पालन नहीं किया इसलिए वहां के अल्पसंख्यक प्रताड़ित

होकर भारत आते रहे। यह सिलसिला आज भी कायम है, लेकिन विपक्ष जानबूझकर इसकी अनदेखी करना पसंद कर रहा है। वह यह समझने को भी तैयार नहीं कि पाकिस्तान में दलितों के साथ किस तरह छल हुआ और उसके चलते वहां मंत्री रहे जोगेंद्र नाथ मंडल को किस तरह भारत आना पड़ा? पाकिस्तान में आज भी अल्पसंख्यक प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन हमारे विपक्षी दल कुछ कहने को तैयार नहीं। आखिर क्यों?

कांग्रेस सीएए के प्रति किस तरह अंध विरोध से ग्रस्त है, इसका उदाहरण है उसके शासित राज्यों द्वारा इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाना। यह संविधान विरोधी आचरण तब किया गया जब नागरिकता के मामले में राज्य सरकारों की कहीं कोई भूमिका नहीं। नागरिकता कानून संबंधी संशोधन विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में व्यापक बहस हुई थी। इसमें सभी दलों ने भाग लिया था। संसद से पारित कानून के खिलाफ सड़क पर उतरने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने यही करना शुरू कर दिया। इन दलों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ है। कुछ गैर राजनीतिक संगठन भी इसी काम में लग गए। इसी के चलते धरने-प्रदर्शन भी आयोजित होने लगे। दिल्ली में शाहीन बाग इलाके में चल रहा धरना तो एक नाकाबंदी है। इस धरने से लाखों लोग परेशान हो रहे



अवधेश राजपूत

हैं, लेकिन उसे समर्थन दे रहे विपक्षी दलों को इसकी परवाह नहीं। उनके इसी रवैये को देखते हुए प्रधानमंत्री ने यह कहा कि यदि संसद से पारित कानून के खिलाफ जनता को भड़काया जाएगा और हिंसा को आंदोलन का अधिकार मान लिया जाएगा तो लोकतंत्र का चलना मुश्किल होगा।

कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि आखिर नेहरू को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के साथ समझौता क्यों करना पड़ा? इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री को यह क्यों कहना पड़ा कि पूर्वी पाकिस्तान के पीड़ित अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए? क्या इससे खराब बात और कोई हो सकती है कि 1964 में तो पड़ोसी देशों में हो रहे धार्मिक उत्पीड़न पर चिंता जताई गई, लेकिन आज ऐसा करने से न केवल बचा जा रहा है, बल्कि इस उत्पीड़न के शिकार लोगों को राहत देने के लिए बनाए गए कानून का विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री ने यह सही सवाल पूछा कि क्या नेहरू और शास्त्री ने ऐसे बयान इसलिए दिए,

क्योंकि वे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे? कम से कम कांग्रेस को यह तो स्मरण ही होगा कि मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में नेता विपक्ष के तौर पर बांग्लादेश जैसे देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को लेकर क्या मांग की थी? कायदे से उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी इस मांग के अनुरूप कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने दस साल तक कुछ नहीं किया। इससे भी हैरानी की बात यह है कि अब जब मोदी सरकार ने वही काम किया जैसा वह चाह रहे थे तो कांग्रेस विरोध कर रही है। यह तो एक तरह से खुद के खिलाफ खड़ा होना है।

हालांकि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के दोहरे मानदंडों को बेनकाब करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, लेकिन लगता नहीं कि उसके रवैये में कोई सुधार होगा। इसके भी आसार कम ही हैं, जो लोग सीएए के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वे भी अपनी जिद छोड़ेंगे, क्योंकि उनका विरोध प्रायोजित है और उसका मकसद भी कुछ और है। शाहीन बाग और ऐसे ही जो धरने देश के अन्य हिस्सों में चल

response@jagran.com

प्रिय लेखक के अवसान की पीड़ा



हार्स्य-कंग्य

साधक जी गहरे सदमे में थे। उनके प्रिय लेखक का निधन हो गया था और यह खबर उन्हें पूरे बतौरस मिनट की देरी से मिली।

अब तक तो सोशल मीडिया में कई लोग बाजी मार ले गए होंगे। फिर भी उन्होंने खुद को संभाला। ऐसा करना जरूरी था, अन्यथा क्षति और व्यापक हो सकती थी। पहले तो उन्होंने इस खबर की पुष्टि की। इस बार पक्की सूचना थी कि उनके 'प्रिय लेखक' साहित्यिक यात्रा के बजाय अंतिम यात्रा पर ही निकले हैं। इससे इत्मिान हुआ। पहले वह दो बार 'फेक-न्यूज' से गच्चा खा चुके थे। वरिष्ठ लेखक से नजदीकी दिखाने की होड़ में उनके स्वगिरिहण से पहले ही सोशल मीडिया पर वह उनका 'शोकोत्सव' मना चुके थे। अचानक लेखक की निगाह जब अपनी ही 'जीवित श्रद्धांजलि' पर पड़ी तो गड़बड़ हो गई।

उस सबक को याद कर साधक जी तुरंत सोशल मीडिया पर आए। वहां कोहराम मचा हुआ था। एक नवोदित कवि 'टूट' कर रहा था। उसने लेखक जी के शव के साथ ही सेल्फी ले ली थी। उसे वायरल होते देख उनका दिल बैठ गया, पर उन्हें अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। ऐसे झटके खाने का उनका तजुबा रहा है। उन्होंने जल्दी से पुराने अलबम खंगाले। कभी वह लेखक के बड़े खास थे। सो उनके साथ खिंचे गए चित्रों का खासा स्टॉक था। उन्होंने एक दुर्लभ फोटो को 'प्रिय लेखक से आखिरी आशीर्वाद का सौभाग्य इस नाचीज को' कैप्शन के साथ परोसा ही था कि पूरी



संतोष त्रिवेदी

उन्हें जो सम्मान नहीं मिले, हम सब उन्हें हथियाने का संकल्प लेते हैं। यही पुण्यात्मा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी

साहित्यिक बिरादरी उस पर टूट पड़ी। लोगों ने अंततः उनके दुख को मान्यता दे दी। वह बराबर हर श्रद्धांजलि को 'लाइक' कर रहे थे। इससे उनका दुख लगातार 'अपडेट' हो रहा था। उन्होंने एक घंटे में ही उस नवोदित कवि के दुख को पटखनी दे दी।

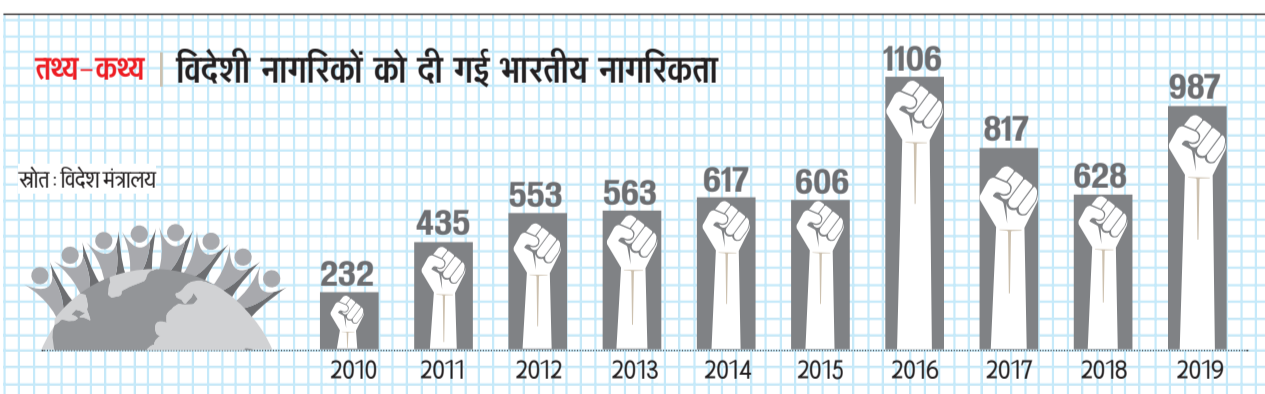
स्वर्गवासी लेखक की ऐसी श्रद्धांजलि देखकर कई वरिष्ठ भीतर ही भीतर 'कलपने' लगे। सोचने लगे कि साहित्य में ऐसे जीवित रहने से अच्छा है कि इस तरह की मौत ही आ जाए। कम से कम एक दिन के लिए ही सही, वे चर्चित तो होंगे। पर प्रकटतः यह सब तो नहीं कह सकते थे। आखिर लोकलाज भी कोई चीज होती है। साहित्यकार होने के नाते सभी पर्याप्त रूप से संवेदनशील थे। जिस लेखक का शोक इतना वायरल हो चुका हो, उस पर कुछ तो लिखना होगा। यही सोचकर एक वरिष्ठ ने मर्मांतक संस्मरण लिखा, 'वह कहते रहे कि साहित्य की सद्गति होने तक लिखते रहेंगे। अब किसको पता था कि साहित्य से पहले

उनको ही सद्गति मिलेगी। जीवन भर वह न जाने कहां-कहां पड़े रहे, किस-किसको पकड़े रहे! इश्वर अब उन्हें अपने चरणों में स्थान दे!'

दूसरे वरिष्ठ उनसे भी ज्यादा आहत दिखे जो स्वर्गीय लेखक के समकालीन थे। पिछले महीने ही 'पचहत्तर पत्र' का उत्सव मनाया था। उन्होंने कहा, 'मेरा उनसे गहरा लगाव था। जब वह नवोदित लेखक थे तब मेरे ही किरायेदार थे। किराया तो छोड़िए, हमने कभी भी उनको उधारी देने से मना नहीं किया। मांगने के मामले में वह शुरू से ही उदार थे। यहीं से साहित्य में 'उदारवाद' की नींव पड़ी। ऐसी पूंजी के बिना साहित्य आज स्वयं को अनाथ महसूस कर रहा है।'

ऐसे-ऐसे संस्मरण पढ़कर साधक जी घबराते लगे। नवोदित कवि को तो वह निपटा चुके थे, पर ये तो उनकी ही तरह प्रतिभा से 'लैंस' थे। उन्होंने अतिरिक्त दुख से आखिरी वार किया, 'अपने प्रिय लेखक की याद में हम हर वर्ष 'लेखक उठाओ सम्मान' देंगे। इसके लिए हमारे साहित्यिक गिरोह के दस सदस्य त्याग के लिए तैयार हैं। ये अगले दस वर्षों तक एक-दूसरे को यह सम्मान लेते-देते रहेंगे। इससे साहित्य में सद्भाव भी बना रहेगा। जीवन भर उनको जो सम्मान नहीं मिले, हम सब उन्हें हथियाने का संकल्प लेते हैं। उस पुण्यात्मा के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।'

उधर लेखक जी की आत्मा स्वर्ग से वह देखकर तड़प रही थी कि आभासी दुनिया में मिले इतने 'सम्मान' को काश उनकी रूह भी 'लाइक' कर पाती! response@jagran.com



कोरोना वायरस वैक्सीन की तलाश

मुकुल व्यास

चीन में महामारी फैलाने वाले नॉवेल कोरोना वायरस को रोकने के लिए दुनिया के कई रिसर्चर वैक्सीन बनाने में जुट गए हैं और इस दिशा में उन्हें कुछ सफलता भी मिल रही है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक एसएस वासन और उनकी टीम ने कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में कामचोलेथ साइटोफिक एंड इंस्ट्रुयल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (सीएसआइआरओ) की कड़ी सुरक्षा वाली प्रयोगशाला में वायरस का पहला बैच विकसित कर लिया है। चीन के बाहर तैयार किया गया यह पहला बैच है। इससे गहन रिसर्च के लिए पर्याप्त स्टॉक जमा हो गया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के डॉहटी इंस्टीट्यूट के शोधार्थियों ने मानव नमूने से वायरस को अलग कर लिया था। ऑस्ट्रेलियाई शोधार्थियों को उम्मीद है कि वायरस के खिलाफ वैक्सीन छह महीने के भीतर तैयार हो जाएगी। चीनी वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वायरस का आनुवंशिक नक्शा सार्वजनिक किए जाने के बाद नए वैक्सीन की खोज में तेजी आ गई है। बड़ी दवा

ऑस्ट्रेलिया में इस वैक्सीन को तैयार करने में जुटे शोधार्थियों का कहना है कि अगले छह माह में वे इसे विकसित कर सकेंगे

कंपनियों और दूसरे रिसर्चर दल वायरस के खिलाफ कारगर वैक्सीन विकसित करने के लिए अलग-अलग एग्रीच अपना रहे हैं। अमेरिका में मेरीलैंड स्थित नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के शोधार्थियों का कहना है कि उन्होंने कोरोना वायरस के महत्वपूर्ण हिस्से का एक संशोधित रूप तैयार कर लिया है जो शरीर को वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस टीम की प्रमुख किञ्जमेकिया कॉबेट का कहना है कि उनका दल वायरस के एक खास प्रोटीन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उनकी रिसर्च चीन में 2001 में प्रकट हुई महामारी पर किए गए अध्ययन पर आधारित है। कोरोना वायरस की ही एक दूसरी किस्म ने यह बीमारी फैलाई थी। समझा जाता है कि

वायरस की यह किस्म वुहान के वायरस से मिलती-जुलती थी।

वुहान वायरस की संरचना को समझने के लिए ऐसे गैर गैर की कल्पना की जाए जिसकी सतह पर चारों तरफ लालें लगी हों। कौनों जैसी संरचना की होड़ में उनके स्वगिरिहण से मुख्य हथियार हैं। इन्हें स्पाइक प्रोटीन भी कहा जाता है। ये प्रोटीन फेफड़े की झिल्ली में मौजूद एसीई 2 रिसेप्टर के साथ जुड़ जाते हैं। एक तरह से ये रिसेप्टर कोशिका की दीवार के प्रवेशद्वार हैं, जिनके जरिये वायरस शरीर में दाखिल हो जाता है। कॉबेट ने बताया कि उनकी टीम इस महत्वपूर्ण प्रोटीन का संशोधित रूप तैयार करने के लिए एंटीबॉडीज निर्मित करने के लिए प्रेरित करेगा। कॉबेट ने कहा कि कोरोना वायरस श्रेणी के वायरस रोगाणुओं के बड़े परिवार से संबंध रखते हैं। इनमें से सात वायरस मनुष्यों को संक्रमित करते हैं। बहरहाल इस मोर्चे पर अभी काफी शोध किए जाने की आवश्यकता है।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

सियासत के अनूठे रंग

दिल्ली विधानसभा चुनाव में सियासी रंगों में बदलाव के कई नमूने देखने को मिले। इसमें सबसे दिलचस्प यह रहा कि राजनीतिक रूप से मुखर बॉलीवुड के कई सितारे आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए लगातार अपनी तरफ से पेशकश करते रहे, मगर इन सितारों की भीड़ जुटाऊ क्षमता और स्टार वैल्यू के बाद भी प्रचार अभियान में शामिल होने के लिए की गई इनकी पेशकश को नजरअंदाज कर दिया गया। बताया जाता है कि प्रचार की पेशकश करने वाले ऐसे चेहरों में स्वरा भारस्कर, तापसी पन्नू और ऋचा चड्ढा जैसे सितारे थे। मगर आप नेतृत्व ने नागरिकता कानून और एनआरसी की मुखालफत करने वाले इन सितारों को प्रचार अभियान से जोड़ने का जोखिम नहीं लिया। चुनाव अभियान को भाजपा की राट्टवारी पिच पर ही सिमट जाने के खतरों के मद्देनजर आप ने नरम हिंदुत्व की राह पर चलने के लिए ऐसे सितारों से परहेज किया जबकि पिछले चुनाव में बॉलीवुड के कई सितारे आप के प्रचार की ताकत रहे थे।

अति उत्साहित अधिकारी

नेता अपने विरोधियों पर हमले का मौका नहीं छोड़ते, लेकिन नौकरशाही से उम्मीद की जाती है कि वह बिना पूर्वाग्रह तथ्यों के आधार पर फैसले करें। खासतौर पर जांच एजेंसियों के अधिकारियों के लिए यह जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, मगर कुछ जांच एजेंसियों के अधिकारी राजनीतिक आकाओं को खुश करने के अति उत्साह में ऐसे फैसले कर लेते हैं, जो राजनीतिक रूप से उनके आका के लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है। पिछले दिनों के लिए ही एक एजेंसी से चुनाव के ठीक पहले एक

राजरंग

विरोधी राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता के खिलाफ अनौपचारिक रूप से खबरें लौक कीं। अब माना जा रहा है कि चुनाव के ठीक पहले बिना ठोस सबूतों के ऐसे आरोप लगाने का दांव उलटा पड़ गया।

एकीकरण की चुनौती

केंडर मर्जर के निर्णय को लेकर जबसे पीएमओ ने रेल मंत्रालय की क्लास लगाई है, मंत्रालय को मानो सांप सूंध गया है। यही नहीं, जिस तरह यूनियनों ने इस निर्णय का विरोध किया है और एक के बाद एक समूह इस फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उससे इस निर्णय के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। यही नहीं, विरोध के सबसे ज्यादा सुर सिविल सेवा से आने वाले उन अफसरों की ओर से सुनाई दे रहे हैं जिन्हें भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि यही वह तबका है जो केंडर एकीकरण से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। इस वर्ग के अफसरों कहना है कि अभी तक सिविल सेवा में आइएएस, आइपीएस और आइएफएस के बाद अफसरों की पहली पसंद रेलवे रहा है, लेकिन अब शायद ही कोई रेलवे में आना चाहेगा। इससे रेलवे में बेहतरीन प्रतिभावान अफसरों की कमी हो जाएगी। दूसरी ओर इंजीनियरिंग के अफसरों की भरमार होने से सर्वोच्च स्तर पर प्रशासकीय एवं प्रबंधकीय क्षमता प्रभावित होने का खतरा है। केंडर एकीकरण से विशेषज्ञताएं प्रभावित होंगी। साथ ही नॉन-गजेटेड स्तर पर विभागों खाई कायम रहेगी। गुप्ता कमेटी ने भी इन्होंने वजहों से केंडर एकीकरण के विचार को खारिज कर दिया था, लेकिन हालिया निर्णय

लेते वक्त इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया गया। इन हालात में केंडर एकीकरण समिति के आगे चुनौतीपूर्ण परिस्थिति तो पैदा हो ही गई है।

जातीय बयान पर घिरे नेताजी

भाजपा से टिकट न मिलने पर चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का हाथ थामने वाले नेताजी को जातीय टिप्पणी महंगी पड़ गई। आखिरकार वह अपनी पार्टी में ही अलग-थलग पड़ गए। हुआ यह है कि मर मॉडर ट्रस्ट के गठन की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता उदित राज को पता भी क्या सूझा कि उन्होंने जातीय संख्या का हवाला देते हुए इसमें दलितों के कम प्रतिनिधित्व पर सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि दलित ब्राह्मणों से संख्या में ज्यादा है। फिर भी ऐसा क्यों? उनका यह ट्वीट ब्राह्मणों और दलितों के बीच कटुता पैदा करने वाला था। फिर क्या था कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उदित राज पर ट्वीट के जरिये ही मोर्चा खोल उन्हें सार्वजनिक रूप से नसीहत दे डाली। इनमें जितिन प्रसाद और राजीव त्यागी सबसे आगे रहे। इन पुराने दिग्गजों ने अपने सहयोगी उदित राज को सोशल मीडिया पर ही खरी-खरी सुनाने में वक्त जाना नहीं किया। अब शायद उदित राज इससे कोई सबक लें।

वैचारिकी

बंगाल

टकराव से किनारा

बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता सरकार के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है, परंतु जिस तरह से राज्यपाल विधानसभा के बजट सत्र के अभिभाषण से पहले तेवर दिखा रहे थे उससे सिपासी गलियारों में चर्चा गर्म थी कि बजट सत्र की शुरुआत टकराव के साथ होगी और वह भी राज्यपाल एवं सरकार के बीच। इसकी तैयारी भी सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने भी कर रखी थी। क्योंकि राज्यपाल ने गुरुवार को ही संकेत दे दिए थे कि वह अपनी मन की बातें सदन में रखेंगे, लेकिन शुक्रवार को राज्यपाल ने टकराव से किनारा कर लिया और सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने भी सदन एवं संवैधानिक प्रमुख की गरिमा को पूरी तरह से सम्मान दिया।

हालांकि राज्यपाल भले ही अभिभाषण दे रहे थे, लेकिन उनके कम में कहीं न कहीं टीस जखर उठी होगी, क्योंकि उन्हें राज्य सरकार के तैयार किए गए भाषण को बिना किसी फेरबदल के पढ़ना पड़ा। जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ काफी तल्ख टिप्पणियां थी। जैसे ‘असहिष्णुता, धार्मिक कट्टरता और नफरत अब इस देश के नए मानक हो गए हैं। सभी तरह की असहमतियों को अस्वीकार कर देना अब देशभक्ति के नाम पर नया फैशन बन गया है।’ यही नहीं सीएए, एपीआर और एनआरसी को लेकर भी राज्य सरकार ने जो बातें लिखी थीं उसे भी बिना किसी

हिचक के पढ़कर सरकार के साथ किसी भी तरह के टकराव की संभावनाओं को भी समाप्त कर दिया। राज्यपाल ने कहा, राज्य सरकार एपीआर, एनआरसी और सीएए के जरिये लोगों में फूट डाले जाने के सख्त खिलाफ है। वहीं राज्यपाल ने ममता सरकार की उपलब्धियां एवं तमाम योजनाओं का गुणगान से लेकर राज्य की उन्नत कानून व्यवस्था, सरकार संचालित योजनाओं का बखान भी किया, जिस पर कुछ दिन पहले उन्होंने अलग राय व्यक्त किया था।

हालांकि शुक्रवार दोपहर डेढ़ बजे तक ऐसा लग रहा था कि धनखड़ भी केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के नक्शे कदम पर आगे चलेंगे। धनखड़ के तेवर को देखते हुए राज्य सरकार ने पहले ही टीवी चैनलों के कैमरों एवं प्रिंट मीडिया के फोटोग्राफरों के सदन में कैमरे के साथ प्रवेश पर रोक लगा दी थी। ताकि यदि कोई टकराव जैसे हालात सदन में पैदा हों तो उसकी वीडियो फुटेज या फिर फोटो मीडिया को नहीं मिल सकें। वहीं सदन में पहुंचे तृणमूल विधायक सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध वाले बेज, सिर पर पट्टी और गले में संबिधान वाले पोस्टर पहन रखे थे। जिसे देखकर समझ में आने लगा था कि राज्यपाल यदि अपने मन की बातें करते हैं तो विरोध शुरू हो जाएगा, परंतु राज्यपाल बड़े ही सहज तरीके से सदन में पहुंचे और भाषण दिया। हालांकि अभिभाषण में सिर्फ एक बार हमारी सरकार का इस्तेमाल किया। वहीं सिर्फ मुख्यमंत्री शब्द बोले। ममता का नाम भाषण में कहीं नहीं था। खैर, जो भी हो केरल विधानसभा जैसे हालात बंगाल में नहीं बना और टकराव टाल गया।

दखल जाए तो दोनों पक्षों ने टकराव टाल कर समझदारी का परिचय दिया है। इससे प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर शांति का वातावरण बनेगा और विकास की राह प्रशस्त होगी।

उत्तराखंड में चिह्नित होंगे हिम तेंदुओं के संभावित स्थल

केदार दत्त, देहरादून

उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में पहली बार होने जा रही हिम तेंदुओं की गणना के लिए वन महकमे ने कमर कस ली है। सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत मार्च से प्रस्तावित गणना से पहले स्थानीय ग्रामीणों की मदद से हिम तेंदुआ संभावित स्थल चिह्नित किए जाएंगे। इस सिंचालित में गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद वन्यजीव विहार से लेकर अस्कोट अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले और इन संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से सटे गांवों के निवासियों के साथ बैठकों का क्रम शुरू किया जाएगा।

उच्च हिमालयी क्षेत्र में दुर्लभ हिम तेंदुओं की मौजूदगी हमेशा से हर किसी की उत्सुकता के केंद्र में रही है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहां भी अच्छी-खासी तादाद में हिम तेंदुओं की मौजूदगी का अनुमान है। गंगोत्री नेशनल पार्क व गोविंद वन्यजीव विहार से लेकर अस्कोट अभयारण्य तक के क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर लगे कैमरा ट्रैप में कैद होने वाली हिम तेंदुओं की तस्वीरें इसकी सस्तीक करती हैं। बायजूद इसके अभी इस रहस्य से पर्दा उठना बाकी है कि आखिर यहां हिम तेंदुओं की वास्तविक संख्या है कितनी। इसी के दृष्टिगत सिक्योर हिमालय परियोजना के अंतर्गत राज्य में पहली मर्तबा हिम तेंदुओं की गणना कराई जा रही है, जो गंगोत्री से

सिक्योर हिमालय परियोजना के

तहत राज्य में होने जा रही हिम तेंदुओं की गणना



उत्तराखंड में अच्छी-खासी तादाद में हिम तेंदुओं की मौजूदगी का अनुमान है।

फाइल

लेकर अस्कोट अभयारण्य तक के उच्च हिमालयी क्षेत्र में चलेगी।

राज्य में सिक्योर हिमालय परियोजना के नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक आरके मिश्र के अनुसार सदी खत्म होने के बाद मार्च से गणना कार्य प्रस्तावित है। इसमें आइटीबीपी, एसएसबी के साथ ही स्थानीय ग्रामीणों की मदद ली जाएगी। इससे पहले गोविंद वन्यजीव विहार और अस्कोट अभ्यारण्य के अंतर्गत 60 गांवों के अलावा इन संचुरियों के साथ ही गंगोत्री नेशनल पार्क से सटे गांवों के निवासियों के साथ बैठकें

उच्च हिमालयी क्षेत्र में दुर्लभ हिम तेंदुओं की मौजूदगी हमेशा से रही हे उत्सुकता के केंद्र में

जागरण संवाददाता,आगरा : मुजफ्फरनगर में खेत की खोदाई में मिली तोप ब्रिटिशकालीन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की रसायन शाखा ने तोप के आधे हिस्से की केमिकल क्लीनिंग कर ली है। तोप पर बने चिह्न और उसकी डिजाइन के आधार पर उसके ब्रिटिश काल (करीब 200 से 250 वर्ष पुरानी) होने का अनुमान जताया जा रहा है।

उप स्थित मुजफ्फरनगर के हरिनगर में 20 जनवरी को खेत की खोदाई में प्राचीन तोप मिली थी। 23 जनवरी को तोप एएसआइ के माल रोड स्थित आगरा सर्किल ऑफिस लाई गई थी। रसायन शाखा ने 27 जनवरी को उसका परीक्षण करने के बाद केमिकल क्लीनिंग का काम शुरू किया था। तोप पर काफी मिट्टी लगी हुई है। अब तक तोप के आधे हिस्से की सफाई की जा चुकी है। इसमें उसके ऊपर बने क्रॉउन के आधार पर प्रारंभिक रूप से उसके ब्रिटिश काल का होने की बात सामने आई है। तोप अच्छी है। इसमें उसके ऊपर बने क्रॉउन के आधार पर प्रारंभिक रूप से उसके ब्रिटिश काल का होने की बात सामने आई है। तोप अच्छी है। गुणवत्ता के लोहे से बनी है।हालांकि तोप के पूरा साफ होने के बाद ही उसकी वास्तविक स्थिति सामने आ पाएगी। केमिकल क्लीनिंग के बाद उसका प्रिजर्वेशन किया जाएगा। अधीक्षण पुरातत्वविद वसंत कुमार स्वर्णकार ने बताया कि तोप ब्रिटिशकालीन है। फिलहाल केमिकल क्लीनिंग का काम अभी जारी है।

लघु ग्रह के धरती से टकराने की आशंका निराधार

रमेश चंद्रा, नैनीताल

बेशक लघु ग्रह पृथ्वी के सबसे बड़े दुश्मन हों, मगर निकट भविष्य में इनसे कोई खतरा नहीं है। 15 फरवरी को धरती के करीब आ रहे एक लघु ग्रह के धरती से टकराने की अफवाहों को वैज्ञानिकों ने सिर से नकार दिया है। धरती से टकराने की आशंका को लेकर यह लघु ग्रह इन दिनों सुर्खियों में है।

इस लघु ग्रह को 163373 संख्या के नाम से जाना जाता है। इसे 2002 में खोजा गया था। लघु ग्रह को पृथ्वी के निकट से गुजरने वाले पिंडों में शामिल किया गया है। खोज के बाद से ही नासा समेत दुनिया की अनेक स्पेस एजेंसियां इस पर नजर रखे हुए हैं। आकार में यह 589 मीटर का है। यह हमारे सौर परिवार का सदस्य है। सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में इस ग्रह को 650 दिन का सफर तय करना होता है। इस लघु ग्रह को लेकर चर्चा है कि 15 फरवरी को धरती के पास से गुजरते समय पृथ्वी से टकरा जाएगा। इसे लेकर भारतीय तारा भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के वरिष्ठ खगोलीय वैज्ञानिक प्रो. आरसी कर्पूर का कहना है कि जब यह हमारे पास से गुजरेगा तो धरती व इसके बीच की दूरी 58 लाख किमी होगी। इतनी अधिक दूरी के चलते धरती से टकराने की संभावना ही नहीं रह जाती। पृथ्वी के साथ इसकी कक्षा की तुलना करें तो इसकी कक्षा दीर्घ वृत्ताकार है, जिसके चलते अपने

75 से 90 फीसद तक की गिरावट आई है तेंदुओं की तादाद में भारत में। सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ रस्टडी (सीडब्ल्यूएस) इंडिया और वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक ताजा अध्ययन में यह बात सामने आई है।

हिमाचल प्रदेश

कुपोषण दूर करने के लिए सराहनीय पहल



प्रतीकात्मक फोटो

को देवभूमि माना जाता है। यहां पर कई मंदिर हैं। इनमें हर रोज सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंडी शहर में शुरू गई इस उल्लेखनीय योजना को प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है। इससे जहां बच्चों को पोषक तत्व मिल सकेंगे, वहीं ऐसे लोगों को भी एक जरिया मिल सकेगा जो चाहकर भी बच्चों के लिए दान नहीं कर पाते हैं। इस तरह की योजना की सफलता के लिए लोगों को भी आगे आना चाहिए।

प्रशासन की यह योजना नि:संदेह सराहनीय है, लेकिन इसमें जनसहयोग बहुत आवश्यक है। जब तक

लोग सहभागी नहीं बनेंगे, तब तक योजना के आकार लेने की संभावना कम रहती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन के इस कदम को लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा और वे राज्य के अन्य मंदिरों में भी इस तरह की योजना में सहभागी बनेंगे। यदि यह योजना सफल होती है तो इसमें एक अनुकरणीय मिसाल बनने की क्षमता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि इसकी कामयाबी के बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी अपनाया जा सकता है। इससे न केवल कुपोषण की समस्या पर कुछ हद तक अंकुश लगेगा, बल्कि उन संसाधनों की बर्बादी भी रूकेगी जो बिना उपयोग के ऐसे ही व्यर्थ हो जाते हैं।

बिहार

अपराधियों को मिले कड़ी सजा



प्रतीकात्मक फोटो

से दो वक्त की रोटी के लिए चाय बेचना शुरू किया। उसने कानून का भी हमेशा ख्याल रखा और अपने नागरिक दायित्वों का पूरी तरह निर्वहन किया, अन्यथा

अपराधियों को महज गिलास देने से मना नहीं करता। उन्हें पता था कि बिहार में शराबबंदी है और कोई उनका दुकान से गिलास लेकर शराब का सेवन करे तो गलत है। इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। पुलिस ने कहा है कि अपराधियों की पहचान की जा रही है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पर इसका ध्यान रखना होगा कि रोजमर्रा के ऐसे कितने ही मामलों की तरह यह भी एक रूटीन भर का मामला बनकर नहीं रह जाए।

अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी जरूरी है। यह भी विचारणीय प्रश्न है कि जब राज्य में शराबबंदी है तो ऐसे असामाजिक तत्व खुलेआम शराब पीने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं। हाल के महीनों में कई पुलिसकर्मियों के विरुद्ध बर्खास्तगी जैसी सख्त कार्रवाई भी हुई है, लेकिन अभी भी शराब का खेल जारी है। सरकार को चाहिए कि इन मामलों में और सख्ती बरते, दोधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, ताकि समाज में कानून के राज का सीधा संदेश जाए और अपराधियों में भय पैदा हो।

जर्मन तकनीक से और सस्ते उपकरण बनाएगा एलिम्को

शाशांक शेखर भारद्वाज, कानपुर

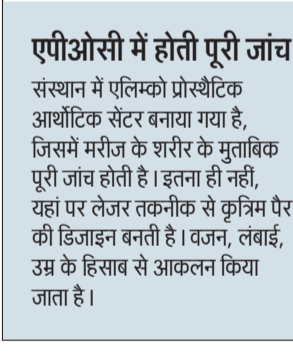
दिव्यांगों के लिए कृत्रिम हाथ-पैर और अन्य उपकरण बनाने वाले एशिया के नंबर वन संस्थान आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलिम्को) और सस्ते उपकरण तैयार करेगा। यह न सिर्फ विदेशी उपकरणों को न सिर्फ टक्कर देंगे, बल्कि बाजार से बेहद सस्ते भी होंगे। इन उपकरणों का उपयोग बेहद आसान होगा। एलिम्को ने जर्मनी की ऑटोबाॅक और इंग्लैंड की मोटीवेशन कंपनी से करार किया है। ऑटोबाॅक के सहयोग से करीब एक हजार हाई एंड प्रोस्टैटिक लेग (कृत्रिम पैर) बन चुके हैं। अब अन्य उपकरणों की तैयारी को जा रही है। एक प्रोस्टैटिक लेग की कीमत 20 से 25 हजार रुपये आ रही है।

बाजार में इसी तरह के प्रोस्टैटिक लेग डेढ़ लाख रुपये में मिल रहा है। कृत्रिम पैर सस्ते होने से यह एडीप (उपकरणों की खास फिटिंग के लिए सहायता योजना) में आ जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक दिव्यांगों को लाभ मिलेगा।

जैसी जरूरत वैसी व्हीलचेयर : मोटीवेशन कंपनी के साथ मिलकर संस्थान की खास तरह की व्हील चेयर बनाने की योजना है। यह व्हीलचेयर दिव्यांगों की जरूरत के मुताबिक होगी।

मार्केट में कृत्रिम पैर की कीमत डेढ़ लाख रुपये, संस्थान में 25 हजार

सीएसआर फंड से दिव्यांगों की होगी मदद, व्हीलचेयर में इंग्लैंड का सहयोग



एपीओसी में होती पूरी जांच

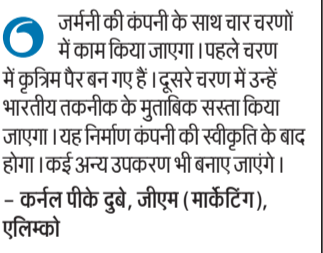
संस्थान में एलिम्को प्रोस्टैटिक आर्थोटिक सेंटर बनाया गया है, जिसमें मरीज के शरीर के मुताबिक पूरी जांच होती है। इतना ही नहीं, यहां पर लेजर तकनीक के कृत्रिम पैर की डिजाइन बनती है। वजन, लंबाई, उम्र के हिसाब से आकलन किया जाता है।

जर्मनी की कंपनी के साथ चार चरणों में काम किया जाएगा। पहले चरण में कृत्रिम पैर बन गए हैं। दूसरे चरण में उन्हें भारतीय तकनीक के मुताबिक रस्ता किया जाएगा। यह निर्माण कंपनी की स्वीकृति के बाद होगा। कई अन्य उपकरण भी बनाए जाएंगे।

- कर्नल पीके दुबे, जीएम (मार्केटिंग), एलिम्को

चार चरणों में होगा काम

ऑटोबाॅक ने कॅंप्यूटराइज्ड न्यूमैरिकली कंट्रॉल्ड (सीएनसी) मशीन स्थापित की है, जिससे शरीर की बनावट के मुताबिक हबहु लाइटवेट, प्लीक्सिग्लैस और हाई वैवालिटी के कृत्रिम पैर बनाए जा रहे हैं।



जर्मनी की कंपनी के साथ चार चरणों में काम किया जाएगा। पहले चरण में कृत्रिम पैर बन गए हैं। दूसरे चरण में उन्हें भारतीय तकनीक के मुताबिक रस्ता किया जाएगा। यह निर्माण कंपनी की स्वीकृति के बाद होगा। कई अन्य उपकरण भी बनाए जाएंगे।

- कर्नल पीके दुबे, जीएम (मार्केटिंग), एलिम्को

स्टेशनों पर बार कोड स्कैन करने के साथ ही बुक हो जाएगा टिकट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर

रेलवे स्टेशनों पर अब जनरल टिकट के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। काउंटर के पास या गेटों पर बार कोड स्कैन करने के साथ ही टिकट बुक हो जाएगा। यह सुविधा मोबाइल यूटीएस (अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम) एप पर मिलेगी।

यूटीएस एप से स्टेशन परिसर के भीतर या रेल लाइन के आसपास 15 मीटर के दायरे में टिकट बुक नहीं होते हैं। ऐसे में यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे ने यह अहम निर्णय लिया है। फिलहाल इज्जतनगर मंडल के ‘ए’ श्रेणी के स्टेशनों पर यह सुविधा मिलने लगी है। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर, लखनऊ और छपरा जंक्शन पर ट्रायल चल रहा है। जल्द ही एचन और ए कटेगरी के स्टेशनों पर यह नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी।

प्रथम चरण में एचन और ‘ए’ के अलावा ‘बी’ व ‘डी’ श्रेणी के कुछ स्टेशनों के साथ कुल 65 जगहों पर यात्रियों की यह सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। पूर्वोत्तर रेलवे में 16 अक्टूबर 2018 से मोबाइल यूटीएस एप की सुविधा लोगों को मिल रही है। पूर्वोत्तर रेलवे में एक फीसद यात्री भी एप से टिकट बुक नहीं करते हैं।

मोबाइल यूटीएस एप पर मिलेगी सुविधा, नहीं लगानी पड़ेगी लाइन

एप की खासियतें
<ul style="list-style-type: none">स्टेशन परिसर से 15 मीटर के दायरे में बुक नहीं होंगे टिकट स्टेशन के पांच किलोमीटर के दायरे में टिकट बुक कराने की सुविधा स्टेशन से दो किलोमीटर के दायरे में बनता है प्लेटफार्म टिकट एप से बुक टिकट सेव नहीं होते, स्क्रीन शॉट संभव नहीं यात्रा पूरी होते ही अपने आप समाप्त हो जाता है टिकट वापस नहीं होता है मोबाइल एप से बुक टिकट का किराया
<ul style="list-style-type: none">मोबाइल यूटीएस एप सिस्टम में यात्रियों को एक और अतिरिक्त सुविधा मिल जाएगी। क्यूआर बार कोड लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। - पाकज कुमार सिंह, सीपीआरओ, एनई रेलवे

15 साल पूरे हो गए हैं गुगल मैप्स के गत गुरुवार को। इस अवसर पर गुगल ने इसका नया लोगो जारी किया। इसके साथ ही इसमें नए फीचर्स जोड़े गए हैं। नए आइकन वाले एप में एक्सप्लोर, कम्प्यूट, सेव्ड और अपडेट्स के टैब्स दिए गए हैं।

वुहान में फंसे भारतीयों के लिए देवदूत बनी टीम एयर इंडिया

इन दिनों

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

आज कोरोना वायरस का नाम सुनते ही लोगों में डर बैठ जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि जब इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित चीन के वुहान शहर में जाने की बात हो तो किसी का क्या हाल होगा, लेकिन एयर इंडिया के कुछ जांबाजों ने वहां जाकर न सिर्फ भारतीय नागरिकों को वापस लाने में सफलता हासिल की, बल्कि अपने कर्तव्य को भी पूरा किया। इस पूरी प्रक्रिया के इंचार्ज और एयर इंडिया के डायरेक्टर ऑपरेशंस अमिताभ सिंह ने बताया कि इस बचाव दल में कुल 34 सदस्य शामिल थे।

अमिताभ सिंह ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि जब हम वुहान पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे हम किसी ऐसे शहर में पहुंच गए हैं जहां का सर्वनाश हो चुका है और भूतों का बसेरा है। शुरू में यह किसी अन्य उड़ान की तरह था और वायुमार्ग व्यस्त थे, लेकिन जब हम नीचे उतरने लगे तो सन्नाटा हम पर मंडराने लगा। हवाई अड्डे पर खामोशी छाई हुई थी। सभी विमानों को पार्क कर

चीन के वुहान शहर में फैले कोरोना वायरस के प्रकोप से हर कोई डरा हुआ है। हालात ये हैं कि हर देश अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने का कोई न कोई उपाय कर रहा है। ऐसे में हमारे नागरिकों को वहां से निकालने की जिम्मेदारी एयर इंडिया के 34 जांबाजों की टीम को सौंपी गई, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। आइए जानें कैसे टीम एयर इंडिया ने यह संभव किया...



कैप्टन अमिताभ सिंह, कमल मोहन, संजय अवलकर, एस.एच. रेजा व भूपेश नारायण। फाइल, प्रेद

सील कर दिया गया था। सड़कें खाली थीं।

अमिताभ के मुताबिक, पांच पायलट और 15 केबिन क्रू को निर्धारित प्रस्थान से दो-तीन दिन पहले वुहान से भारतीयों को निकालने के मिशन के बारे में बताया गया। उड़ान से एक दिन पहले, पायलट और केबिन क्रू को मिशन की विस्तृत जानकारी दी गई। एयरलाइन ने चालक दल और सहायक कर्मचारियों के लिए मेडिकेटेड सूट, सुरक्षात्मक जूते, दस्ताने, एन-35 मास्क, चश्मा

और टोपी की भी खरीदारी की थी।

मिशन को अंजाम देने के लिए बोंग 747 विमान का इस्तेमाल किया गया, जिसे आमतौर पर वीवीआइपी के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यह विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 31 जनवरी की दोपहर 12.30 बजे वुहान के लिए रवाना हुआ। इसमें अतिरिक्त ईंधन, स्पेयर पार्ट्स और पर्याप्त भोजन-पानी की व्यवस्था भी की गई। जबो नाम से मशहूर इस विमान को इसलिए

चुना गया था क्योंकि यह एक डबल डेकर विमान है, जिसमें एक साथ 423 यात्री बैठ सकते हैं। टीम में शामिल एक अन्य पायलट ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उसने अपने परिवार को इस मिशन में नहीं भूमिका के बारे में नहीं बताया था। चार घंटे की लंबी उड़ान के बाद जबो वुहान में उतरा, लेकिन उसे यात्रियों के लिए करीब आठ घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ा। इस दौरान विमान दल के लोग काफी चिंतित दिखे कि आखिर यह देरी



क्यों हो रही है। इस बारे में अमिताभ सिंह ने बताया कि दरअसल, चीनी अधिकारियों ने एयर इंडिया के विमान के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद ही छात्रों को भारतीय वाणिज्य दूतावास के लिए अपने होटल और हॉस्टल से जाने की अनुमति दी। विमान के वुहान पहुंचने के बाद ही छात्रों को हवाई अड्डे तक जाने की अनुमति दी गई, जिस कारण यह देरी हुई। चीनी अधिकारियों से समन्वय का काम अमिताभ सिंह के पास ही था।

उड़ान का संचालन कैप्टन कमल मोहन, कैप्टन संजय अचलकर, कैप्टन एस.एच. रेजा, कैप्टन भूपेश नारायण ने किया। केबिन क्रू टीम का नेतृत्व मंजू तंवर कर रही थीं। फ्लाइट में मौजूद तीन डॉक्टरों और चार नर्सिंग स्टाफ की टीम ने सभी 324 यात्रियों के तापमान को मापा और यात्रियों को बोर्ड करने की अनुमति देने से पहले उन्हें मास्क पहनना सिखाया।

विमान के अंदर बरती गई सावधानियां : विमान के अंदर जोखिम को कम करने के लिए कई तरह की सावधानियां बरती गईं। सभी यात्रियों को इकोनॉमी क्लास में बैठाया गया। इंजीनियर और डॉक्टर आगे के सेक्शन में फर्स्ट क्लास में थे, जबकि अतिरिक्त केबिन क्रू और कर्मशिलिंग स्टाफ को ऊपरी डेक पर एक्जैक्यूटिव क्लास में जगह दी गई। पायलट को कॉकपिट तक ही सीमित रखा गया। यह उड़ान एक फरवरी की सुबह 7.30 बजे नई दिल्ली लौटी, जहां स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी और सेना व भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के कर्मचारी तैनात थे। यात्रियों को फौरन उतारा गया और चिकित्सकीय जांच के बाद उन्हें विशेष बस से कैप तक पहुंचाया गया। इसके बाद एयर इंडिया की इस टीम के कई सदस्य फिर से वुहान जाने की तैयारी में जुट गई क्योंकि उन्हें बाकी बचे लोगों को भी वापस लाना था।

यशस्वी : मुश्किल इम्तिहान के ने बनाया और मजबूत

वर्चित चेहरा

निखिल शर्मा, नई दिल्ली

तीन साल तक वह मैदान कर्मी के साथ मुंबई के आजाद मैदान में मुस्लिम यूनाइटेड क्लब के टेंट में रहा। उसे ऐसा करना भी पड़ा क्योंकि उसे दूध की डेयरी से बाहर निकाल दिया गया था, जहां वह सोता था। यशस्वी जायसवाल उस वक्त सिर्फ 11 वर्ष का था और तब उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी वो था उसका सपना। भारत के लिए क्रिकेट खेलने का। अब छह साल बाद चुके हैं। यशस्वी अब 17 वर्ष के हो गए हैं।

यशस्वी शीर्ष क्रम के शानदार बल्लेबाज हैं, जो इस समय दक्षिण आफ्रीका में चल रहे अंडर-19 विश्व कप में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। उन्होंने विश्व कप के सेमीफाइनल में नाबाद 105 रनों की अहम पारी खेलकर भारतीय टीम को ना सिर्फ 10 विकेट से जीत दिलाई बल्कि टीम को फाइनल में पहुंचा दिया, जहां उसका सामना रविवार को बांग्लादेश से होगा।

यशस्वी के पिता की उत्तर प्रदेश के भदोही में एक छोटी सी दुकान है। दो भाइयों में छोटे यशस्वी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई पहुंच गए। उनके पिता को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पा रहे थे। यशस्वी के चाचा संतोष का मुंबई के वल्लों में घर था, लेकिन यह रहने के लिए काफी नहीं था। इसके बाद संतोष ने मुस्लिम यूनाइटेड क्लब के मालिकों से यशस्वी को टेंट में रहने की इजाजत मांगी, जहां वह मैनैजर थे। यह तब की बात थी जब उनको कलबादेवी में दूध की डेयरी से निकाल दिया गया था। पूरा दिन क्रिकेट खेलने के बाद यशस्वी थककर वहां सोने जाते थे। एक दिन उन्होंने यह कहकर यशस्वी का सामान बाहर फेंक दिया कि वह कुछ नहीं करता है, किसी शाने में हाथ नहीं बंटता है और सिर्फ सोता है। तब तीन साल के लिए यह टेंट ही उनका घर बन गया। यशस्वी इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके संघर्ष की कहानी भदोही नहीं पहुंचे, नहीं तो उसका क्रिकेट करियर खत्म हो जाता। ऐसा कम ही होता था जब उसके पिता उसको कुछ पैसे भिजवाते थे, लेकिन वह भी काफी नहीं रहते थे। जब वे पानी के बताशे : संघर्ष के दिनों में यशस्वी ने काफी कुछ देखा। आजाद मैदान में रामलीला के दौरान उन्होंने पानी के बताशे बेचे और फल बेचने में मदद की, लेकिन इसके बावजूद भी उनको थूके पेट सोना पड़ा था, क्योंकि जिस मैदान कर्मी के साथ वह टेंट में रहते थे उससे उनकी लड़ाई होती रहती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह खाना



अंडर-19 विश्व कप में टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले यशस्वी जायसवाल का बल्ला इन दिनों खूब चल रहा है, लेकिन अपने यहां तक के सफर में उन्होंने तमाम संघर्ष झेले और उन्हें पार किया। जानते हैं इस युवा बल्लेबाज के जोश, जुनून और संघर्ष से भरी दास्तां को...

बनाए बिना उनको सोने नहीं देता था।

रोटी बनाने की इयूटी : यशस्वी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि रामलीला के दौरान मैं अच्छा कमाता था। मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि मेरे टीम के साथी यहां पर पानी के बताशे खाने नहीं आएंगे। कई बार ऐसा हुआ और मुझे उन्हें बताशे खिलाते हुए देखा नहीं लगता था। वह पूरी कोशिश करते थे कि कुछ पैसे कमाए जा सकें। वह बड़े लड़कों के साथ मैच खेलकर और बड़ा स्कोर करके 200-300 रुपये सप्ताह कमा लेते थे। यशस्वी हमेशा देखते थे कि उनकी उम्र के लड़के अपने साथ खाना लाते थे या उनके परिजन उनके लिए खाने का डिब्बा लाते थे, लेकिन वह खाना खुद बनाते और खाते। वह नाश्ता नहीं करते थे और किसी से नाश्ता खिलाने का आग्रह करते। वह भोजन और रात का खाना टेंट में ही करते और उनकी इयूटी रोटी बनाने की थी।

इस तरह शुरू हुआ सफर : मुंबई के अंडर-19 कोच संतोष सामंत यशस्वी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनको मुंबई के अगला बड़ा खिलाड़ी करार दिया। सामंत ने कहा कि उसके अंदर गेंदबाजों का दिमाग पढ़ते और खुद को उसके मुताबिक ढालने की क्षमता है। कई अंडर-19 के खिलाड़ी

जल्द शॉट खेलने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। मुंबई की अंडर-19 टीम में चुने जाने से पहले यशस्वी की किस्मत तब बदली जब उसे कोच ज्वाला सिंह से मिले। ज्वाला खुद भी उत्तर प्रदेश से यहाँ आकर बसे हैं और उन्हें यशस्वी में खुद का बचपन दिखा। ज्वाला ने कहा कि वह मात्र 12 साल का होगा और वह एक अच्छे गेंदबाज को आसानी से खेल रहा था। मैं तब सीधा उससे जुड़ गया, क्योंकि जब मैं उत्तर प्रदेश से मुंबई आया था तो मेरे पास भी रहने के लिए घर नहीं था। कोई गॉडफादर नहीं था, कोई राह दिखाने वाला भी नहीं। उसने पिछले पांच साल में 49 शतक लगाए हैं। यशस्वी अब कदमवदी में एक छोटी चॉल में रह रहा है, जिसे वह अपना घर बताता है।

आइपीएल नीलामी में बदली किस्मत : अंडर-19 विश्व कप से पहले हुई आइपीएल नीलामी में यशस्वी की किस्मत बदल गई। उनको राजस्थान रॉयल्स ने दो करोड़ से ऊपर की रकम में खरीदा। अब उम्मीद है कि यशस्वी उस छोटी सी चॉल में नहीं रहेंगे। रविवार को बांग्लादेश से फाइनल मुकाबले से पहले ही उन पर दुनियाभर की निगाहें टिक गई हैं।

इनसे मिलिए

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जब यह कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने राम मंदिर ट्रस्ट के गठन को मंजूरी दे दी है तो लंबे समय से चला आ रहा इंतजार खत्म हो गया और इसी के साथ वकील समुदाय के पितामह कहे जाने वाले के. परासरन एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। इस बार सुर्खियों में आने की वजह उनकी वकालत नहीं, बल्कि उन्हें 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट का पहला ट्रस्टी बनाया जाना है और साथ ही यह ट्रस्ट उनके घर के पते पर ही पंजीकृत किया गया है।

92 वर्षीय परासरन बीते वर्ष अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुर्खियों में थे। 2016 के बाद से कोर्ट में उनकी उपस्थिति भले ही कम रही थी, लेकिन दो बड़े मुकदमों ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया था। पहला-सबरीमाला और दूसरा अयोध्या राम जन्मभूमि मामला। इन दोनों मुकदमों के चलते दो बार देश के अदालतों में सुनवाई के लिए परासरन चेन्नई से दिल्ली वापस आए। हिंदू धर्मग्रंथों के जानकार परासरन सर्वोत्कृष्ट

दो बार देश के अदालतों में सुनवाई के दौरान सुर्खियों में थे तो इस वर्ष इस फैसले के बाद गठित किए गए ट्रस्ट की वजह से चर्चा में आ गए। उन्हें 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट का पहला ट्रस्टी बनाया जाना है और यह ट्रस्ट उनके घर के पते पर ही पंजीकृत किया गया है...



सरकारी वकील हैं। 1970 के बाद से वह हर सरकार के विश्वसनीय रहे। अदालत में अक्सर हिंदू धर्मग्रंथों पर व्याख्यान देते हैं। इतना ही नहीं, अपने धर्म से समझौता किए बिना कानून में दिए गए इनके योगदान के लिए मद्रास के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल ने इन्हें भारत में वकील समुदाय का पितामह कहा था।

सबरीमाला और अयोध्या राम जन्मभूमि मामले से पहले एक और केस में वह सुर्खियों में रहे। राम सेतु केस में जब दोनों विरोधी पार्टियां परासरन के पास पहुंचीं तो उन्होंने सरकारी के खिलाफ जाकर, सेतुसमुद्रम

परियोजना से सेतु की रक्षा करने का निर्णय लिया। जब जजों ने परासरन से पूछा कि वह सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने स्कंद पुराण का जिक्र किया, जिसमें इस सेतु का वर्णन है।

1927 में तमिलनाडु के श्रीरंगम में जन्मे के. परासरन के पिता केशव अयंगर वकील और वैदिक विद्वान थे। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की। परासरन के तीनों पुत्र मोहन, संतोष और बालाजी भी वकील हैं। मोहन परासरन संग्रम-2 सरकार में कुछ समय के लिए सॉलिसिटर जनरल रहे। अब परिवार की

चौथी पीढ़ी ने भी इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए वकालत की दुनिया में कदम रखा है। परासरन ने 1958 में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की थी। बीती सदी के सातवें दशक में बड़े मामलों में परासरन का सामना अक्सर नानी पालकीवाला से होता था। आपातकाल के दौरान परासरन तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल थे। 1980 में देश के सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए। 1983 से 1989 तक देश के अदालतों में परासरन के रूप में काम किया। 1992 में जब मुंबई निवासी मिलन बनर्जी को अदालतों में परासरन नियुक्त किया गया, तब परासरन को 'सुपर एजी' के रूप में संदर्भित किया गया। बनर्जी को मध्यस्थता और वाणिज्यिक कानूनों में महारत हासिल थी, लेकिन संवैधानिक मामलों में सरकार के पास परासरन ही सबसे अच्छा विकल्प रहे।

सरकारें बदलीं, लेकिन परासरन की सराहना हमेशा की गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें सविधान के कामकाज की समीक्षा के साथ प्राख्यान और संपादकीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। वहीं, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संग्रम-1 सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा और उन्हें संसद के उच्च सदन में मनोनीत किया।

तीन साल की वेदा की दुनिया हुई दीवानी

उभरता सितारा

तनु गुप्ता, आगरा

प्रतिभा एक खुशबू की तरह होती है, जिसे फैलाने से कोई रोक नहीं सकता। जन्मरत होती है तो बस समय और सही मंच की। बीते दिनों आगरा की तीन साल की वेदा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उनके साढ़े पांच मिनट के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर ऐसी धूम मचाई कि सप्ताहभर में ढाई करोड़ से अधिक लोगों ने उसे देखा और देखते ही देखते वह इंटरनेट की सनसनी बन गई।

भारत सहित सिंगापुर, कुवैत, अफगानिस्तान, फिलीपींस, अमेरिका तक के करीब ढाई लाख से अधिक व्यूअर्स ने वेदा के वीडियो को शेयर किया है। इतना ही नहीं छह फरवरी की रात टेक्सस रेडियो से वेदा के वीडियो को सुनाया भी गया। वेदा के माता-पिता ने कुछ ही समय पहले आगरा की आवास विकास कॉलोनी से मुंबई शिफ्ट हुए हैं।

दरअसल, गत 26 जनवरी को मुंबई के बांद्रा स्थित सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम में संकल्प युगवर्ष संस्था ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें संगीत शिक्षक माधव अग्रवाल ने बेटी वेदा ने दिल है छोट्टा सा...गीत गाया। नन्ही सी वेदा पिक और ब्लैक प्रॉक में मंच पर अपने पिता संग प्रस्तुति देने के साथ ये गिनती बढ़ती गई और सात दिन बाद व्यूअर्स की संख्या ढाई करोड़ पार कर



पहली पॉप गाने के बाद कर्मान गायक कहकर हरेक का दिल जीत लिया। साढ़े पांच मिनट के गीत के दौरान वेदा स्टेज पर डांस भी करती रही। दो फरवरी की रात वेदा के माता-पिता ने परफार्मेंस का वीडियो फेसबुक पेज पर अपलोड किया तो धड़ाधड़ लाइक और शेयर मिलने लगे। इजाफा उस वक्त हुआ जब अभिनेता जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर ने इसे अपने फेसबुक और ट्विटर पेज यो यो पर शेयर किया। 48 घंटे के भीतर वेदा के वीडियो को 20 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया और 15 हजार से अधिक लोगों ने अपने सोशल अकाउंट पर इसे शेयर कर दिया था। हर दिन के साथ ये गिनती बढ़ती गई और सात दिन बाद व्यूअर्स की संख्या ढाई करोड़ पार कर

कहते हैं प्रतिभा कुदरत की देन होती है, बस सही समय और मंच पर वह सामने आती है। बीते दिनों आगरा की वेदा ने एक मंच पर कुछ ऐसा कर दिखाया कि रातोंरात सोशल मीडिया की स्टार बन गई। इतना ही नहीं, साढ़े पांच मिनट की परफॉर्मेंस के बल पर उन्हें एक टीवी शो में रोल भी मिल गया...

चुकी है। वेदा के पिता माधव अग्रवाल को बचपन से ही संगीत का शौक था। तीन साल पहले वह मुंबई शिफ्ट हो गए। वेदा की मां मेधा वहीं टिफिन सर्विस चलाती हैं। माधव ने बताया कि जब वह संगीत का रियाज करते हैं तो वेदा आसपास ही रहती है। जावेद ने कहा अगली बार करुणा साथ में डांस : प्रस्तुति के बाद अभिनेता जावेद जाफरी ने ग्रीन रूम में आकर वेदा की तारीफ की और अगली बार स्टेज शेयर करने के इच्छा जताई। वीडियो वायरल होते ही सोनी चैनल पर जल्द शुरू होने जा रहे शो 'पापा की पंरी' के लिए भी वेदा को साइज कर लिया गया है। ताऊ-दादी खुशी में वांट रहे तड़डू : आगरा की

देश-दुनिया से मिल रही सराहना युं तो वेदा के वीडियो को अबतक लाखों लोगों की सराहना मिल चुकी है। दुनियाभर से कमेंट मिलने अभी भी लगातार जारी हैं। भारत सहित, सिंगापुर, कुवैत, अफगानिस्तान तक के व्यूअर्स वेदा के वीडियो को शेयर कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा कमेंट- टीवीटर पर आज की सबसे प्यारी चीज। दीपिका नारायण भारद्वाज, फिक्स निदेशक वीडियो देखकर मेरा दिन बन गया। शेयर करने के लिए शुक्रिया। हर्ष गौरांका, बिजनेस टाकस शानदार आत्मविश्वास और बहुत प्यारी आवाज। मेरा आशीर्वाद छोटी बच्ची के साथ है। ईश्वर करे वो भविष्य में एक महान गायक बने। डॉ. अनिता बैजमिन, ग्लोबल पीस एंबेसडर

आवास विकास कॉलोनी स्थित माधव के पेंचुक निवास पर खुशी का माहौल है। परिवार की दुबारा ब्रिटिया की इस उपलब्धि पर दादी बीना अग्रवाल और ताऊ मनीष अग्रवाल मिठाइयां बांट रहे हैं। घर पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।

दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी थ्रीडी प्रिंटेड इमारत बनकर तैयार हो गई है। अब इसका उपयोग दुबई नगरपालिका द्वारा सामान्य प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाएगा। यह निर्माण उस घोषणा का हिस्सा है जिसमें 2030 तक 25 प्रतिशत इमारतों को थ्रीडी करने के लिए कहा गया था। इसे वोस्टरन की कंपनी एपिस कोर ने डिजाइन किया है और थ्रीडी प्रिंटर, जिप्सम कम्पाउंड युक्त क्रेन से बनाया गया है।



दुनिया की सबसे बड़ी थ्रीडी प्रिंटेड इमारत दुबई में 2030

तक 25 प्रतिशत इमारतों को थ्रीडी करने के लिए कहा गया था। यह निर्माण उस घोषणा का हिस्सा है

बिल्डिंग के वारे में

दुबई में तैयार इस दो मंजिला इमारत को 6900 वर्ग फीट में बनाया गया है। इसमें दुबई नगर पालिका का ऑफिस है। इसका इस्तेमाल सामान्य प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाएगा।

कैसे किया तैयार

थ्रीडी प्रिंटर ने कुछ इंच मोटी सामग्री परतों के साथ दीवारें तैयार कीं। इसके बाद पूरी ऊंचाई की दीवारें बनाई गईं। आखिर में छत इनके ऊपर रखी गई। फिर खिड़कियों के लिए खाली जगह छोड़कर दीवारों को इंसुलेशन से भर दिया।



अगला लक्ष्य

कंपनी का अगला प्रोजेक्ट सुइसियाना और कैलिफोर्निया में है। यहां कंपनी को 500 वर्ग फीट में एक रहने योग्य घर 24 घंटे में तैयार करना है।



कम लागत और अधिक टिकाऊ

इस बिल्डिंग को बनाने में लेबर की लागत 70 प्रतिशत और इमारत की लागत 90 प्रतिशत तक कम हो गई। इसमें तेजी से सूखने वाले सीमेंट, जिप्सम के तत्वों को मिलाया गया है। थ्रीडी प्रिंटिंग तकनीक से तैयार इमारत की लागत सामान्य मटेरियल के मुकाबले आधी से कम आती है और यह उससे अधिक मजबूत और टिकाऊ होती है।

चीन में सबसे ऊंची थ्रीडी प्रिंटेड बिल्डिंग

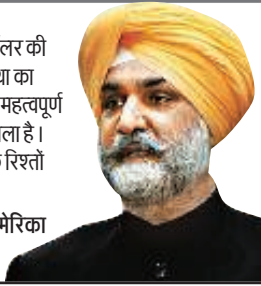
दुनिया में सबसे ऊंची थ्रीडी प्रिंटेड बिल्डिंग चीन के सूजो में है। 190 फीट ऊंची इस बिल्डिंग में 5 मंजिलें हैं। दुनिया में सबसे पहले 1980 में इस तकनीक को खोज गया था। इसके खोजकर्ता इंजीनियर और फिजिसिस्ट चुक हुल थे।

पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में मददगार होंगे स्टार्ट-अप

राज्य ब्यूरो, मुंबई: देश की इकोनॉमी को पांच लाख करोड़ डॉलर का आकार देने में स्टार्ट-अप कंपनियां बड़ी भूमिका निभाएंगी। यह बात आज मुंबई में केंद्रीय कोशल विकास एवं रोजगार मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने कही। पांडे शनिवार को रामभाऊ म्हालांगी प्रबोधिनी के तहत अटल इन्व्यूबेशन सेंटर द्वारा आयोजित दूसरे न्यू इंडिया स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। ये सेंटर नीति आयोग के अटल इन्व्यूबेशन मिशन के तहत संचालित किए जा रहे हैं।

पांच लाख करोड़ डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पाने में अमेरिका के बेहद महत्वपूर्ण कारोबारी साझेदार रहने वाला है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों की अपार संभावनाएं हैं।

— तरनजीत सिंह संधू, अमेरिका में भारत के राजदूत



डीजल-पेट्रोल की कीमत में लगातार गिरावट से घरेलू ग्राहकों को बड़ा फायदा

नई दिल्ली, आइएनएस: डीजल-पेट्रोल के भाव में लगातार गिरावट के चलते ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। शनिवार को भी पेट्रोल 24 पैसे और डीजल 27 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया। इस गिरावट के बाद शनिवार को दिल्ली में पेट्रोल 72.45 रुपये, मुंबई में 78.11 रुपये, कोलकाता में 75.13 रुपये और चेन्नई में 75.27 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिका। वहीं दिल्ली में डीजल 65.43 रुपये, मुंबई में 68.57 रुपये, कोलकाता में 67.79 और चेन्नई में 69.10 रुपये प्रति लीटर रहा। सात जनवरी के बाद से पेट्रोल का दाम तीन रुपये से ज्यादा गिरा है।

कोरोना की चिंता में कच्चे तेल के भाव में लगातार गिरावट

सात जनवरी के बाद से पेट्रोल का दाम तीन रूपये से ज्यादा गिरा



प्रतीकात्मक

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक इस महीने दिल्ली में पेट्रोल 82 पैसे और डीजल 85 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। कोरोना वायरस से प्रभावित ग्लोबल मार्केट में तेल की मांग में कमी के डर से कच्चे तेल के भाव में लगातार गिरावट देखने को मिली है। पिछले कई सप्ताह से कोरोना प्रभावित कच्चे तेल के भाव में 20 परसेंट तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसके

अलावा शुक्रवार को रूस ने कच्चे तेल के उत्पादन में कमी के लिए और इंतजार करने की बात कही थी। इससे भाव में एक परसेंट की गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल स्तर पर उत्पादन इकाइयों में अस्थायी रूप से उत्पादन रुकने के चलते इंधन की खपत में कमी आई है। इस समय कच्चे तेल की

कीमत करीब 55 डॉलर प्रति बैरल के आस-पास आ गई है। घरेलू बाजारों में खुदरा तेल की कीमत ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के भाव पर निर्भर करती है। तेल कंपनियों प्रतिदिन आधार पर तेल की कीमत तय करती हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से तेल की कीमत बहुत महत्वपूर्ण है। यह देश की इकोनॉमी को कई स्तर पर प्रभावित करती है। गौरतलब है कि भारत कच्चे तेल की खपत का अधिकतर हिस्सा आयात करता है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव तो बनता ही है, साथ ही चालू खाते के घाटे में इजाफा होता है।

कच्चे तेल के भाव में गिरावट से उपभोक्ताओं को राहत मिली ही है और सरकार ने भी राहत की सांस ली है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई के माध्यम से इसकी कीमतों पर नियंत्रण रखा जाता है। दाम में और गिरावट के बाद कच्चे तेल के निर्यातक देशों के संगठन ओपेक द्वारा इसके उत्पादन में कटौती का फैसला किया जा सकता है।

कोरोना से दुनिया को लग रही बड़ी आर्थिक चपत

जेएनएन, नई दिल्ली

वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती छाई है और उसे दुनिया के बड़े देशों से उम्मीद है। हालांकि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन पर असर पड़ना तय है और चीन के लड़खड़ाने से दुनिया पर बड़ा और बुरा असर पड़ेगा। चीन में कोरोना से कुछ वर्ष पहले सामने आए सारस ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा था।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में 16 फीसद हिस्सा : वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन 2003 की सारस महामारी के वक्त से ही अनिवार्य हिस्सा है। यह विश्व की फेक्ट्री के रूप में विकसित हुआ है और आइफोन जैसे प्रोडक्ट यहीं से निकलते हैं। साथ ही बहुत सी चीजों की यह मांग पैदा करता है। चीन से दवा है कि उसके पास हज़ारों-लाखों घनी उपभोक्ता हैं जो लगजरी उत्पादों, पर्यटन और कारों पर खर्च करते हैं। एक अनुमान के तौर पर 2003 में वैश्विक

अर्थव्यवस्था में चीन की हिस्सेदारी चार फीसद थी, वहीं आज यह करीब 16 फीसद तक पहुंच चुकी है। सारस ने पहुंचाया था नुकसान : सारस के चलते 8,098 लोग बीमार हुए थे और 774 मारे गए थे। हालांकि चीन के वृहान शहर में कोरोना के सामने आने के बाद से 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और दुनिया के करीब 25 देशों के 35 हजार लोग संक्रमण से जूझ रहे हैं। चीनी अधिकारियों ने वृहान के साथ कुछ अन्य शहरों को भी बंद कर दिया है। बावजूद इसके वायरस लगातार फैलता जा रहा है।

उत्पादन पर ब्रेक : लूनर महीने के दौरान छुट्टी के चलते चीन में कार संयंत्र बंद हैं। इसके बाद वैश्विक कार निर्माता फॉक्सवैगन, टोयोटा, डेम्लर, जनरल मोटर्स, रेनॉ, होंडा और ह्यूंडई अपना काम फिर से शुरू करने वाले थे। एस्पेंड्री ग्लोबल रेंटिंग्स के मुताबिक, यह प्रकोप पहली तिमाही में कार निर्माताओं के उत्पादन को 15 फीसद घटा सकता है। टोयोटा ने कहा है कि वह 17 फरवरी तक अपने संयंत्रों को बंद रखेगा। ब्रिटिश

ब्रांड बरबरी ने चीन में अपने 64 में से 24 स्टोर्स बंद कर दिए हैं। सबसे ज्यादा खतरा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ रहा है। दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन चिप निर्माता क्वालकॉम ने चेताया है कि कोरोना का प्रकोप मांग में महत्वपूर्ण अनिश्चितता का कारण बन सकता है, आपूर्ति के लिए उत्पादन की आवश्यकता होगी। वहीं हंडई ऑटो पार्ट्स की कमी से जूझ रहा है।

उम्मीदों पर टिका विश्वास : विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल जो स्थिति है उससे निपटा जा सकता है। यदि कोरोना वायरस के प्रभावितों की संख्या में कमी आती है और चीन की फैक्ट्रियां फिर से शुरू होती हैं तो इसका असर पहली तिमाही में चीनी अर्थव्यवस्था पर अस्थायी असर डालेगा और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था पर छोटा सा प्रभाव छोड़ेगा।

महामारी का खतरा : बीमारियां प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में ज्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। विश्व बैंक के एक शोध के अनुसार, गंभीर महामारी वैश्विक जीडीपी के लगभग 5 फीसद या 3 लाख करोड़ डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान

कर सकती है। विश्व बैंक ने 2013 में महामारी पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि गंभीर महामारी अपने अचानक और व्यापक प्रभाव में एक विश्व युद्ध जैसी होती है। ऐसा करने से उपभोक्ता वस्तुओं और ऊर्जा की मांग सीमित हो जाती है। कंपनियों और सरकारों द्वारा दुकानों और निष्क्रिय कारखानों को बंद करने के निर्णय से उत्पादन रुक जाता है।

ऐसे लड़ना होगा : चीनी सरकार कोरोना के सामने आने के बाद आर्थिक गिरावट को रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ी है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने इस सप्ताह महत्वपूर्ण ब्याज दर में कटौती की है। साथ ही भारी मात्रा में नकदी को बाजारों में उतारा है। नए टैक्स और सब्सिडी की भी घोषणा की है। अर्थशास्त्रियों की उम्मीद है कि सरकार आगामी दिनों में अतिरिक्त उपायों की घोषणा करेगी। यदि वायरस फैलता रहता है, तो वे मानते हैं कि बीजिंग को अपने ऋण को नियंत्रण में लाने और अर्थव्यवस्था में सीधे पैसा डालने के लिए लंबे समय से चल रहे प्रयासों को छोड़ना होगा।

मजबूत स्थिति में है इकोनॉमी : सीतारमण निर्देश

टोस वजह के बगैर लोन देने से मना करने वाले बैंक की एमएसएमई करें शिकायत

आठ परसेंट की ग्रोथ रेट जल्द हासिल करने की वित्त मंत्री ने जताई उम्मीद



शनिवार को कारोबारियों को संबोधित करती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। एएनआइ

चेन्नई, एएनआइ : सुस्ती की बहस के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमी को वर्तमान स्थिति को लेकर संतोष जताया है। 'जन-जन का बजट' नाम से आयोजित कार्यक्रम में कारोबारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय देश की इकोनॉमी अच्छी स्थिति में है, खासकर वृहत अर्थव्यवस्था के संकेतक अपने सुनहरे दौर में हैं। वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) से कहा कि अगर कोई बैंक उन्हें बेवजह लोन देने से आनाकानी कर रहा है या टोस कारण नहीं बता रहा, तो वे वित्त मंत्रालय में इसकी शिकायत कर सकते हैं।

वित्त मंत्री का कहना था कि बुनियादी कारक बेहतर हैं और विदेशी मुद्रा भंडार के साथ-साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अपने शीर्ष स्तर पर है। इस

दौरान वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि बैंक अधिकारियों से संवाद बढ़ाने की योजना तैयार की जा रही है। सीतारमण ने बताया कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी एमएसएमई सेक्टर के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लोन मिलने में व्यवधान की बात पर वित्त मंत्री ने कहा कि मंत्रालय जल्द ही इसके लिए विशेष सेंटर बनाने का रहा है। विशेष सेंटर को ई-मेल के जरिये शिकायत भेजी जा सकेगी। शिकायत की एक प्रति बैंक को भी भेजी होगी।

सीतारमण ने कहा कि सरकार इकोनॉमी

जीएसटी में खामियों को दूर कर रही सरकार

चेन्नई, आइएनएस : जीएसटी में खामियों के चलते सरकार को बड़ा राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा करदाताओं को भी मुश्किलों से दो-चार होना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जीएसटी में लगातार सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। मौजूदा समय में इसमें सुधार के लिए तकनीकी साधनों का सहारा लिया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आठ परसेंट की ग्रोथ रेट हासिल करने के लिए सरकार जीएसटी में सुधार कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए तकनीकी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले कई महीनों से एक लाख करोड़

रुपये से अधिक का जीएसटी कलेक्शन किया जा रहा है। इसमें सुधार के बाद कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1,04,000 करोड़ रुपये, दिसंबर में 1,03,000 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। इस वर्ष जनवरी में यह और बढ़कर 1,11,000 करोड़ रुपये रहा। जीएसटी कलेक्शन में इजाफा सुधार की ओर एक अच्छा संकेत है। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय के मुताबिक जीएसटी में सुधार के लिए सरकार डाटा एनालिटिक्स, आउटर विभाग से जानकारी जुटाने, आयात-निर्यात की जानकारी रखने जैसे उपाय अपना रही है।

को गति देने का हर्ससंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि देश की इकोनॉमी जल्द ही आठ परसेंट की विकास दर हासिल कर लेगी। गौरतलब है कि वर्ष 2019

ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत संकट भरा रहा है। इस दौरान इसकी ग्रोथ रेट 2.9 परसेंट आंकी गई, जो वर्ष 2009 की मंदी के बाद सबसे कम है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा का तिमाही मुनाफा 73 परसेंट गिरा, इस वर्ष से बड़ी आस

नई दिल्ली, प्रे: अग्रणी ऑटो निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के तिमाही मुनाफे में भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी ने शनिवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान उसका शुद्ध मुनाफा 73 परसेंट गिरकर 380 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी को 1,396 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। हालांकि कंपनी ने कहा कि अच्छे मानसून और खरीफ की फसल में उत्पादन अधिक होने के चलते वाहन उद्योग में सुधार की उम्मीद है।

समीक्षाधीन अवधि में कंपनी का कुल राजस्व 12,120 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 12,893 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी के मुताबिक इसकी बिक्री में कमी के चलते मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई है। समीक्षाधीन अवधि में कंपनी ने 1,23,353 वाहन बेचे, जबकि पिछले वर्ष 1,33,508 वाहन बेचे थे। साथ तरह वाहन की बिक्री में आठ परसेंट की गिरावट देखी गई। इस

बिक्री में कमी को बताया मुनाफे में गिरावट की वजह

आने वाले महीनों में ग्रामीण बाजारों में बिक्री बढ़ने की बड़ी उम्मीद



प्रतीकात्मक

दौरान कंपनी के टैक्सी की बिक्री में भी छह परसेंट की गिरावट आई।

कंपनी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक समीक्षाधीन अवधि में चाहनों और टैक्सटर्स के निर्यात में भी गिरावट देखने को मिली। इस अवधि में कंपनी का निर्यात 22 परसेंट गिरकर 9,633 यूनिट्स रहा। पिछले वित्त

महिंद्रा का कार्यकाल बढ़ा

मुंबई, आइएनएस : अग्रणी ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने एक्जीक्यूटिव चेयरमैन आनंद महिंद्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया है। इस फैसले के बाद वे नवंबर, 2021 तक अपने पद पर बने रहेंगे। इससे पहले कंपनी ने बताया था कि वे इसी वर्ष अप्रैल में एक्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद छोड़ देंगे। कंपनी ने यह फैसला सेबी के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें एक्जीक्यूटिव चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पदों को अलग करने की समय-सीमा अप्रैल, 2022 तक बढ़ाने की बात कही गई थी। इससे पहले सेबी ने कहा था कि कोई एक व्यक्ति कंपनी के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन और एमडी के पद पर एक साथ नहीं रह सकता है।

वर्ष की इसी अवधि में कंपनी ने 12,363 यूनिट्स निर्यात की थीं।

नए टैक्स नियमों से बचत की आदत पर दिख सकता है विपरीत असर

आम बजट से हफ्तों या महीनों पहले से यह माना जा रहा था कि पर्सनल इनकम टैक्स कम किया जाएगा। कॉरपोरेट इनकम टैक्स रेट में पहले ही कटौती की जा चुकी थी ऐसे में पर्सनल इनकम टैक्स में भी कटौती की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि सीधे टैक्स कम करने के बजाय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर्सनल इनकम टैक्स का एक समानांतर सिस्टम पेश कर देंगी।

इससे पहले अगस्त में कॉरपोरेट टैक्स के मामले में भी यही किया गया था। यानी कॉरपोरेट के पास विकल्प है कि अगर वे सारी टैक्स छूट छोड़ दें तो वे घटे रेट पर टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इसी तरह से अब व्यक्तिगत करदाताओं के पास विकल्प है कि अगर वे टैक्स छूट का फायदा न लें तो वे घटे हुए रेट पर इनकम टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति टैक्स छूट का कितना फायदा उठाता है उसके आधार पर उसके लिए टैक्स कम हो सकता है और कम नहीं भी हो सकता है। टैक्सपेयर्स को एक विकल्प

दिया गया है और हर एक टैक्सपेयर को फैसला लेना है कि उसे इस विकल्प का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं।

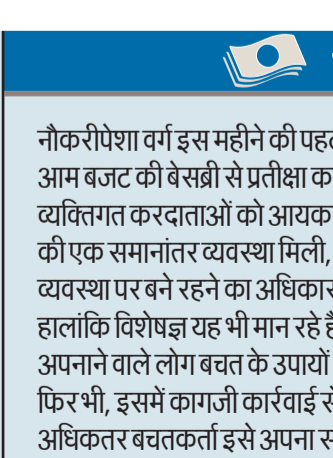
मोटे तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि जो लोग 10 से 12 लाख रुपये तक या 15 लाख रुपए तक कमा रहे हैं वे कम टैक्स रेट वाला नया सिस्टम चुनना चाहेंगे क्योंकि उनको कम टैक्स देना होगा। इसके अलावा उनके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना भी सरल होगा। वहीं 25-30 लाख रुपये या इससे अधिक कमाने वालों के लिए कोई खास फायदा या नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितनी तरह की टैक्स छूट उपलब्ध है उसका फायदा हर कोई उठा सकेगा। हालांकि कई तरह के उदाहरण से अब आकर्षक केलकुलेशन किया जा रहा है कि टैक्सपेयर्स सभी तरह की टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन कम इनकम वालों के लिए यह व्यावहारिक नहीं है।

मैं खास तौर पर इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि क्या इस वैकल्पिक टैक्स सिस्टम को अपनाने के बाद लोग बचत



धीरेंद्र कुमार, सीईओ वैद्यूरिसर्व

के प्रति उदासीन होंगे? क्योंकि लोगों को ज्यादातर ऐसे टैक्स छूट के विकल्पों को छोड़ना होगा जो सेक्शन 80 सी के तहत आते हैं। जैसे पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, पेंशन सिस्टम और इंग्ल्यासएस फंड। इन विकल्पों में बड़े पैमाने पर लोग निवेश करते हैं क्योंकि यहाँ इनको टैक्स बचाने



नौकरीपेशा वर्ग इस महीने की पहली तारीख को पेश किए गए आम बजट की बेसरी से प्रतीक्षा कर रहा था। बजट पेश हुआ और व्यक्तिगत करदाताओं को आयकर में सीधी छूट के बदले टैक्स की एक समानांतर व्यवस्था मिली, जिसमें शामिल होने या पुरानी व्यवस्था पर बने रहने का अधिकार करदाताओं को ही दिया गया है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मान रहे हैं कि आयकर की नई व्यवस्था अपनाने वाले लोग बचत के उपायों के प्रति उदासीन हो सकते हैं। फिर भी, इसमें कागजी कार्रवाई से इस हद तक मुक्ति दी गई है कि अधिकतर बचतकर्ता इसे अपना सकते हैं।

इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, भले ही सेक्शन 80-सी के तहत आने वाले विकल्पों को यह छूट न मिले। निश्चित तौर पर यह एक लाभ है और इसे बजट पारित होने से पहले ठीक किया जाना चाहिए। बचतकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा बदलाव डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी डीडीटी हटाना है। ऐसा होने की उम्मीद थी थी और टैक्स सिस्टम को साफ सुथरा बनाने या म्यूचुअल फंड की ओर से दिया जाने वाला डिविडेंड निवेशकों के पास पूरा पहुंचेगा। और इसके बाद इस पर निवेश के इनकम टैक्स स्लेब के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। रिटायर हो चुके व्यक्ति जैसे निवेशक जो कम टैक्स स्लेब में आते हैं, उन्हें कम टैक्स चुकाना होगा। बॉण्ड से नया म्यूचुअल फंड बनाने का स्वाद सरकार को लग चुका है और अब यह सरकार की आदत बन चुकी है। पीएसयू बॉण्ड इंटीएफ की सफलता के बाद वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकारी बॉण्ड से नया फंड बनाया जाएगा। रिटेल

इन्वेस्टर को सरकारी बॉण्ड सीधे बेचने का यह एक तंत्र है। भारत में यह प्रचलन एकदम नया है। डेट फंड में क्रेडिट से जुड़ी दिक्कतों की वजह से जिस तरह से डेट फंड निवेशकों को मुश्किल का सामना करना पड़ा है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि निवेशक इस प्रोडक्ट को हाथों हाथ लेंगे। लेकिन क्या लंबी अवधि में ये नए प्रोडक्ट प्राइवेट कंपनियों के डेट बॉण्ड से लोगों की दिलचस्पी खत्म कर पाएंगे यह देखने की बात होगी। फिलहाल के लिए तो निश्चित तौर पर निवेश के लिए यह अच्छा उत्पाद है। अगर पर्सनल फाइनेंस अब बचत के लिहाज से कुल मिलाकर देखा जाए तो यह दिलचस्प प्रोडक्ट है और पर्सनल इनकम टैक्स में सुधार के लिए रचनात्मक तरीका खोजा गया है। अब आपके पास एक सरल टैक्स स्ट्रक्चर कम टैक्स रेट और कुछ टैक्स छूट होगी। लेकिन यह सब आपके पास एक विकल्प के तौर पर होगा। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल करें या न करें।

...तो पैंगोलिन से फैला कोरोना वायरस

कोरोना वायरस चीन के बाद लगभग पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेने को आतुर है। इंसानी जान का दुश्मन कोरोना अब तक सात सौ लोगों की जान लील चुका है और तीस हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। चीनी शोधकर्ताओं ने कोरोना के लिए पैंगोलिन को जिम्मेदार ठहराया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, कोरोना से पीड़ित मरीज और पैंगोलिन में मौजूद इस वायरस का आनुवांशिक अनुक्रम 99 फीसद समान है। हालांकि अभी तक यह शोध प्रकाशित नहीं हुआ है।



न्यूज गेलरी

‘दुश्मन की चुनौती से निपटने में ईरान पूरी तरह सक्षम’

तेहरान: ईरान अपने दुश्मनों की चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त ताकतवर है। अमेरिका की ओर से दबाव और प्रतिबंध झेल रही देश की वायुसेना भी पर्याप्त ताकतवर है। यह बात ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कही है। वायुसेना कमांडरों को संबोधित करते हुए खामेनेई ने कहा, हम युद्ध छेड़ने के लिए मजबूत नहीं हैं बल्कि दुश्मनों की चुनौतियों का खाल्ना करने के लिए मजबूत बने हैं। हम किसी को भी धमकाना नहीं चाहते। लेकिन किसी की धमकियों को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है। इराक की राजधानी बगदाद में ईरान के शीर्ष कमांडर सुलेमानी को अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने के बाद से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। (एफपी)

हाफिज के खिलाफ पाक की कोर्ट ने टाला फैसला

लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ आतंकी फंडिंग के दो मामलों में अपने फैसले को टाल दिया है। सईद ने अर्जी देकर फैसले को टालने की गुहार लगाई थी। लाहौर की आतंकी रोधी अदालत (एटीसी) के जज अरशद हुसैन भट्ट ने जमात-उद-दावा के प्रमुख सईद के खिलाफ दोनों मामलों में गत हफ्ते अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत के एक अधिकारी ने बताया, ‘एटीसी के जज ने शनिवार को हाफिज सईद की अर्जी को स्वीकार कर लिया। इसमें आतंकी फंडिंग के सभी मामलों को एक करने और सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाए जाने का आग्रह किया है।’ अधिकारी के अनुसार, अभियोजक ने सईद की अर्जी का विरोध किया और कहा कि दो मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत कानून के तहत फैसला सुना सकती है। इसके बाद अदालत ने मंगलवार तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी और सईद की अर्जी पर बहस के लिए अभियोजक और बचाव पक्ष के वकीलों को नोटिस जारी कर दिया। (प्रेट्र)

कजाखस्तान में जातीय संघर्ष, आठ की मौत, 40 घायल

मस्को: दक्षिण कजाखस्तान में शुक्रवार को जातीय गुटों में हुए संघर्ष में जहां आठ लोगों की मौत हो गई, वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए। संघर्ष के दौरान उपद्रवियों ने आम लोगों की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। राष्ट्रपति कासिम जोमार्टो तोकेव ने किर्गिस्तान की सीमा के निकट हुई हिंसा के मामले में शनिवार को आपातकालीन सत्र बुलाया। साथ ही मामले की जांच के लिए आयोग का गठन भी कर दिया है। गृह मंत्री येरलान तुर्मुशेव ने राजधानी नूर-सुल्तान में कहा कि आठ लोगों की मौत हुई है और 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं। माना जाता है कि यह संघर्ष कजाख और अल्पसंख्यक दुंगन्स के बीच हुआ है। दुंगन्स मुस्लिम हैं और इनकी रिहायश किर्गिस्तान, कजाखस्तान और पूर्वोत्तर चीन में है। उप प्रधानमंत्री बर्दिबेक सपरबयव अस्पताल में भर्ती लोगों से मिले और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। (एफपी)

चिंताजनक

हैकिंग ग्रुप अवरमाइन ने दिया अंजाम, गूगल, फेसबुक और ट्विटर के सीईओ का अकाउंट भी कर चुके हैं हैक

सैन फ्रांसिस्को, एजेंसियां: दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट फेसबुक के ट्विटर, इंस्टाग्राम और मैसेंजर अकाउंट को हैक किए जाने की खबर है। इसे हैकिंग ग्रुप ‘अवरमाइन’ ने अंजाम दिया है। हालांकि अब सभी अकाउंट को री-स्टोर कर लिया गया है। बता दें कि अवरमाइन ग्रुप इससे पहले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी का अकाउंट हैक कर चुका है।

हैकर्स ने थर्ड पार्टी प्लेफार्म के जरिये इंस्टाग्राम पर फेसबुक के अकाउंट को हैक किया और हैकर्स के ग्रुप की एक तस्वीर पोस्ट की। अवरमाइन ने फेसबुक के ट्विटर अकाउंट को हैक करके पोस्ट किया, ‘हाय, हम लोग अवरमाइन हैं। अच्छा, फेसबुक को भी हैक किया जा सकता है, लेकिन इसकी सिक्वोरिटी कम-से-कम ट्विटर से अच्छी है। माइक्रो ब्लागिंग साइट ट्विटर के प्रवक्ता ने हैक होने की पुष्टि की है। एक ई-मेल बयान में उन्होंने बताया, ‘अकाउंट को एक थर्ड पार्टी

11 दिसंबर 2019 को एटीसी में हाफिज सईद और दूसरे आरोपितों के खिलाफ आतंकी फंडिंग के मामले में आरोप तय किए गए थे। पाकिस्तान के आतंकी रोधी विभाग ने सईद और उसके सहयोगियों के खिलाफ कई शहरों में 23 एफआइआर दर्ज की थी।

चीनी चिकित्सा पद्धति में होता है इसका प्रयोग

पैंगोलिन स्तनधारी प्राणी है, जिसके शरीर पर शल्क (स्केल) जैसी संरचना होती है। इसी के जरिए यह अन्य प्राणियों से खुद की रक्षा कर पाता है। फिलहाल ऐसे शल्क दुनिया में सिर्फ इसी के पास होते हैं। चीटी और दीमक खाने के कारण इसे चीटीखोर भी कहा जाता है। यह संरक्षित जानवर है। दुनिया में सर्वाधिक तस्करि इसी जीव की होती है। इसी कारण यह गंभीर संकट में है। इसका उपयोग पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति में किया जाता है। इसके कुछ हिस्सों का उपयोग त्वचा और गट्टिया के साथ कई अन्य रोगों में किया जाता है। चीन में पैंगोलिन बेचने वालों को 10 या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है।



चमगादड़ और मनुष्य के बीच की कड़ी

चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप की जांच में जुटे शोधकर्ताओं का कहना है कि लुमप्राय पैंगोलिन चमगादड़ों और मनुष्यों के बीच की गायब कड़ी हो सकते हैं। चमगादड़ों को इस बीमारी का नवीनतम वाहक माना गया है। आनुवांशिक विश्लेषण के मुताबिक, मनुष्यों में फैला वायरस 96 फीसद चमगादड़ों के समान था। फ्रांस के पाश्चर इंस्टीट्यूट के अरनोड फाटेटे के अनुसार, यह बीमारी चमगादड़ों से सीधे मनुष्य तक नहीं पहुंचती है बल्कि हमें लगता है कि कोई अन्य जानवर इसका मध्यस्थ है।

चीन में कोरोना से पहली बार दो विदेशियों की मौत

महामारी ▶ मरने वालों में एक अमेरिकी महिला और एक जापानी पुरुष

चीन में मौत का आंकड़ा 700 के पार, अब तक लगभग 35,000 संक्रमित

बीजिंग, एजेंसियां: महामारी का रूप लेते जा रहे कोरोना वायरस से चीन के वुहान शहर में पहली बार दो विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। इनमें अमेरिका की एक महिला और जापान का एक पुरुष शामिल हैं। इनको मिलाकर शनिवार तक चीन में मरने वालों की संख्या 723 हो गई है, जबकि 34,598 लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं। यह आंकड़ा 2002-03 में सास नामक बीमारी से हुई 774 लोगों की मौत के करीब पहुंचते जा रहा है। चीन ने कहा है कि फिलहाल हुबेई में दवा समेत मेडिकल सामग्रियों की सप्लाई में सुधार हुआ है, लेकिन हालात जल्द काबू में नहीं हुए तो सप्लाई गड़बड़ा सकती है।

अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने शनिवार को अपने नागरिक की मौत की पुष्टि की है। प्रवक्ता ने कहा कि 60 साल की अमेरिकी महिला की छह फरवरी को वुहान के एक अस्पताल में मौत हो गई। वुहान में अधिकारियों ने कोरोना वायरस से किसी विदेशी नागरिक की मौत का यह पहला मामला बताया है। हालांकि, वुहान के अस्पताल में जापान के 60 साल के एक नागरिक की भी मौत हुई है। उसे निमोनिया की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, बाद में कोरोना के लक्षण भी उसमें पाए गए थे। जापान के विदेश मंत्रालय ने टोक्यो में इसकी घोषणा की। मंत्रालय ने कहा कि बीमारी की पहचान में मुश्किल के चलते जापानी व्यक्ति की मौत का कारण वायरल निमोनिया बताया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

पाक में हिंदुओं का अपमान करने वाले पोस्टर के लिए नेता निलंबित

लाहौर, प्रेट्र: सत्ताधारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी ने अपने लाहौर चैप्टर के महासचिव को निलंबित कर दिया है। पार्टी ने पोस्टर पर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना साधने वाले नारे का तीव्र विरोध होने के बाद यह कदम उठाया। शनिवार को मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

मियां अकरम उस्मान ने कश्मीर एकजूटता दिवस के सिलसिले में पोस्टर लगाया था। पूरे देश में पांच फरवरी को कश्मीर एकजूटता दिवस मनाया गया था। पोस्टर पर ‘हिंदू बात से नहीं लात से मानता है’ नारा लिखा था। सोशल मीडिया पर इस नारे को लेकर उस्मान की आलोचना होने के बाद पार्टी ने पोस्टर के लिए माफी मांगी। ये पोस्टर लाहौर में सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए थे।

निलंबित करने के बाद उस्मान को भेजे गए कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया गया है कि पोस्टर पर लिखे गए शब्द पार्टी की नीतियों का उल्लंघन करते हैं। पार्टी के लाहौर अध्यक्ष जूहेर अब्बास खोखर ने यह नोटिस जारी किया। विशेष समिति अब इस



चीन के वुहान शहर में एक अस्पताल में कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित मरीज को आइसोलेशन वॉर्ड में लेकर जाते चिकित्सक। यहां संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है। एपी

चीन से आने वालों को अलग रख रहा हांगकांग

हांगकांग ने चीन से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से दो हफ्ते के लिए कोरंट्राइन यानी अलग-अलग कमरों में वुहान के एक अस्पताल में मौत हो गई। वुहान में अधिकारियों ने कोरोना वायरस से किसी विदेशी नागरिक की मौत का यह पहला मामला बताया है। हालांकि, वुहान के अस्पताल में जापान के 60 साल के एक नागरिक की भी मौत हुई है। उसे निमोनिया की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, बाद में कोरोना के लक्षण भी उसमें पाए गए थे। जापान के विदेश मंत्रालय ने टोक्यो में इसकी घोषणा की। मंत्रालय ने कहा कि बीमारी की पहचान में मुश्किल के चलते जापानी व्यक्ति की मौत का कारण वायरल निमोनिया बताया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेयसस ने कहा है कि संगठन के विशेषज्ञों का एक दल जल्द ही चीन जाएगा। उन्होंने कहा कि दल के मुखिया के सोमवार या मंगलवार तक हुबेई पहुंच जाने की उम्मीद है, बाकी सदस्य उसके बाद जाएंगे। उन्होंने इस मिशन में अमेरिका के मेडिकल दल के शामिल होने की भी उम्मीद जताई। डब्ल्यूएचओ कोरोना वायरस को जल्द ही कोई नया नाम देने

का मायवाबी मिलने के साथ ही राशन पानी की कमी से भी नहीं जुझना पड़ेगा। शनिवार को अनिवार्य कोरंट्राइन का असर भी दिखा। शुक्रवार को जहां चीन से हांगकांग 96 हजार से ज्यादा लोग आए थे, वहीं शनिवार को यह संख्या मात्र नौ हजार रह गई। प्रशासन पूरी तरह सतर्कता बरत रहा है।

चमगादड़ और मनुष्य के बीच की कड़ी

चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप की जांच में जुटे शोधकर्ताओं का कहना है कि लुमप्राय पैंगोलिन चमगादड़ों और मनुष्यों के बीच की गायब कड़ी हो सकते हैं। चमगादड़ों को इस बीमारी का नवीनतम वाहक माना गया है। आनुवांशिक विश्लेषण के मुताबिक, मनुष्यों में फैला वायरस 96 फीसद चमगादड़ों के समान था। फ्रांस के पाश्चर इंस्टीट्यूट के अरनोड फाटेटे के अनुसार, यह बीमारी चमगादड़ों से सीधे मनुष्य तक नहीं पहुंचती है बल्कि हमें लगता है कि कोई अन्य जानवर इसका मध्यस्थ है।

पीटीआइ नेता मियां अकरम उस्मान। फाइल

मामले की जांच करेगी। उस्मान ने कहा, मोदी की जगह हिंदू छाप दिया: उस्मान ने भड़काऊ पोस्टर के लिए प्रिंटर को दोषी ठहराया। उसने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना चाहते थे। गलती से मोदी की जगह प्रिंटर ने हिंदू छाप दिया। उन्होंने ट्वीट किया, ‘मैं सोमा के दोनों तरफ रहने वाले शांतिप्रिय की नीतियों का उल्लंघन करते हैं। पार्टी के लाहौर अध्यक्ष जूहेर अब्बास खोखर ने यह नोटिस जारी किया। विशेष समिति अब इस

फेसबुक के ट्विटर, इंस्टाग्राम और मैसेंजर अकाउंट हैक



अवरमाइन दुबई का हैकिंग ग्रुप है।

प्रतीकात्मक

प्लेटफार्म में हैक कर लिया था। कंपनी ने थर्ड पार्टी प्लेटफार्म का नाम तो नहीं बताया है, लेकिन सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल ‘कोरोस’ (केएचओआरओएस) द्वारा किए गए ट्वीट के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। कोरोस डिजिटल मार्केटिंग और पीआर विभागों द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट का प्रबंधन करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक वेब सेवा है। इतना

ही नहीं यह सोशल मीडिया अकाउंट को थर्ड पार्टी एप से जोड़ता है। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा कि जैसे ही हमें अकाउंट हैक होने के बारे में बताया गया, हमने उसे लॉक कर दिया। फेसबुक ने भी शुक्रवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने की पुष्टि की। फेसबुक के प्रवक्ता जो ओसबोर्न ने कहा, ‘हमारे कुछ

कॉर्पोरेट सोशल अकाउंट को थोड़े समय के लिए हैक कर लिया गया था, लेकिन बाद में इस दिक्कत को ठीक कर लिया गया।’ अवरमाइन ग्रुप साल 2016 से एक्टिव है। कहा जाता है कि इस ग्रुप में दुबई के कुछ किशोर हैं। फेसबुक अकाउंट को ठीक उसी तरह हैक किया गया है, जिस तरह पिछले महीने नेशनल फुटबाल लीग का अकाउंट हैक किया गया था।

संक्रमण के लिए पैंगोलिन जिम्मेदार

गुआंगझू स्थित दक्षिण चीन कृषि विश्वविद्यालय का कहना है कि उसके दो शोधकर्ताओं, शेन योंगी और जिआो लिहुआ, ने पैंगोलिन को जानवरों और मनुष्यों से लिए गए कोरोना वायरस की आनुवांशिक तुलना के आधार पर एनसीओवी-2019 के संभावित स्रोत के रूप में पहचाना है। पता चला है कि यह संक्रमण फैलाने और अन्य जीवों के लिए जिम्मेदार है। यह अनुक्रम 99 फीसद समान है।

जल्द प्रकाशित होगा शोध

चीनी शहर वुहान में दिसंबर में कोरोना वायरस का प्रकोप उभरा था। माना जा रहा था कि सीफूड और जंगली जानवरों के बाजार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। यहीं पर संक्रमित होने वाले कई लोग काम करते थे। हालांकि पैंगोलिन बाजार में बेची जाने वाली चीजों में सूचीबद्ध नहीं था लेकिन इसकी अंधेध बिक्री की जाती रही है। पिछले महीने, बीजिंग में वैज्ञानिकों ने दावा किया कि सांप कोरोना वायरस का स्रोत थे, लेकिन उस सिद्धांत को अन्य शोधकर्ताओं ने खारिज कर दिया। उधर, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष लियु वार्होनिंग ने बताया कि कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के प्रयासों में मदद के लिए शोध के परिणाम जल्द ही प्रकाशित किए जाएंगे।

शोध से मिलेगी मदद

शोध में आनुवंशिक अनुक्रम की समानता पर और बातें सामने आ सकती हैं। कनाडा के हैमिल्टन में मैकमास्टर विश्वविद्यालय के कोरोना वायरस शोधकर्ता अरिंज बनर्जी का कहना है कि पैंगोलिन के रक्त नमूने से यह पता चल सकता है कि यह मनुष्यों तक कैसे पहुंचा और भविष्य में इसके प्रसारण को कैसे रोका जा सकता है।



पाक कोर्ट ने नाबालिग ईसाई लड़की के साथ शादी को वैध ठहराया

कराची, प्रेट्र: पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों का अपहरण करके उनका धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने के मामले अक्सर सुनने को मिलते हैं। ताजा मामला एक 14 साल की ईसाई लड़की का है, जिसकी शादी को अदालत ने शर्ह कानून के मुताबिक वैध ठहराया है। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि चूंकि लड़की का मासिक धर्म शुरू हो चुका है, इसलिए इस्लामी कानून के हिसाब से शादी जायज है। अब लड़की के माता-पिता इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।

लड़की के पिता यूनिंस और मां नगीना मसीह के मुताबिक, 14 साल की हुमा का पिछले साल अक्टूबर में सिंध से अपहरण कर लिया गया था। बाद में अपहरणकर्ता अब्दुल जब्बार ने धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह कर लिया। इसके खिलाफ लड़की के माता-पिता ने सिंध के हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि वे अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। उसे देखना चाहते हैं। जस्टिस मुहम्मद इकबाल कलरोही और न्यायाधीश इश्राफ अली की पीठ ने तीन फरवरी को दिए अपने आदेश में कहा कि यह ठीक है कि लड़की नाबालिग है, लेकिन उसका मासिक धर्म शुरू हो चुका है। ऐसे में इस्लामी कानून के मुताबिक अपहरणकर्ता अब्दुल जब्बार के साथ उसकी शादी पूरी तरह वैध है। कोर्ट ने लड़की की उम्र की पुष्टि के लिए पुलिस को जांच का भी आदेश दिया है। लड़की के परिजनों की वकील तबस्सुम युसूफ ने कहा कि जांच अधिकारियों ने अपहरणकर्ता का पक्ष लिया है। वह सुप्रीम कोर्ट से न्याय की मांग करेंगी। उन्होंने कहा कि फैसला सिंध बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2014 के अनुकूल नहीं है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी को वैध नहीं माना जा सकता है।

160 देशों में प्रतिबंधित हथियारों को अब अपनाने लगा है अमेरिका

वाशिंगटन: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वादे के साथ सत्ता में आए थे कि वह अंतहीन युद्धों को खत्म कर देंगे, लेकिन उनका प्रशासन अब उन हथियारों को अपना रहा है, जिन्हें दुनिया के 160 से ज्यादा देश प्रतिबंधित कर चुके हैं।

क्लस्टर बम और एंटी-पर्सनल लैंड माइंस जैसे घातक हथियार भविष्य में इस्तेमाल के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ये हथियार अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की भावी युद्ध योजनाओं का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। हालांकि अभी ऐसा कोई ठोस आँचलिय नहीं बताया गया है कि क्यों जल्द इस्तेमाल किया जाएगा? अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पेर हथियार संबंधी इस तरह की नई नीतियों का समर्थन करते हैं। इस बदलाव पर उस समय से गौर किया जा सकता है,

तैयार किए जा रहे क्लस्टर बम और एंटी-पर्सनल लैंड माइंस जैसे घातक हथियार

अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की भावी युद्ध योजनाओं का बनते जा रहे हैं अहम हिस्सा

1997 में हुई थी ओटावा संधि

एंटी-पर्सनल लैंड माइंस पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1997 में ओटावा संधि हुई थी। उस समय इस पर 120 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। अब 164 देश इस संधि का हिस्सा हैं। इस संधि को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों ने नहीं अपनाया है।

जब वर्ष 2017 में जिम मैटिस रक्षा मंत्री थे। उस समय आए एक सैन्य रणनीति मसौदे में रूस और चीन को अमेरिका का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बताया गया था। इन

दोनों के पास उल्लेखनीय थल सेना है और युद्ध के मैदान में दुश्मन सेनाओं को रोकने के लिए बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल किया था। पेंटागन के प्रवक्ता जोनाथन हॉफमैन ने गत सोमवार को पत्रकारों से कहा कि विभिन्न रक्षा शाखाओं के साथ व्यापक चर्चा के परिणामस्वरूप नीति में बदलाव किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह बताने से इन्कार कर दिया कि किसके कहने पर नीति बदली जा रही है।

रक्षा विभाग के पूर्व अधिकारियों ने बताया कि रूस के हमले और यूक्रेन से क्रीमिया को अलग करने की घटना के विश्लेषण के दौरान प्रशासन में लैंड माइंस और दूसरे उन हथियारों पर बहस छिड़ी थी, जिनको मना किया जा चुका था। नवंबर, 2017 में मैटिस ने 2008 के एक मेमो को रद कर दिया था। इस मेमो में लगभग सभी क्लस्टर हथियारों के उपयोग पर रोक लगाने और इनके जखीरे को नष्ट करने का आदेश दिया गया था।

ट्रंप ने महाभियोग में गवाही देने वाले दो अफसरों को हटाया

वाशिंगटन, प्रेट्र: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महाभियोग प्रक्रिया के दौरान अपने खिलाफ गवाही देने वाले दो अफसरों को हटा दिया है। दोनों ने अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की समिति के समक्ष महाभियोग मामले में ट्रंप के खिलाफ गवाही दी थी। बता दें कि तीन दिन पहले ही अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने ट्रंप को महाभियोग के सभी आरोपों से बरी कर दिया था।

अधिकारियों की इस हिमाकत से चिढ़े ट्रंप ने राहत पाते ही यूरोपीय संघ में अमेरिका के राजदूत गोर्डन सोडलैंड और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) में यूक्रेन मामलों के विशेषज्ञ लेफिंटेंट कर्नल एलेक्जेंडर विंडमैन को बर्खास्त कर दिया। विंडमैन और सोडलैंड डेमोक्रेट्स के बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा में महाभियोग की जांच के दौरान मुख्य गवाह थे। इससे पहले सोडलैंड ने कहा था, ‘राष्ट्रपति ट्रंप यूरोपीय

यूरोपीय संघ में अमेरिका के राजदूत गोर्डन सोडलैंड और एनएससी के सदस्य विंडमैन को बर्खास्त किया

संघ में बतौर अमेरिकी राजदूत मुझे तत्काल वापस बुलाना चाहते हैं।’ वहीं विंडमैन ने वकील ने कहा कि लेफिंटेंट कर्नल को सच बोलने के लिए पद से हटाया गया है। बता दें कि विंडमैन को हटाए जाने से कुछ देर पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ‘मैं चाहता हूँ कि विंडमैन चले जाएं। अगर कोई यह सोचता है कि मैं उनसे खुश हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।’

ह्विट हाउस ने महाभियोग मामले से जुड़े इन दो अधिकारियों की बर्खास्तगी को अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। ह्विट हाउस ने विंडमैन के जुड़वा भाई लेफिंटेंट कर्नल येवगेनी विंडमैन को भी पद से हटा दिया है। दोनों ह्विट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का हिस्सा थे।

रविवार विशेष

टेक ज्ञान से ब्रेक डांस और कॉमेडी तक, सोशल मीडिया के सुपर स्टार करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं। मैंगी सप्ताह जारी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की प्रभावशाली युवाओं की 30 अंडर-30 में लिस्ट में यूट्यूबर गौरव चौधरी और वाइन स्टार भुवन बाम भी शामिल हैं। वहीं, 18 साल का टिक टोअर युवराज सिंह बॉलीवुड में छा गया है और अभिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन जैसे दिग्गज उसके प्रशंसक बन चुके हैं। इन युवाओं ने केवल केवल अपनी रचनात्मकता और कुछ कर दिखाने के जज्बे के बूते जहां बेशुमार शोहरत कमाई है, वहीं दौलत के मामले में भी वह झंडे गाड़ रहे हैं। कमाई की बात करें तो यह प्रतिमाह 20 लाख रुपये तक है। जोधपुर, बीकानेर से **मनीष गोधा** की रिपोर्ट।

मचा रहे धूम, कमाई भी बूम-बूम

सोशल मीडिया के सुपर स्टार: टेक ज्ञान से ब्रेक डांस और कॉमेडी तक, करोड़ों दिलों पर कर रहे राज

टैक्निकल गुरुजी: गौरव चौधरी

अजमेर में जन्मे और बीकानेर में पढ़े-लिखे 28 साल के गौरव चौधरी बीते कुछ साल से यूट्यूब पर टैक्निकल गुरुजी नाम से चैनल चला रहे हैं। इसमें वह नए मोबाइल और गैजेट्स के बारे में ज्ञान देते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि शुद्ध हिंदी में। 1.5 करोड़ सब्सक्रिप्शन वाला उनका यह चैनल एक बड़ा हिंदी यूट्यूब चैनल है। बीकानेर से बीटेक और बिट्स पिलानी, दुबई कैम्पस से माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के एमई करने के बाद गौरव ने दुबई पुलिस के सीसीटीवी डिपार्टमेंट में बतौर सिक्युरिटी सिस्टम इंजीनियर काम कर रहे गौरव बताते हैं, टेक्नोलॉजी के प्रति मेरा रुझान बचपन से ही था। मुझे पता था कि भारत में, वह भी हिंदी पढ़ी में, मोबाइल और रोजमर्रा के गैजेट्स या उपयोगी टेक्नोलॉजी को लेकर उत्सुकता है और आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी में उन्हें कोई एक्सपर्ट से सल्लाह मिले। मैंने



अभिनेत्री नोरा फतेही के साथ गौरव। यही किया। गौरव के यूट्यूब चैनल के करीब 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि उनके वीडियो व्यूज का आंकड़ा 1.5 अरब व्यूज का है। अपने यूट्यूब चैनल से अब तक 1.5 मिलियन डॉलर से अधिक से ही था। मुझे पता था कि भारत में, वह भी हिंदी पढ़ी में, मोबाइल और रोजमर्रा के गैजेट्स या उपयोगी टेक्नोलॉजी को लेकर उत्सुकता है और आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी में उन्हें कोई एक्सपर्ट से सल्लाह मिले। मैंने

बाबा जैक्सन: युवराज सिंह

इन दिनों इंडियन माइकल जैक्सन की चहुंओर चर्चा है। जोधपुर का 18 साल का युवराज सिंह टिकटॉक स्टार बन चुका है। उसके डांस वीडियोज ने मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ जैसी का दिल जीता, जो अब उसकी फैन लिस्ट में शामिल हैं। बाबा जैक्सन नाम से टिकटॉक चैनल चलाने वाला यह रजस्थानी लड़का सोशल मीडिया का सुपर स्टार बन गया है। अब प्रसिद्ध कोरियोग्राफर रेमा डिस्जुजा ने आधासन दिया है कि वे भी उसे अपनी अगली फिल्म में अवसर देंगे। युवराज ने कहा, मुझे तो केवल माइकल जैक्सन को कॉपी करने का शौक था। दोस्तों ने वीडियो बनाए और जब ये सोशल मीडिया पर लिट होने लगे तो मैंने टिकटॉक पर वीडियो डालना शुरू कर दिया। युवराज के इस टिकटॉक चैनल के करीब 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले युवराज के पिता जोधपुर में टाइल्स लगाने का काम करते हैं। दो बहनों समेत तीन बच्चों



स्ट्रीट डांसर फिल्म की टीम के साथ युवराज (मध्य)। के इस परिवार का गुजारा भी मुश्किल से चलता है। जोधपुर के पावटा क्षेत्र में रहने वाले युवराज फिलहाल मुंबई में है। दिल्ली के एक प्रोफेशनल डांस ग्रुप के साथ भी जुड़ गए हैं। युवराज को फेमस होता देखकर मां और बहन बेहद खुश हैं। बहन ने बताया कि डांस का अभ्यास करते वक्त शोशा की बहुत जरूरत पड़ती है ताकि स्टेप्स देख सकें, लेकिन हमारे यहां इतना बड़ा शोशा नहीं था। तब युवराज मकान की छत पर कड़ी धूप में अभ्यास करता था ताकि अपनी पछाई को देख वह स्टैप्स सुधार सके।



प्रियंका चोपड़ा के साथ भुवन बाम। • सौ. यूट्यूब, टिकटॉक (समी फोटो) **बीबी की वाइन्स: भुवन बाम** बीबी यानी भुवन बाम। और बीबी की वाइन्स उनका यूट्यूब चैनल। दिल्ली निवासी 26 वर्षीय यह यूट्यूबर सोशल मीडिया का कॉमेडी किंग है। बड़ौदा, गुजरात में जन्में भुवन ने दिल्ली के ग्रीन फोल्ड्स स्कूल और शहीद भगत सिंह कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद करियर की शुरुआत एक संगीतकार के रूप में रेस्तरां में की। बाद में कुछ गाने भी कंपोज किए। लेकिन नाम मिला इंटरनेट पर। उन्होंने पहला कॉमेडी वीडियो एक न्यूज रिपोर्टर पर बनाया था। 2015 में यूट्यूब चैनल शुरू किया। इन वीडियोज में भुवन शहरी किशोरों के जीवन को हंसीमजाक के साथ दर्शाते हैं। खुद एक्टिंग करते हैं। उनके चैनल के वर्तमान में 1.62 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। कमाई की बात करें तो यह औसत 25 लाख रुपये प्रतिमाह तक है। भुवन भी महंगी कारों के शौकीन हैं।

वाह उस्ताद नहीं, वाह बोड़ाम बोलिये जनाब

खासियत ▶ जाकिर हुसैन को भी पसंद है झारखंड के बोड़ाम में बनने वाला तबला

पूर्वी सिंहभूम के बोड़ाम प्रखंड के आंधारझोर में 200 वर्षों से बन रहे पारंपरिक वाद्ययंत्र



बोड़ाम ब्लाक के आंधारझोर गांव में तबले की गुणवत्ता परखते मेघनाथ रूहीदास (सबसे बाएं), साथ में हैं उनके सहयोगी।

बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ओडिशा से लेकर दिल्ली और पंजाब तक के लोग आते हैं। तबला बनाने के माहिर मेघनाथ रूहीदास बताते हैं कि उस्ताद जाकिर हुसैन से लेकर बड़े-बड़े तबलावादकों को यहां का तबला

पसंद है। यहां से तबला मंगाने के लिए ये उस्ताद एक-डेढ़ माह पहले फोन पर ऑर्डर देते हैं, जिसे उनके शिष्य आकर ले जाते हैं। रूहीदास बताते हैं कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि इतने प्रसिद्ध लोग हमारे यहां के

तबले के मुरीद हैं। पॉपुलर किशन महाराज भी यहां से तबला मंगवाते थे।

पुरुष-महिला मिलकर बनाते हैं साज : आंधारझोर में वाद्ययंत्र बनाने का सिलसिला करीब 200 वर्ष से चल रहा है। इस कुटीर उद्योग को शीर्ष पर पहुंचाने में यहां पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी अहम भूमिका निभाती रही हैं। पुरुष वाद्य यंत्रों के लिए लकड़ी काटने-तराशने और चमड़ा साफ करने व चढ़ाने-कसने का काम करते हैं, जबकि महिलाएं छोल, नगाड़े, तबले, तारा और अन्य गाजे-बाजे को सुंदर पेंटिंग के जरिए आकर्षक बनाती हैं। मधुर सुरों के साथ जुगलबंदी कर लोगों के दिलों के तार झूंकते करने वाले साज की आवाज में बोड़ाम के लोगों की कारीगरी भी घुली रहती है। सुर-संगीत को ऊंचाई देने के यंत्र बनाने का हुनर यहां सबके पास है। यही कारण है कि गांव का लगभग हर आदमी वाद्ययंत्र बनाने में माहिर है।

नीम-बबूल के तबले होते हैं उम्दा : मेघनाथ बताते हैं कि कुछ वाद्ययंत्रों का निर्माण लकड़ी से होता है, जबकि कुछ मिट्टी और लोहे से भी बनाए जाते हैं। वाद्ययंत्रों के निर्माण में शीशम, आम, कटहल, नीम आदि

इलेक्ट्रॉनिक वाद्ययंत्रों ने तोड़ी कमर

एक समय था जब तबला, ढोलक, नाल की इतनी मांग होती थी कि बोड़ाम के कारीगरों को सोने-खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी, अब ऐसा नहीं है। 10-15 साल में इलेक्ट्रॉनिक वाद्ययंत्रों के बाजार ने इस उद्योग की कमर तोड़ दी है। उनके परिवार के बच्चे और युवा भी पढ़-लिखकर दूसरे रोजगार में जा रहे हैं। गांव में लगभग 100 परिवार हैं, जो पहले इसी से आजीविका चलाते थे। अब तो उन्हें तबला बेचने के लिए हर रविवार को जमशेदपुर में अस्थायी दुकान सजाना पड़ता है। बावजूद नाम कायम है और तबले के शौकीन कई लोग इनके उत्पाद खरीदने को पहुंचते हैं।

की लकड़ी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। वैसे नीम और बबूल से बने तबले उम्दा होते हैं। जाकिर हुसैन व किशन महाराज समेत कई तबला वादक इसी की मांग करते हैं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/positive-news

मिलिए 90 साल के 'युवा' से, समझ जाएंगे फलसफा

जीना इसी का नाम है

हिमांशु मिश्र, बरेली

सिखा रहे जीने की कला...

इस बुजुर्ग के स्वामिभान और संघर्ष के कायल हैं रुहेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र

कैम्पस में बेचते हैं गुड़-चना, छात्रों से कहते हैं- उम्र के साल मत गिनो, लक्ष्य गिनो



बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय में चना-गुड़ बेचने पहुंचे 90 वर्षीय द्वारिका प्रसाद।

रुहेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र इस बुजुर्ग के स्वामिभान और संघर्ष के कायल हैं। दिसेंबर, जनवरी की भीषण ठंड में पारा चाहे कितना भी गिर जाए, उनका स्वामिभान सर्वोच्च पर रहता है। वह झोले में नमकीन, गुड़, चना लेकर निकल पड़ते हैं। दिनभर में जो कमाते हैं, उससे परिवार चलाने में मदद करते हैं। छात्रों से कहते हैं, उम्र के साल मत गिनो, लक्ष्य गिनो...।

कलेंडर भले ही कहता रहे कि द्वारिका प्रसाद की उम्र 90 साल है मगर, जच्चा हर रोज उन्हें मेहनतकश युवा साबित करता है। मई-जून की तपती दोपहर उनके कदम नहीं रुक पाते। मौसम कोई भी हो, ताप अधिक हो या कम, उनका स्वामिभान सदा सर्वोच्च पर स्थिर रहता है। छात्र उनके इसी जीवट के कायल हैं। परिवार में बेटे, बहु, पोता-पोती सब हैं। फिर भी आप चना, गुड़ बेचने क्यों आते हैं? अब बुजुर्ग हो गए हैं, आराम करिए... ये शब्द उनसे कई लोगों ने कहे। हर बार जवाब आता है- वे सब मेहनत कर अपनी जिंदगी अच्छे से बसर कर रहे हैं। मैं उन पर आश्रित क्यों रहूं। उम्र की परेशानियां कुछ नहीं। जो हिम्मत हार जाए, वो जिंदगी क्या...।

उम्र की गिनती तुम भी मत करना...

आपकी उम्र क्या है... सवाल का जवाब छात्रों को उन्हीं की तरह समझाते हैं। कहते हैं... ज्यादा नंबर अच्छी बात होती है या कम। जब कॉलेज की परीक्षा में ज्यादा नंबर आपको सफल कर सकते हैं तो जिंदगी में कम नंबर (कम उम्र) वाला ही सफल व संघर्षशील क्यों हो। जिसकी उम्र के नंबर ज्यादा हो, वो ज्यादा संघर्षशील भी तो हो सकता है। फिर मुस्कुराकर कहते हैं... तुम भी उम्र के साल मत गिनो, लक्ष्य गिनो।

के लिए मामला कोर्ट में चल रहा है। तारीख होती है तो वहां भी जाता हूँ। रहता है। वह बताते हैं कि उनकी लगीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है। पढ़े-लिखे नहीं इसलिए कुछ लोगों ने गुमराह कर लिया। जमीन पर कब्जा वापस लेने

अनजान रिश्तों से बांधी भावनाओं की डोर...

संडे बॉक्स जरा हटके...

विनीत मिश्र, मथुरा

लावारिस शवों को खुद मुखाग्नि देती हैं डॉ. लक्ष्मी गौतम

निराश्रित महिलाओं के लिए बेटी बन करती हैं सेवा, निभाती हैं सभी दायित्व



वृंदावन में लावारिश शव का अंतिम संस्कार करती डॉ. लक्ष्मी गौतम।

जब बेटे के साथ किया अंतिम संस्कार

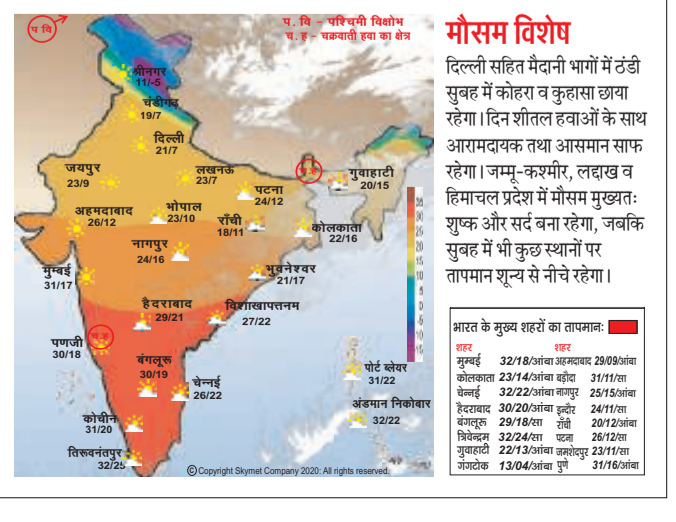
डॉ. गौतम के पति विजय कुमार बैंक में सहायक प्रबंधक पद से रिटायर्ड हैं। बड़ा बेटा अवन एनपीसीआइएल में साइटोफिक आफसर है, बेटी अवनिका झारखंड में कोर्ट सब रजिस्ट्रार है। सबसे छोटा बेटा शुभम मर्चेन्ट नेवी में कैप्टन है। दो साल पहले का वाक्या सुनाते हुए लक्ष्मी गौतम ने बताया कि छुट्टी पर शुभम घर आया था। वृंदावन में सड़क पर शव पाड़ होने की खबर मिली। शुभम को लेकर पहुंची। शव को इमशान घाट ले गई। शाम होने को थी, स्कूटी की हेडलाइट में मुखानि दी।

दिया- जिन महिलाओं का कोई नहीं, उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है? पता चला कि मौत के बाद शव बोरे में भरकर संबंधित विभाग की कार्रवाई के इंतजार में इधर-उधर छोड़ दिए जाते हैं। सर्वे रिपोर्ट तो भेज दी मगर, निराश्रितों का पारिवारिक सदस्य बनने की भी ठान ली। रिपोर्ट पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आश्रय सदन में मृत्यु होने पर वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए थे। 2012 में उन्होंने कनकधारा फाउंडेशन बनाया। अब तक कितने अनजानों का अंतिम संस्कार किया? लक्ष्मी कहती हैं कि कभी गिनती

नहीं की, औसतन हर साल ये संख्या 20 से 25 रहती ही है। लक्ष्मी कहती हैं कि एक अंतिम संस्कार में चार से साढ़े चार हजार रुपये का खर्च आता है। यह खर्च खुद वहन करती हैं। दुनिया में जो आया है, सबको मोक्ष मिले, बस यही जीवन का उद्देश्य है। फाउंडेशन आश्रय सदन में राशन का इंतजाम करता है। निराश्रितों का इलाज भी करता है। आश्रयसदन में किसी भी महिला की मौत होती है, तो उसका अंतिम संस्कार करने के बाद 13 दिन बाद शुद्धीकरण कार्यक्रम भी करती हैं।

786 वाले 99 हजार नोट एकत्रित कर बनाया वर्ल्ड रिकार्ड

संगद सूत्र, उदयपुर : करेंसीमैन के नाम से मशहूर उदयपुर के विनय भाणवात ने सात सौ छियासी अंक वाले 99 हजार नोटों का संग्रह कर वर्ल्ड रिकार्ड बनाया है। उनका नाम इंटरनेशनल जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड फ़ाउंडेशन लॉन्ग में दर्ज किया गया है। इंटरनेशनल जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स के मुख्य समन्वयक व अध्यक्ष डॉ. माइक ने लंदन स्थित कार्यालय से प्रमाण पत्र, स्मृति चिह्न व स्वर्ण पदक जारी कर बधाई दी। इंटरनेशनल जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स की भारत के हैदराबाद स्थित शाखा के मुख्य समन्वयक विंगी नरेंद्र गौड़ ने यह जानकारी दी।



साप्ताहिक राशिफल

रविवार 9 फरवरी, 2020 से शनिवार 15 फरवरी, 2020 तक

मेष (चू, वे, चो, ला, ती, लू, ले, लो, आ) व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में सफलता, धन आगमन में प्रगति, नए स्थान में व्यापार का योग, पारिवारिक सुख शांति, भौतिक साधनों की वृद्धि, संतान के प्रति कार्य योजना, शिक्षा में एकाग्रता, चयन में सफलता, वाद-विवाद से बचें, अधिकारी से अनबन, शुभ अंक-4

वृष (इ, ऊ, ए, ओ, पा, पी, वी, वू, वै, वी) धन आगम में प्रयास करें, धन के आगमन में सावधानी रखें, पारिवारिक जीवन में मन खिन्न, शत्रु परास्त, दांपत्य में प्रसन्नता, जीवन साथी से मिलन, वाहन सावधानी से चलाएं, निर्माण की रुरुपरेखा, आय में प्रगति, अपयश, राज्य पक्ष से जांच योग, शुभ अंक-5

मिथुन (का, की, कू, घ, छ, के, को, हा) नए स्थान पर व्यापार का योग, सावधानी से कार्य करें, पारिवारिक जीवन में चिंता की समाप्ति, साधनों की वृद्धि, संतान के कार्य में प्रगति, शिक्षा में एकाग्रता बनाएं, व्यर्थ के कार्यों से बचें, जीवन साथी का सहयोग, यात्रा से लाभ, सलाह से कार्य करें, लोकप्रियता में वृद्धि, शुभ अंक-7

कर्क (ही, हु, हे, हो, झ, डू, डे, डो) व्यापार, उद्योग, नौकरी के क्षेत्रों में अवरोध, धन से कार्य करें, नए क्षेत्र में सावधानी से कार्य करें, पारिवारिक जीवन में सुख शांति, साधन की वृद्धि, संतान से अनबन, शिक्षा में रुचि की कमी, व्यर्थ के कार्यों से बचें, यात्रा से बचें, राज्य पक्ष से सावधान, शुभ अंक-6

सिंह (मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टै) आत्मविश्वास की वृद्धि, कार्य करने वालों से सहयोग, पारिवारिक जीवन में सुधार, वाहन का योग, संतान के कार्य के प्रति योजना, चयन में देरी, आलस्य से बचें, दांपत्य में अनबन, यात्रा से लाभ, अधिकारी जन सावधानी से कार्य करें, व्यय पर नियंत्रण करें, शुभ अंक-8

कन्या (टो, पा, पी, पु, ष, उ, पे, पो) अर्थ साधन अच्छा, आत्मविश्वास की कमी, सहयोगी जनो से सावधान, पारिवारिक जीवन शांतिमय, साधनों की वृद्धि, संतान से अनबन, शिक्षा में रुचि, वाद-विवाद से बचें, दांपत्य में सुधार, खान-पान में सावधानी रखें, संपत्ति से हानि, सावधानी से कार्य करें, शुभ अंक-9

तुला (रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, तै) नौकरी, उद्योग व्यापार के कार्य में प्रगति, धन आगम में प्रगति, पारिवारिक जीवन में साधन वृद्धि, वाहन योग, संतान की सफलता, तकनीकी विषय में रुचि, चयन में देरी, सलाह से किए गए कार्य में सफलता, जीवन साथी का मिलन, व्यय अधिक, अधिकारी से सहयोग, शुभ अंक-10

वशिक (तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू) व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में श्रम से सफलता, धन आगम अच्छा, साहस की वृद्धि, अच्छे समाचार की प्राप्ति, पारिवारिक जीवन में अवरोध, संतान के कार्य में सहयोग, शिक्षा में रुचि, तलाक में विकाार, दांपत्य में सुख, वाहन सावधानी से चलाएं, ग्रहों की प्रतिकूलता, शुभ अंक-11

धनु (ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, दा, भे) धन आगम में सुधार, आत्मविश्वास की कमी, सहयोगी जनो से सावधान, पारिवारिक जीवन अच्छा, संतान के कार्य में सहयोग, चयन में अवरोध, वाद दांपत्य में अनबन, यात्रा में सावधानी, राज्य पक्ष से सहयोग, आय में सुधार, व्यक्ति के कारण अपयश, शुभ अंक-12

मकर (भो, जा, ज, खी, खू, खे, खो, गा, गी) अर्थ साधन ठीक, आत्मविश्वास की वृद्धि, नए स्थान में व्यापार, पारिवारिक जीवन में साधन की वृद्धि, वाहन योग, संतान के मंगल कार्य, शिक्षा में रुचि, शत्रु प्रभावी, यात्रा में लाभ, नए यंत्र स्थापन का योग, आय में प्रगति, व्यय पर नियंत्रण करें, शुभ अंक-1

कुम्भ (गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सा, दा) प्रतिस्पर्धा का योग, धन आगम में सुधार, कार्य में सहयोग से सफलता, यात्रा आगम में साधन की वृद्धि, अनबन, भूमियोग, संतान के कार्य में सहयोग, शिक्षा में रुचि, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहे, दांपत्य में तनाव, यात्रा से लाभ, लोकप्रियता की वृद्धि, आय में सुधार, शुभ अंक-2

मीन (दी, दू, थ, झ, ङ, दे, दा, चो, ची) धन आगम में प्रगति, नए स्थान में व्यापार का योग, पारिवारिक सुख-शांति, शिक्षा में एकाग्रता, चयन में सफलता, दांपत्य में प्रसन्नता, यात्रा से लाभ, अधिकारी से अनबन, राज्य पक्ष से सावधान, आय में प्रगति, व्यय पर नियंत्रण करें, मन में भय का प्रभाव, शुभ अंक-3

